चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

फ़तवों से बेफ़िक्र मुस्लिम युवा

पेज 3

जाति, जनगणना और आरक्षण

पेज 5

चार धाम यात्रा अव्यवस्था का शिकार

पेज 7

साई की महिमा

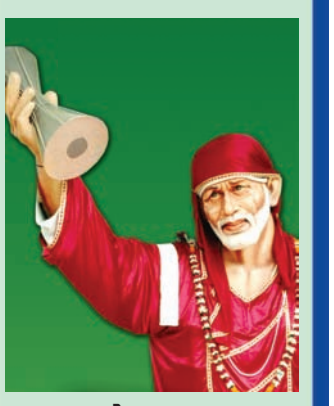

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 7 जून-13 जून 2010

प्रधानमंत्री जी, ये सफलता है या विफलता

फोटो–*सुनील मल्होत्रा*

मनीष कुमार

मनमोहन सिंह सरकार का एक साल पूरा हो गया. इस साल आज़ाद भारत में दो सबसे बड़े घोटाले हुए. आईपीएल घोटाले में केंद्रीय मंत्रियों, नेताओं, फ़िल्म स्टारों, अधिकारियों और अंडरवर्ल्ड के ख़तरनाक गठजोड़ का ख़ुलासा हुआ. 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 60 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान भी सरकार के खाते में आया. इसके अलावा महंगाई, सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल, माओवादियों का आतंक और भ्रष्टाचार के नए-नए रूप देखने को मिले. किसानों की सब्सिडी के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मंदी के नाम पर कॉरपोरेट के लिए सरकारी ख़ज़ाना खोल दिया गया और आम आदमी को समस्याओं से ख़ुद निपटने के लिए बेसहारा छोड़ दिया गया. प्रधानमंत्री देश के सबसे ईमानदार नेताओं में से हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. पिछले एक साल में उनकी ईमानदारी की परछाई सरकार के कामकाज पर नहीं पड़ती दिखाई दे रही है.

भारत में सरकारें तो पांच साल के लिए ही चुनी जाती हैं. पहला साल किसी भी सरकार का लक्ष्य और दिशा तय करता है, लेकिन इस सरकार की विवेचना करना थोड़ा अलग है. डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में देश को एक सपना दिखाया था, वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने भारत की आर्थिक नीति पूरी तरह से बदल दी. आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का रास्ता साफ़ कर उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि 2010 तक देश में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, सारी सड़कें पक्की हो जाएंगी, बिजली की समस्या ख़त्म हो जाएगी, किसान खुशहाल हो जाएंगे, मज़दूरों की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और देश विकसित देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा. बीस साल बीत गए. मनमोहन सिंह वित्तमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन ग़रीब पहले ज़्यादा ग़रीब और अमीर पहले से कई गुना ज़्यादा अमीर बन गए. गांव और शहर में इतना फासला पैदा हो गया है कि नेताओं के झूठे वादों से भी भरोसा उठ गया. विकास की रोशनी चंद महानगरों में सिमट कर रह गई और बाकी देश अंधेरे के दलदल में फंसकर सिसक रहा है. मनमोहन सिंह सरकार की विवेचना इसी परिप्रेक्ष्य में करने की ज़रूरत है. यह कहना भी ज़रूरी है कि यूपीए-2 सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने विधिवत एक प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें वह एक विजनरी की जगह राजनीतिज्ञ ज़्यादा नज़र आए.

मनमोहन सिंह ने पिछले एक साल में उन्हीं नीतियों को अपनाया, जिस नीति की उन्होंने 1991 में शुरुआत की थी. मनमोहन सिंह ने पूरे साल भर देश की जनता को नव उदारवाद की आग में झोंक दिया. पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने बहुत पहले ही आज के हालात से संसद को रूबरू कराया था. मनमोहन सिंह के बजट से वह इतने व्यथित हुए कि उन्होंने लोकसभा में यह चेतावनी दी थी कि उदारवाद की आर्थिक नीति देश को एनार्की की ओर ले जाएगी. आज चंद्रशेखर जी की बातें सही साबित हो रही हैं. देश के दो सौ से ज़्यादा जिले ऐसे हैं, जहां सरकार की मौजूदगी नहीं है या फिर नाममात्र है. स्वर्गीय चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने, तब मनमोहन सिंह उनके आर्थिक सलाहकार थे. जब नरसिम्हाराव की सरकार बनी तो वी वित्तमंत्री बने. वित्तमंत्री बनते ही मनमोहन सिंह ने पूरी पलटी मार दी और उदारवाद के मसीहा बन गए. वित्तमंत्री बनने से पहले मनमोहन सिंह के विचार अलग थे. उन्होंने देश के विकास में सरकार की भूमिका को ख़त्म करने का जो सिलसिला शुरू किया, वही नीति आज देश में चल रही है. नव उदारवाद का असर हमारे देश पर ऐसा हुआ है कि 80 फ़ीसदी लोग विकास की धारा से अलग हो चुके हैं. सरकार की नीतियों का फ़ायदा इन 80 फीसदी तक नहीं पहुंच पा रहा है.

पिछले साल जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो दुनिया मंदी की चपेट में थी. भारत भी इसकी मार से बच नहीं पाया, क्योंकि 1991 की नीति की वजह से भारत उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुका था. देश की विकास दर पर बुरा असर हुआ, निर्यात भी प्रभावित हुआ और लाखों लोग बेरोज़गार हो गए. यूपीए की सरकार पिछले एक साल में आम आदमी से ज़्यादा ख़ास लोगों के साथ नज़र आई. सरकार ने अमीरों के कर में ज़्यादा छूट देने की रणनीति पर काम किया. 2009-2010 के दौरान 502299 करोड़ रुपये की छूट दी गई. इसमें से 79554 करोड़ रुपये की छूट कॉरपोरेट सेक्टर को दी गई और 40929 करोड़ रुपये की छूट इनकम टैक्स देने वालों को मिली. इन आंकड़ों से साफ़ है कि सरकार ने मंदी के नाम पर देश के कॉरपोरेट सेक्टर और अमीरों को भारी फ़ायदा पहुंचाया. पिछले एक साल में भारत ने महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. आम आदमी ने महंगाई की ऐसी मार कभी नहीं झेली थी. खाने-पीने के सामानों के दाम आसमान छूने लगे. 2009 में महंगाई की दर 20 फीसदी तक पहुंच गई, जो अभी भी लगभग 17 फीसदी है. इस रिकॉर्ड तोड़ महंगाई की वजह यह है कि सरकार ने कृषि को अनदेखा कर दिया. पिछले साल भीषण सूखे की वजह से किसानों ने दोहरी मार झेली. बाकी कसर सरकार ने कृषि क्षेत्र का सरकारी ख़र्च कम करके पूरा कर दिया. किसानों की मदद करने के बजाय सरकार ने फूड सब्सिडी में 400 करोड़ और खाद सब्सिडी में 3000 करोड़ रुपये की कमी कर दी. यह कैसी विचारधारा है कि अमीरों और कॉरपोरेट सेक्टर की मदद के लिए सरकार अपनी तिज़ोरी खोल देती है, लेकिन ग़रीब किसानों की मदद के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है. इस नीति का क्या मतलब निकाला जाए. क्या यह मान लिया जाए कि सरकार पूरी तरह उद्योगपतियों, कॉरपोरेट सेक्टर और अमीरों के हाथों की कठपुतली बन गई है.

पिछले एक साल में सरकार ने जो भी नीतियां बनाईं, उनका सीधा फ़ायदा देश के अमीरों और शक्तिशाली परिवारों को हुआ. सरकार देश की ग़रीब जनता को भूल गई, उसने आम आदमी को महंगाई, बेरोज़गारी और ग़रीबी से जूझने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है. ग़रीब किसानों, जंगलों में रहने वाली जनजातियों, मज़दूरों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विकास या उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले एक साल में सरकार ने न तो कोई पहल की और न ही कोई क़ानून बनाया.

अजीबोग़रीब बात यह है कि सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर और अमीरों को जो छूट दी, उसकी भरपाई वह आम जनता की जेबें काट कर पूरा कर रही है. सरकार ने अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिया. सरकार ने पेट्रोल और डीजल सहित कई सारी चीजों पर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी. बाज़ार में सामान पहले से ज़्यादा महंगा हो गया और जिसका सीधा असर देश की ग़रीब जनता झेल रही है. डॉ. मनमोहन सिंह अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान तो हैं, लेकिन जिस तरह की नीति अपनाई जा रही है, उससे कोई यह कैसे मान ले कि सरकार महंगाई से निपटने के लिए कोई कारगर कदम उठाएगी. यूपीए-2 को अब लेफ्ट पार्टी के समर्थन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए सरकार बेफ़िक्र होकर अब पब्लिक सेक्टर यूनिट को बेचने की तैयारी कर रही है. सरकार की योजना से यही लगता है कि कॉरपोरेट और अमीरों को टैक्स में जो छूट दी गई है, उसकी भरपाई वह सरकारी कंपनियों को बेच कर पूरा करने वाली है. सरकार की योजना है कि इन कंपनियों को बेच कर 40 हज़ार करोड़ रुपये का नुक़सान पूरा किया जाए. यह कहा जा सकता है कि पिछले एक साल में सरकार ने जो भी नीतियां बनाईं, उनका सीधा फ़ायदा देश के अमीरों और शक्तिशाली परिवारों को हुआ. सरकार देश की ग़रीब जनता को भूल गई, उसने आम आदमी को महंगाई, बेरोज़गारी और ग़रीबी से जूझने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है.

हैरानी की बात यह है कि ग़रीब किसानों, जंगलों में रहने वाली जनजातियों, मज़दूरों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के विकास या उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले एक साल में सरकार ने न तो कोई पहल की और न ही कोई क़ानून बनाया. सरकार विकास के आंकड़े दिखा कर अपनी पीठ ठोंक रही है कि सूखे और मंदी के बावजूद भारत की विकास दर 7 फ़ीसदी से ज़्यादा है. यह एक अच्छा संकेत तो है, लेकिन यह विकास दर किसी सरकार की वजह से नहीं, बल्कि देश के लोगों की मेहनत का नतीजा है. अगर देश मंदी के दौर में भी विकास कर रहा है तो इसके लिए सरकार नहीं, देश की जनता को शाबाशी मिलनी चाहिए. सवाल यह है कि इस विकास के लिए सरकार ने क्या किया. कोई यह नहीं बता सकता है कि सरकार ने ऐसी कौन सी एक भी नीति अपनाई है, जिसकी वजह से भारत का विकास हो रहा है.

न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल भी सरकार की इस मनोस्थिति को दर्शाता है, जहां सरकार ने जनता से ज़्यादा मुनाफ़े को प्राथमिकता दी. सरकार इस बिल को संसद में लेकर आ भी गई, लेकिन विरोध इतना ज़बर्दस्त हुआ कि उसके क़दम पीछे हट गए. यह बिल भारत-अमेरिका परमाणु संधि का हिस्सा था. इस बिल के ज़रिए यह तय होगा कि अगर कोई हादसा हो जाए तो अमेरिकी कंपनी और सरकार को कितने-कितने पैसे देने पड़ेंगे. सरकार ने कुल 450 मिलियन डालर की सीमा तय की, जो भोपाल गैस कांड में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय राशि से भी कम थी. अब यह भी समझना ज़रूरी है कि जब कोई न्यूक्लियर दुर्घटना होगी, वह भोपाल गैस कांड से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह होगी. गौर करने वाली बात यह है कि इस बिल के मुताबिक़ किसी हादसे के बाद अमेरिकी कंपनी को तीन सौ करोड़ रुपये देने थे. इस बिल के तहत 67 मिलियन डॉलर भारत सरकार को देने पड़ेंगे. सरकार द्वारा तय की गई राशि यूरोप और अमेरिका की राशि से काफी कम है. मतलब यह कि भारत के लोगों की जान अमेरिका और यूरोप में रहने वाले लोगों की जान से सस्ती है. इस बिल के ज़रिए यूपीए सरकार ने यही संदेश दिया कि उसे देश की जनता के हितों से अमेरिकी कंपनियों के हित ज़्यादा प्रिय हैं. सरकार को लगता है कि मार्केट मेकिनिज्म हर समस्या के निदान के लिए सक्षम है और इससे सब का भला होगा. ये बातें सिर्फ़ किताबों में पढ़ते समय अच्छी लगती हैं. हमारे देश की सच्चाई यह है कि निजीकरण और उदारीकरण के इस दौर ने पिछले एक साल में एक से बढ़कर एक दलालों को पैदा किया है. यूपीए सरकार की एक साल की कहानी घोटालों पटी हुई है.

पिछले एक साल में जितने घोटाले सामने आए, वह यूपीए की पिछली सरकार के पांच सालों में नहीं आए. आईपीएल की काली दुनिया का जब भंडाफोड़ हुआ तो उसके छींटों ने सरकार के कई मंत्रियों को दागदार कर दिया. यह बात आम हो गई है कि क्रिकेट की आड़ में उद्योगपतियों, नेताओं, फ़िल्म स्टारों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और अंडरवर्ल्ड का एक ख़तरनाक नेटवर्क देश में फल-फूल रहा है. आईपीएल मनी लाउंडरिंग, अंडरहैंड डीलिंग, भाई-भतीजावाद, हवाला और काले धन का केंद्र बन चुका है. यूपीए के महत्वपूर्ण मंत्री शशि थरूर का इस्तीफ़ा लेकर सरकार ने इस मामले की लीपापोती करने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन कई और मंत्री एवं नेता शक़ के घेरे में हैं. यह कैसी सरकार है, जिसकी नाक के नीचे उसके मंत्री और नेता पिछले तीन सालों से इतना बड़ा घोटाला करते रहे, लेकिन उसे इसका पता तक नहीं चला. कहने को तो जांच हो रही है, लेकिन जनता को पूरी तरह यह विश्वास हो चुका है कि विपक्ष के साथ मिलकर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जसवीर सिंह बीर ने अपने तबादले के बाद वक़्त से पहले ही रिटायरमेंट की मांग की.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

उठो, जागो, काम करो

केंद्रीय सूचना आयोग तमाम कठिनाइयों के बावजूद लगातार पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है. जन शिक़ायतों के निराकरण में हो रही देरी से चिंतित आयोग ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह जन शिक़ायतों के निराकरण के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए गाइड लाइन जारी करे. संयोग से इन बातों का संबंध न्यायपालिका की उन आपत्तियों से नहीं है, जिनकी वजह से मनमोहन सिंह सूचना क़ानून में संशोधन करना चाहते हैं. यह निर्देश सूचना आयुक्त शैलेष गांधी ने जारी किए हैं. आरटीआई कार्यकर्ता इस निर्देश को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, क्योंकि सरकार एक समय सीमा के तहत जवाब देने में असफल रही है. सूत्रों के मुताबिक़, कुछ राज्यों में गाइड लाइन बनाई तो गई है, लेकिन कभी उसका अनुपालन नहीं होता. शैलेष गांधी के पास जो मामला आया था, उसमें उन्हें पता चला कि प्रशासनिक सुधार और जन शिक़ायत विभाग ने जवाब देने के लिए एक ख़ास समय सीमा तय तो की थी, लेकिन उक्त लोक प्राधिकरण ने शायद ही कभी उस गाइड लाइन पर अमल किया हो. गांधी के इस निर्देश से उन बाबुओं को प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, जो गाइड लाइन का पालन नहीं करते.

निष्क्रिय एजेंसी

जाति आधारित जनगणना, जिसकी मांग कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी की थी, के बारे में गृहमंत्री पी चिदंबरम ने सुझाव दिया है कि यह काम पिछड़ा वर्ग के लिए बने राष्ट्रीय आयोग करे. हालांकि चिदंबरम ने जाति आधारित जनगणना की मांग का विरोध किया था. अब गृहमंत्री के बयान ने इस आयोग के लिए एक योग्य अध्यक्ष की खोज को तेज़ कर दिया है. वर्ष 2009 से यह आयोग, जब इसके अध्यक्ष जस्टिस आर एस पांडियन रिटायर हुए, बिना अध्यक्ष के ही चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एम एन राव का नाम आगे बढ़ाया है. इस प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी हरी झंडी मिलना बाक़ी है.

इस्तीफ़े से आई आफ़त

पंजाब के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का इस्तीफ़ा आजकल इस राज्य के नौकरशाहों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव जसवीर सिंह बीर ने अपने तबादले के बाद वक़्त से पहले ही रिटायरमेंट की मांग की. उनका तबादला इस बात के लिए किया गया था कि उन्होंने मुख्यमंत्री के परिवार की बात नहीं मानी थी. सूत्रों के मुताबिक़, बीर के इस्तीफ़े ने बादल को मुसीबत में डाल दिया है. पंजाब के आईएएस एसोसिएशन ने सरकार से बीर की भावनाओं पर ध्यान देने की मांग की है. वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने इस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को अपमानित करने की घटना की जांच एक तय समय सीमा के भीतर कराने की मांग की है. बीर का इस्तीफ़ा अब एक महत्वपूर्ण मुद्दे में तब्दील हो चुका है.

dilipcherian@chauthiduniya.com

प्रधानमंत्री जी, ये सफलता है या विफलता

पृष्ठ 1 का शेष

सरकार आईपीएल घोटाले के सभी गुनहगारों को बचा ले जाएगी.

यूपीए सरकार 2 जी स्पेक्ट्रम स्कैम पर बचाव की मुद्रा में है. अंडरहैंड डीलिंग की वजह से सरकारी ख़ज़ाने को क़रीब 60 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. मंत्री के ख़िलाफ़ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में मंत्री को क्लीन चिट भी दे दी. मनमोहन सिंह से इस स्कैम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारा काम नियम के तहत किया गया है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. डीएमके को साथ रखना यूपीए की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ज़िम्मेदारी और जवाबदेही के सवाल पर मनमोहन सिंह की सरकार घेरे में आ गई. घोटाले और षड्यंत्र की कहानी का एक और ख़ुलासा तब हुआ, जब यह पता चला कि सरकारी एजेंसियां कुछ मुख्यमंत्रियों, विपक्ष के नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के नेताओं की भी फोन टेपिंग कर रही हैं. जिन एजेंसियों पर आतंकवादियों और अंडरवर्ल्ड पर नज़र रखने की ज़िम्मेदारी है, वे राजनीतिक विरोधियों और जनता के नुमाइंदों पर नज़र रखने का काम कर रही हैं.

प्रधानमंत्री की छवि देश के सबसे ईमानदार नेता की है, लेकिन उनका ख़ुद ईमानदार होना पर्याप्त नहीं है. प्रधानमंत्री जी की ईमानदारी की परछाई सरकार और सरकारी तंत्र पर भी दिखनी ज़रूरी है. सरकारी तंत्र में भीषण भ्रष्टाचार है, यह सबको पता है. अफ़सोस इस बात का है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने नए-नए रूप ले लिए हैं. ज़मीनी हक़ीक़त यह है कि सरकारी तंत्र ने भ्रष्टाचार के अपने जाल में गांव के लोगों को भी हिस्सेदार बना लिया है. नरेगा हो, मिड डे मील हो या फिर सरकार का अन्य कोई प्रोजेक्ट, सब भ्रष्टाचार के नए केंद्र बन चुके हैं. गांवों में सरकारी पैसे की बंदरबांट हो रही है. सरकारी फाइलों में कार्यों का पूरा ब्यौरा भरा जा रहा है. मंत्री उन्हीं फाइलों को देखकर प्रेस कांफ्रेंस में ख़ुद की पीठ ठोक रहे हैं. विकास का सारा काम सिर्फ सरकारी फाइलों पर चल रहा है. एक साल में यूपीए सरकार के खाते में यह भी शामिल होना चाहिए कि देश के अधिकारियों ने फाइलों के ज़रिए विकास के पुल बांधने में महारत हासिल कर ली है. इससे तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भ्रष्टाचार की नदी सरकार के शीर्ष से बह रही है.

भ्रष्टाचार रोकने की ज़िम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसके लिए नैतिक अधिकार भी होने चाहिए. अगर शीर्ष मंत्रियों के नाम घोटाले और स्कैम में आते रहेंगे तो भ्रष्टाचार को रोकने की पहल कैसे हो सकती है. अगर संस्थागत भ्रष्टाचार को राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाई जा सकेगी. महंगाई को लेकर विपक्ष के तेवरों और कटमोशन पर सरकार बैकफुट पर आ गई. लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए मुलायम सिंह, लालू प्रसाद यादव और मायावती के साथ जिस तरह की डीलिंग हुई, उससे सरकार की छवि तो ख़राब हुई ही, साथ ही जनता का विश्वास भी टूट गया. इसका असर यह हुआ कि सोनिया गांधी के अनुरोध के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया.

यूपीए-2 सरकार देश में क्या करना चाहती है, यह शायद देश की जनता को सही ढंग से पता नहीं है. वजह यह है कि पिछली बार की तरह इस बार यूपीए का कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम नहीं है. सरकार की नीति क्या है, योजना क्या है और विज़न क्या है, यह हमारे सामने स्पष्ट नहीं है. सरकार बनने के बाद यही संदेश दिया गया कि यूपीए अपनी दूसरी पारी में उन कामों को करेगी, जो पिछली बार गठबंधन राजनीति की मजबूरियों की वजह से नहीं कर सकी.

यूपीए सरकार पूरी तरह बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनी रही. चाहे वह गैस और पेट्रोल की क़ीमतें हों, टेलीकाम स्पेक्ट्रम का आवंटन हो, खनन, वित्तीय सेक्टर, रिटेल सेक्टर या फिर विदेशी शिक्षा संस्थान हो. सरकार की हर नीति का फ़ायदा देश के बड़े उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों को पहुंचा. पिछले एक साल से नेताओं, उद्योगपतियों और दलालों के गठजोड़ जिस तरह से देश में फल-फूल रहे हैं, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया.

कॉरपोरेट और अमीरों के हितों का ख्याल रखने में सरकार का एक साल बीत गया, लेकिन अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर नज़र भी नहीं पड़ी. वजह भी साफ़ है कि पिछले साल कोई महत्वपूर्ण चुनाव नहीं थे. चौथी दुनिया अख़बार में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद सरकार ने खानापूर्ति के लिए संसद में उसे पेश तो कर दिया, लेकिन रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को लागू करने की कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही है. सरकार बहुमत में है. दूसरी सेकुलर पार्टियां भी कांग्रेस के साथ हैं. शायद सरकार इस मौके का फ़ायदा उठाना नहीं चाहती, वरना दंगा विरोधी कानून और ग़रीब एवं पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण लागू करने में क्या दिक्कत है, यह समझ के बाहर है. सरकार को पिछले एक साल में माओवादियों के ख़िलाफ़ लड़ाई में कोई सफलता नहीं मिली. जिन इलाक़ों में माओवादियों की पकड़ है, वहां की जनजातियों का विश्वास जीतने में भी वह विफल रही.

जब सरकार बनी थी, तब मनमोहन सिंह ने सौ दिनों के एजेंडे की घोषणा की थी. संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के ज़रिए सरकार ने यह वादा किया था कि सौ दिनों के अंदर महंगाई पर लगाम लगेगी, किसानों को राहत मिलेगी, मज़दूरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होगी और भ्रष्टाचार ख़त्म होगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला आरक्षण विधेयक पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया था. इसके साथ-साथ सरकार ने घोषणा की थी कि अगले 5 सालों में झुग्गी-झोपड़ी को ख़त्म कर दिया जाएगा और ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वालों को हर महीने 3 रुपये किलो की दर से 25 किलो अनाज दिया जाएगा. यूपीए सरकार ने रोज़ाना 20 किलोमीटर और हर साल 700 किलोमीटर सड़क बनाने का भी लक्ष्य रखा था. फ़िलहाल देश में हर रोज़ दो किलोमीटर से भी कम सड़क बन पा रही है. बिजली के क्षेत्र में 5653 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी फ़िलहाल अधूरा ही है. सौ दिन का वादा था, पूरा बरस बीत गया.

जब हम सरकार के एक साल के काम का हिसाब ले रहे हैं, तो यह भी ज़रूरी है कि हमें विपक्षी दलों का भी आकलन करना चाहिए. पिछले एक साल में विपक्ष ने क्या किया, यह जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रजातंत्र में सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी ज़िम्मेदारी होती है. एक साल पूरा होने पर विपक्ष तर्कहीन प्रतिक्रिया देता रहा. वामपंथी भी मनमोहन सिंह के एक साल की सही विवेचना करने में विफल रहे. आडवाणी जी, प्रकाश करात जी, मुलायम सिंह जी, लालू प्रसाद यादव जी क्या आप लोग इन बातों को जानते हैं? क्या आपको यह पता नहीं है कि यूपीए सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर और अमीरों को टैक्स में हज़ारों करोड़ रुपये की छूट दे दी और ग़रीब किसानों की सब्सिडी के पैसे कम कर दिए? अगर आपको पता है तो आप सब चुप क्यों बैठे हैं?

manish@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 13
दिल्ली, 7 जून–13 जून 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9810017924
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

लड़कियां खुल कर हम से बात कर रही थीं. अपना फोटो खिंचवाने में उन्हें कोई संकोच नहीं था. उनकी बातें कह रही थीं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं. अब हम अपनी मुस्तकबिल ख़ुद बनाएंगे.

फ़तवों से बेफ़िक्र मुस्लिम युवा

शशिशेखर

अंबर जफर एक युवा मुस्लिम महिला हैं. वह नोएडा के एक निजी स्कूल में फिजिकल ट्रेनिंग टीचर हैं. अंबर कहती हैं, वातानुकूलित दफ्तरों में बैठकर फ़तवे जारी करने वाले को चाहिए कि वे ज़रा आम लोगों के बीच जाएं, उनकी हालत देखें, उनकी वास्तविक समस्याओं को समझें और फिर फ़तवा जारी करने के बारे में सोचें. जी हां, यह प्रतिक्रिया उस युवा भारत की है, जो अब अपने साथ किसी भी तरह भेदभाव बर्दाश्त नहीं करना चाहता. यह प्रतिक्रिया उस फ़तवे के ख़िलाफ़ है, जिसके मुताबिक़ मुस्लिम महिलाएं किसी सरकारी या निजी दफ्तर में काम नहीं कर सकतीं. महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मी से बात नहीं कर सकतीं. यह प्रतिक्रिया उन मुफ्तियों के ख़िलाफ़ भी है, जो बिना सोचे-समझे और ज़मीनी हक़ीक़त को जाने बग़ैर बात-बात पर फ़तवे सुनाने से नहीं हिचकते. दरअसल, फ़तवे तभी दिए जाते है जब कोई मुफ्तियों से सवाल करता है. ऐसे में इनको ज़िम्मेदारी से दूसरे मुफ्तियों से मशवरा कर के ही फ़तवा देना चाहिए. पिछले कुछ महीनों के भीतर ही दारूल उलूम देवबंद की ओर से क़रीब दर्जन भर फ़तवे जारी किए गए. इनमें से ज़्यादातर फ़तवे मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए थे. मसलन, मुस्लिम लड़कियां सरकारी या ग़ैर सरकारी दफ्तरों में काम नहीं कर सकतीं, अपने पुरुष सहकर्मी से बातचीत नहीं कर सकतीं, जन्मदिन मनाना ग़ैर इस्लामिक है, बैंक या शराब कंपनी में काम करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है या कि बीमा करवाना हराम है. फ़तवे का इस्लाम में बहुत ज़्यादा महत्व है. इस्लाम में फतवे कुरान और हदीस की रोशनी में ही दिए जाते है. लेकिन सवाल उठता है कि आख़िर युवा मुस्लिमों (लड़के और लड़कियां दोनों) की राय में आजकल जारी होने वाले ऐसे फतवों की अहमियत कितनी है. मुस्लिम महिलाओं को कहीं बाहर से ख़तरा नहीं है. तलाक़ जैसा मसला अभी भी मुस्लिम महिलाओं के लिए एक दु:स्वप्न से कम नहीं है, जहां मात्र तीन बार तलाक़ बोलकर एक मर्द अपनी पत्नी से मुक्ति पा लेता है. क्या ऐसी हालत से गुज़रने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए धर्म के इन ठेकेदारों के पास कोई फ़तवा नहीं है? लेकिन मुस्लिम महिलाओं और परिवारों को आर्थिक तौर पर असुरक्षित बनाने के लिए इनके पास फ़तवों की कमी नहीं है. इनके फ़तवे के मुताबिक़, एक मुस्लिम परिवार भले ही मुफलिसी में अपनी पूरी ज़िंदगी गुज़ार दे, लेकिन अपनी बेटी की कमाई स्वीकार नहीं कर सकता. ऐसा करना हराम है. अब कोई इन लोगों को समझाए कि अगर किसी परिवार में बेटा हो ही न या फिर आवारा निकल जाए, तब बेटी अगर अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से परिवार का भरण-पोषण करती है तो इसमें ग़लत क्या है? या फिर वह परिवार अपनी बेटी की कमाई न ले और भूख से मर जाए. इस फ़तवे पर जामिया से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही शहला कहती हैं, जब मां-बाप बेटों की कमाई स्वीकार कर सकते हैं तो बेटी की क्यों नहीं. लड़की की कमाई स्वीकार करना बिल्कुल हराम नहीं है. जब इस्लाम में सब चीज़ों में बराबरी की बात है तो फिर इस मामले में असमानता क्यों? वहीं अंबर जफर कहती हैं, हमारे मां-बाप हम पर इतना ख़र्च करते हैं, महंगी शिक्षा दिलाते हैं तो अगर हम कमा रहे हैं तो हमारी भी यह ज़िम्मेवारी बनती है कि हम अपने परिवार को सपोर्ट करें. जबकि हुदा हसन की सोच इस मसले पर थोड़ी जुदा है. वह कहती हैं कि परिवार को अगर ज़रूरत हो, तभी लड़की की कमाई स्वीकार करनी चाहिए, वैसे घर का ख़र्च पुरुष की कमाई से ही चले तो अच्छा है. लेकिन ताहिरा इस मसले पर हुदा की बातों से सहमत नहीं हैं. जामिया की छात्र ताहिरा कहती हैं कि मान लीजिए, अगर मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है तो क्या हम अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते. बेटी की कमाई स्वीकार करना बिल्कुल भी हराम नहीं है. इस तरह के फ़तवे मुस्लिम समाज को और पिछड़ेपन की ओर ले जाएंगे.

हालांकि कई महिला संगठनों ने मुस्लिम लड़कियों के काम करने पर जारी फ़तवों का मुखर विरोध किया है. सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने इस फ़तवे पर कहा कि वह देवबंद और उसके फ़तवे को कोई महत्व नहीं देती हैं. यह मुस्लिम औरतों की ज़िंदगी में जबरन दख़लंदाज़ी करने जैसा है, फिर भी इस फ़तवे का पढ़ी-लिखी महिलाओं पर कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ेगा. मशहूर गीतकार एवं शायर जावेद अख़्तर ने जब इस फ़तवे के विरोध में मुंह खोला तो उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिलने लगी. बाद में इस फ़तवे पर सफाई देते हुए कहा गया कि काम करने से किसी को मना नहीं किया है, लेकिन महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करते समय अपनी इज़्ज़त और सम्मान का ख्याल रखना चाहिए. इसके पीछे तर्क यह था कि आजकल जिस तरह पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे लोग अपने अधिकार और हद भूल जाते हैं. लेकिन फ़तवा जारी करने वाले विद्वानों को क्या अपने अधिकार और हद याद हैं? क्या ऐसे फ़तवे मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करते?

नौकरी करके अपना जीवनयापन करना भी तो मौलिक अधिकार है. ऐसे में यह फ़तवा सुना दिया जाता है कि मुसलमान बैंक या शराब कंपनी में काम नहीं कर सकते. अब अगर किसी मुस्लिम युवा को कहीं कोई काम न मिले और किसी बैंक में नौकरी मिल रही हो, तो क्या वह उसे छोड़ देगा? जामिया से पढ़ाई कर रहे नूर आलम कहते हैं कि अगर कहीं और काम नहीं मिलता है और तब किसी बैंक या शराब कंपनी में काम मिलता है तो क्यों नहीं करूंगा. मजबूरी है, परिवार चलाना है तो काम क्यों नहीं करेंगे. इस मुद्दे पर और सुलझे तरीक़े से बात करते हुए जामिया से ही पर्शियन भाषा की पढ़ाई कर रहे फज़ल कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो बात सैकड़ों साल पहले कही गई, वह आज के जमाने में भी लागू हो. बैंक में काम करना हमारा पेशा है तो इसमें क्या बुराई है. लेकिन जेएनयू के पर्शियन विभाग के मोहम्मद आमिर शराब कंपनी में काम करने का पुरज़ोर विरोध करते हैं. वह कहते हैं कि शराब कंपनी में काम तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है. हां, अगर कोई दूसरा काम न मिल रहा हो, तब बैंक में काम किया जा सकता है, क्योंकि भारत जैसे देश में ब्याज से कहां-कहां बचा जा सकता है.

फ़तवों के बारे में इन छात्रों की राय भी काफी अहम है. जामिया के फज़ल का कहना था कि जब किसी बड़ी हस्ती के ख़िलाफ़ फ़तवा जारी किया जाता है तो क्या वह उसे मानता है. बिल्कुल नहीं. तो फिर फ़तवा जारी करने का मतलब ही क्या है? ऐसे ही अंबर जफर कहती हैं कि एसी ऑफिस में बैठकर फ़तवे जारी करने वाले मुफ्तियों को चाहिए कि वे ज़रा आम लोगों के बीच जाएं, उनकी हालत देखें, उनकी वास्तविक समस्याओं को समझें और फिर फ़तवा जारी करने के बारे में सोचें. आज के जमाने में ज़िंदगी चलाने के लिए सब को कमाना पड़ता है. कुछ महीने पहले जब शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद का यह बयान आया था कि महिलाएं सिर्फ़ बच्चे पैदा करें, राजनीति उनका काम नहीं है. तब भी *चौथी दुनिया* ने इस मामले पर मुस्लिम महिलाओं से बात की थी. साथ ही इस पर आवरण कथा भी प्रकाशित की थी, जिसमें कई जानी-मानी मुस्लिम महिला विद्वानों एवं शिक्षाविदों ने कल्बे जव्वाद के बयान की कड़ी आलोचना की थी. *चौथी दुनिया* से बात करते हुए मुस्लिम छात्राओं ने भी खुलकर इस बयान की निंदा की थी. जामिया से बायो साइंस की पढ़ाई कर रहीं बुशरा का कहना था कि मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ़ राजनीति, बल्कि सभी क्षेत्रों में आना चाहिए. साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मानती हूं कि हम लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमें राजनीति से लेकर सभी क्षेत्रों में जाने के लिए सोचना चाहिए. धर्म की ग़लत व्याख्या करके कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता.

बहरहाल यह रुख़ तो मुस्लिम युवाओं का रहा. यहां एक अहम सवाल यह है कि खाप पंचायतों के मामले पर कई नेताओं ने अपनी जुबान ख़ूब चलाई. ऐसे नेताओं में नवीन जिंदल, गृहमंत्री चिदंबरम तक शामिल थे. बाबा रामदेव भी खाप पंचायत पर बोले, लेकिन जब मामला फ़तवों का आता है तो हर तरफ ख़ामोशी छा जाती है. हां, जावेद अख़्तर जैसे कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी ही अपनी बात कह पाने की हिम्मत जुटा पाते हैं. आख़िर ऐसा क्यों और कब तक?

shashishekhar@chauthiduniya.com

फ़तवों पर मुस्लिम युवाओं की प्रतिक्रिया

लड़की की कमाई स्वीकार करना बिल्कुल हराम नहीं है. जब इस्लाम में सब चीजों में बराबरी की बात है तो फिर इस मामले में असमानता क्यों? अगर मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है तो क्या मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकती. इस तरह के फ़तवे मुस्लिम समाज को और पिछड़ेपन की ओर ले जाएंगे.

शहला : *टीचर ट्रेनिंग, जामिया.*

दफ्तर में अपने पुरुष सहकर्मी से ज़रूरत होने पर बातचीत की जा सकती है. बातचीत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? सारी बंदिशें लड़कियों के लिए ही क्यों? कुरान में तो पहले मर्दों के लिए ही पर्दा है कि वे किसी महिला को बुरी नज़र से न देखें.

खुशबू : *हिंदी ऑनर्स, जामिया.*

मैं एक टीचर हूं. मुझे 20 साल तक के बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग देनी होती है, उनसे बात करनी होती है. मेरे लिए यह संभव नहीं है कि उन बच्चों से बिना बात किए अपना काम कर सकूं. हां, यह ज़रूर है कि मैं अपने दायरे में रहती हूं. इस तरह के फ़तवे जारी करना ग़लत है.

अंबर जफर : *फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर, रॉकफोर्ड स्कूल, नोएडा*

मुस्लिम लडकियां काम क्यों नहीं कर सकती. मुस्लिम लड़कियां सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में ज़रूर काम कर सकती हैं. लेकिन यह भी ज़रूरी है कि लड़कियां हिजाब में भी रहें. और अगर ज़रूरत हो तो मुस्लिम लड़कियां अपने पुरुष सहकर्मी से बातचीत भी कर सकती हैं.

हुदा हसन : *जाकिर हुसैन कॉलेज, डीयू*

जरूरी नहीं है कि जो बात सैकड़ों साल पहले कही गई वो आज के ज़माने में भी लागू हो. वक्त के हिसाब से बहुत-सी चीजें बदल जाती हैं. जीवन यापन के लिए काम करना ग़लत तो नहीं है. और हम इसके लिए हम बैंक में काम करते हैं तो इसमें बुरा क्या है. यह हमारा पेशा है.

फजल : *पर्शियन विभाग, जामिया.*

मुस्लिम महिलाओं को न सिर्फ राजनीति, बल्कि सभी क्षेत्रों में आना चाहिए. साइंस की स्टूडेंट होने के नाते मानती हूं कि हम लड़कियों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और हमें राजनीति से लेकर सभी क्षेत्रों में जाने के लिए सोचना चाहिए. धर्म की ग़लत व्याख्या करके कोई हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता.

बुशरा, *बायो साइंस, जामिया*

क्या वे वाकई ऐसे फ़तवों को मानना चाहते हैं, जो उनकी आज़ादी में खलल डालते हों या बेवजह उन पर बंदिशें लगाती हों. या फिर, मर्द और औरत के बीच असमानता बढ़ाते हों? आख़िरकार, ऐसे फ़तवों और इन्हें जारी करने वाले मुफ्तियों के बारे में 21वीं सदी के पढ़े-लिखे और ऊंची तालीम हासिल करने वाले युवा मुस्लिम क्या सोचते हैं? यही सब कुछ जानने के लिए *चौथी दुनिया* ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ कामकाजी महिलाओं से बातचीत की. इन छात्रों से बात करना एक सुखद एहसास की तरह था. मुस्लिम लड़कियां खुल कर कैमरे के सामने हम से बात कर रही थीं. अपना फोटो खिंचवाने में उन्हें कोई संकोच नहीं था. उनकी बातें कह रही थीं कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं. अब हम अपनी मुस्तकबिल ख़ुद बनाएंगे.

दारूल उलूम देवबंद का वह फ़तवा, जिसके मुताबिक़ औरतों को मर्दों के साथ काम नहीं करना चाहिए और अपने पुरुष सहकर्मी से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, का विरोध करते हुए जाकिर हुसैन कॉलेज की छात्रा हुदा हसन कहती हैं कि मुस्लिम लड़कियां काम क्यों नहीं कर सकतीं. काम ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन हिजाब में रहकर और अगर ज़रूरत हो तो अपने पुरुष सहकर्मी से बातचीत भी कर सकती हैं. जामिया से हिंदी में ऑनर्स कर रही खुशबू तो एक क़दम आगे बढ़कर कहती हैं, सारी बंदिशें लड़कियों के लिए ही क्यों? कुरान में तो पहले मर्दों के लिए ही पर्दा है कि वे किसी महिला को बुरी नज़र से न देखें. दफ्तर में अपने पुरुष सहकर्मी से ज़रूरत होने पर ज़रूर बातचीत की जा सकती है. बातचीत नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? नोएडा के रॉकफोर्ड स्कूल में फिज़िकल ट्रेनिंग टीचर अंबर जफर कहती हैं कि वह एक टीचर हैं और उन्हें 20 साल तक के बच्चों को फिज़िकल ट्रेनिंग देनी होती है, उनसे बात करनी होती है. इसलिए उनके लिए यह संभव नहीं है कि बच्चों से बिना बात किए अपनी नौकरी कर सकें. अंबर यह ज़रूर मानती हैं कि वह यह सारा काम अपने दायरे में रहकर करती हैं. उनके मुताबिक़, इस तरह के फ़तवे जारी करना ग़लत है. तो क्या सारी बंदिशें महिलाओं पर लाद कर यह जताने की कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम महिलाएं समाज में असुरक्षित हैं या वह अपनी रक्षा ख़ुद नहीं कर सकतीं. लेकिन शायद वे भूल जाते हैं कि

सभी फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

मदन की मौत के बाद जिस तरह विमल गुरुंग की पार्टी के शीर्ष 11 नेताओं ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, उससे साबित होता है कि डंडे की राजनीति से पार्टी के भीतर कितना असंतोष था.

मुस्लिम आरक्षण का मायाजाल

यूसुफ़ अंसारी

हाल ही में जमीयत उलमा–ए–हिंद के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने दोनों को अपनी लंबी–चौड़ी मांगों का पुलिंदा सौंपा. प्रमुख मांग मुसलमानों को आरक्षण देने की है. साथ ही इसमें रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने की मांग भी शामिल है. मुलाक़ात के बाद जमीयत के स्वयंभू अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने मुसलमानों को आरक्षण देने के बारे में जल्द ही कोई ठोस फ़ैसला करने का भरोसा दिया है. इस दावे के बारे में अभी तक न तो प्रधानमंत्री की तरफ़ से कुछ कहा गया है और न ही सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ़ से.

पहली नज़र में यह दावा सरासर झूठा और गुमराह करने वाला लगता है. बुनियादी तौर पर हमारा संविधान धार्मिक आधार पर आरक्षण की इजाज़त नहीं देता. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सलमान ख़ुर्शीद भी खुले तौर पर यह बात पहले ही कह चुके हैं कि तमाम मुसलमानों को पिछड़ा घोषित करके उन्हें आरक्षण देने के लिए लाए गए आंध्र प्रदेश सरकार के विधेयक को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज़ कर दिया था. बाद में वहां भी पिछड़े वर्गों के मुसलमानों का कोटा तय करके मामले को सुलझाया गया. अभी यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. ऐसे में बात गले नहीं उतरती कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों को मुसलमानों को आरक्षण देने संबंधी कोई भरोसा दिया हो. प्रधानमंत्री से मुलाक़ात करने वाले मुस्लिम संगठनों के तमाम रहनुमा भी अच्छी तरह जानते हैं कि संविधान के मौजूदा स्वरूप के मुताबिक़ मुसलमानों को धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता. फिर सवाल पैदा होता है कि ये लोग ऐसा हवाई दावा क्यों कर रहे हैं, जिसे पूरा ही नहीं किया जा सकता? मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग पर आख़िर इन संगठनों का इतना ज़ोर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों की नज़र में हीरो बनकर ये संगठन और इनके रहनुमा अपना कोई उल्लू सीधा कर रहे हों और बाद में मुसलमानों को यह समझा दें कि हमने तो मांग की थी, लेकिन सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम क्या करें? दरअसल, मुसलमानों के लिए आरक्षण का मुद्दा बेहद पेचीदा है. इसे समझदारी और संयम से सुलझाने की ज़रूरत है. मसलमानों को आरक्षण और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करने की मांगें परस्पर विरोधी हैं. रंगनाथ मिश्र आयोग मुस्लिम समुदाय की उन बिरादरियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने की वकालत करता है, जिनकी समकक्ष हिंदू जातियां अनुसूचित जातियों में शामिल हैं. इसके लिए हमें ज़रा इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे. अनुसूचित जातियों में अभी तक हिंदू, सिख और बौद्ध ही शामिल हैं. हालांकि अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा तीन में शुरू में लिखा गया था कि ऐसा कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति में शामिल नहीं होगा, जो हिंदू धर्म से इतर किसी और धर्म को मानता हो, लेकिन बाद में सिखों की मांग पर 1955 में हिंदू शब्द के साथ सिख शब्द जोड़ा गया और 1990 में नवबौद्ध शब्द जोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा देने का रास्ता साफ़ कर दिया गया. 1996 में नरसिंह राव सरकार ने एक अध्यादेश के ज़रिए ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल करने की कोशिश की थी, लेकिन भाजपा के तीखे विरोध के चलते इस अध्यादेश को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा. तबसे ईसाई संगठन दलित ईसाइयों को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने की लगातार मुहिम चला रहे हैं. उन्हीं दिनों मुसलमानों में इस मुद्दे पर जागरूकता पैदा हुई. ऐसे तमाम मुसलमान जिनके पूर्वज कभी दलित हुआ करते थे, ख़ुद को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है. केंद्र सरकार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाख़िल करना है.

दलित ईसाइयों और मुसलमानों की इसी मुहिम का नतीजा है कि सरकार ने जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग को इस मसले पर विचार करके सिफ़ारिश करने का ज़िम्मा सौंपा. जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि धर्म के आधार पर मुसलमानों और ईसाइयों को आरक्षण से वंचित रखना संविधान के ख़िलाफ़ है. जस्टिस रंगनाथ मिश्र ने यह भी कहा है कि संविधान में संशोधन किए बग़ैर ही ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल किया जा सकता है. जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों पर अनुसूचित जाति आयोग भी अपनी मुहर लगा चुका है. अब यह पूरा मामला प्रधानमंत्री के हाथ में है. अगर मुस्लिम संगठन इस पर ज़ोर दें तो यह काम जल्दी हो सकता है. भाजपा और कांग्रेस को छोड़ कर तमाम राजनीतिक दल इसके हक़ में हैं. सवाल पैदा होता है कि तमाम मुस्लिम संगठन इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात क्यों नहीं करते? अभी तक एक भी मुस्लिम संगठन ने जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशें लागू कराने के लिए आंदोलन छेड़ने की बात नहीं की है. अगर रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशें अमल में आ जाएं तो मुसलमानों के विकास के रास्ते खुल सकते हैं. अनुसूचित जातियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं बेहद ग़रीब तबक़े के मुसलमानों को भी मिलने लगेंगी. यही नहीं, लोकसभा की 79 और देश भर में विधानसभाओं की उन 1050 सीटों पर चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो जाएगा, जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं. इससे महिला आरक्षण विधेयक में मुसलमानों के लिए कोटा तय करने का मसला भी हल हो जाएगा. ताज्जुब की बात है कि इतनी अहम सिफ़ारिशों को छोड़ कर तमाम मुस्लिम संगठन सारे मुसलमानों को आरक्षण की बेतुकी मांग पर अड़े हैं. इसके लिए संविधान के बुनियादी ढांचे को बदलना होगा. मौजूदा समय में यह बेहद टेढ़ी खीर है. वैसे भी सारे मुसलमानों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है. आरक्षण की ज़रूरत सिर्फ़ सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों को है. संविधान में भी आरक्षण का यही आधार तय किया गया है. अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले मुसलमान पहले से ही इस वर्ग के लिए तय 27 फ़ीसदी आरक्षण के हक़दार हैं. हां, यह और बात है कि उन्हें इस वर्ग में उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता, जितना मिलना चाहिए, क्योंकि यहां उनका मुक़ाबला आर्थिक रूप से मज़बूत पिछड़ी जातियों से होता है. जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों पर अमल के साथ ही इस वर्ग में आने वाली मुसलमानों की वे बिरादरियां अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगी, जिनकी समकक्ष हिंदू जातियां अनुसूचित जातियों में आती हैं. लेकिन इतनी अहम सिफ़ारिशों को लागू कराने पर तथाकथित मुस्लिम नेतृत्व का कतई ध्यान नहीं है. इसके उलट वे सारे मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग करके संघ परिवार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की वजह और ख़ुराक दोनों दे रहे हैं. ज़ाहिर सी बात है कि सारे मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग किसी भी सूरत से देश हित में नहीं है, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन अगर इसी पर अड़े हैं तो इसकी कोई और वजह हो सकती है. कहीं इसके पीछे यह वजह तो नहीं कि इन तमाम मुस्लिम संगठनों की कमान तथाकथित अगड़े मुसलमानों के हाथ में है. जस्टिस रंगनाथ मिश्र आयोग पिछड़े वर्गों के मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत करता है.

(लेखक चैनल वन के मैनेजिंग एडिटर हैं)

feedback@chauthiduniya.com

गोरखा राजनीति का एक तालिबानी चेहरा

बिमल राय

उनका यक़ीन है कि वे मुझे चुप करा सकते हैं, मगर यहां तक कि अगर कल मैं मर जाता हूं तो कब्र से भी आवाज़ दूंगा. मुझे जिस विचार पर विश्वास है, उसका त्याग मैं इतनी आसानी से नहीं करूंगा. मैं पूरी ताक़त से आवाज़ दूंगा, जगो जगो! केवल तुम्हीं हो, जिसमें एक बेहतर गोरखालैंड बनाने की ताक़त है. एक ऐसा गोरखालैंड, जिस पर तुम गर्व कर सको. दार्जिलिंग के चौक बाज़ार में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तामांग ने अपने आख़िरी भाषण में यही बात कही थी. अपनी सादगी, आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति एवं साहस के लिए विख्यात गोरखाओं की ज़मीन तालिबानी राजनीति का शिकार हो गई है. हिंसा नहीं, लोकतांत्रिक तरीक़े से अपनी बात रखने के पक्षधर तामांग की आशंका इतनी जल्दी उन्हें लील लेगी, यह कोई भी नहीं सोच सकता था. उस दिन भी नहीं, जिस दिन उन्हें रेत दिया गया. जिस राजनीतिक लंठई के बूते विमल गुरुंग चर्चा में आए और गोरखाओं का बहुमत पाया, उसके मुक़ाबले मदन लो प्रोफाइल बरतते थे. हालांकि वह 68 साल पुरानी पार्टी के मुखिया थे और 68वें स्थापना दिवस पर सुबह एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे. उनकी पार्टी तब बनी थी, जब आज गोरखाओं की तरफ़दारी कर रहे नेताओं सुभाष घीसिंग और विमल गुरुंग का संभवत: जन्म भी नहीं हुआ था. 21 मई की सुबह दार्जिलिंग में दरअसल मदन तामांग की हत्या के साथ गोरखा राजनीति का एक बड़ा उदारवादी चेहरा मिट गया, पर हारते–हारते वह जीत गए जैसे लगते हैं.

विमल गुरुंग

मदन की मौत के बाद जिस तरह विमल गुरुंग की पार्टी के शीर्ष 11 नेताओं ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, उससे साबित होता है कि डंडे की राजनीति से पार्टी के भीतर कितना असंतोष था. इनमें अनमोल प्रसाद, हर्क बहादुर छेत्री, मदन तामांग के भाई अमर लामा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव त्रिलोक दीवान, एल बी पेरियार, अमर राई, सी के सुब्बा, नारायण थापा एवं भवजीत तामांग सहित केंद्रीय कमेटी के नेता भी शामिल हैं. हालांकि इस संबंध में गोरखा जनमुक्ति मोर्चे के महासचिव रोशन गिरि ने चौथी दुनिया को बताया कि ज़्यादातर वही नेता हैं, जिन्हें हम निकालने वाले थे. इसके बावजूद पार्टी का खिसकता जनाधार अब छिपाने की बात नहीं रहा. 24 मई को बंद, बरसात और ठंड के बावजूद मदन की शवयात्रा में हज़ारों लोग आए. रास्ते में जनमुक्ति मोर्चा के पोस्टर एवं बैनर फाड़े गए और लोगों ने एक सुर में विमल गुरुंग मुर्दाबाद के नारे लगाए. मदन तामांग को अलग गोरखालैंड राज्य के बदले अंतरिम ढांचा मंजूर नहीं था. उन्होंने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नेताओं पर सरकारी ठेकों के ज़रिए मोटी कमाई करने का आरोप भी लगाया था. वह लोगों को समझा रहे थे कि अलग राज्य के नाम पर आंदोलन के माध्यम से जिस तरह सुभाष घीसिंग ने पर्वतीय परिषद हासिल करके समझौता कर लिया, उसी तरह विमल गुरुंग भी अंतरिम व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि राजनीतिक रूप से यह पहल व्यवहारिक है, क्योंकि गोरखालैंड राज्य का गठन नामुमकिन सा है. गुरुंग की सोच है कि अंतरिम व्यवस्था के ज़रिए वह बेहतर प्रशासन और अपने तरीक़े से विकास के काम जारी रख सकते हैं. ज़ाहिर है, गोरखाओं का एक कट्टरपंथी तबका इससे ख़ुश नहीं था और मदन तामांग इस तबके की सहानुभूति से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे. इसके अलावा मदन ने पहाड़ पर लोकतंत्र बहाल करने के लिए भाजपा, तृणमूल, सिक्किम एकीकरण मंच, जीएनएलएफ (सीके गुट) एवं क्रांतिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया था और वह इसके ज़रिए एक बड़ा आंदोलन भी छेड़ने वाले थे. राजनीतिक रूप से यह क़दम सही था और लोकतंत्र बहाली के लिए मोर्चा बनाने से यह संकेत उभरा कि वर्तमान पर्वतीय परिषद को फिर से बहाल करने से ही अंतरिम व्यवस्था क़ायम हो जाएगी. गोरखाओं का एक बड़ा जनमत मदन से सहमत होता दिख रहा था और शायद यही विमल गुरुंग को अखर रहा था. फिर भी अगर गुरुंग अपनी राजनीति में सह अस्तित्व और मेलमिलाप वाले तत्व के लिए थोड़ी जगह रखते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता.

गुरुंग को अपने राजनीतिक विरोधियों का आगे बढ़ना कभी अच्छा नहीं लगा. सुभाष घीसिंग की दुर्गति को कोई कैसे भुला सकता है. पर्वतीय परिषद के मुखिया पद से इस्तीफ़ा देने के बाद भी वह कई महीनों तक दार्जिलिंग जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे और उन्हें सिलीगुड़ी में डेरा डालना पड़ा. पहाड़ पर लोकतंत्र का नामोनिशान तक नहीं था, इसमें कोई शक नहीं. तारीख़ दर तारीख़ विमल गुरुंग के आंदोलन पर ग़ौर करने से यह बात साफ हो जाती है. पहाड़ पर आने वाली गाड़ियों में जबरन गोरखालैंड का नंबर प्लेट लगाने, नगरपालिकाओं एवं पंचायतों को लंगड़ा बनाने, पार्टी का अपना पुलिस बल बनाने और सरकारी कार्यालयों में ताला मारने जैसी दर्जनों हरक़तों ने विमल गुरुंग के कथित गांधीवादी आंदोलन का जमकर उपहास उड़ाया. अपना जोर दिखाने के लिए बात–बात पर बंद और पथावरोध जैसे कार्यक्रमों का सहारा लेकर विमल ने पहाड़ की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा कर दिया. आंदोलन का ही नतीजा है कि वहां चाय एवं पर्यटन उद्योग पानी मांग रहे हैं और कभी बेहतर शिक्षा के लिए मैदानी इलाक़ों से कालिंपोंग जाने वाले बच्चे मैदानी इलाक़ों का रुख़ कर रहे हैं या फिर सिक्किम का. घीसिंग के बाद मदन तामांग भी गुरुंग के निशाने पर थे और उन्हें भी राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा था. गोरखा लीग का स्थापना दिवस 15 मई को पड़ता है, पर अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था में डुआर्स और तराई के नेपाली बहुल हिस्सों को शामिल करने से केंद्र के इंकार का विरोध करने के लिए गुरुंग ने दो दिन का बंद बुलाया था. 21 मई को भी गोरखा लीग को अपनी जनसभा चौक बाज़ार के बदले क्लब हाउस पर आयोजित करनी पड़ी, क्योंकि अचानक वहां जनमुक्ति मोर्चे की जनसभा होने लगी. 24 जुलाई को मदन तामांग की शवयात्रा निकली. लोग उसमें भाग न ले सकें, इसके लिए गुरुंग ने बंद बुलाया था. हालांकि हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हुए. हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग गोरखा लीग और जनमुक्ति मोर्चा दोनों ने की है. हालांकि बंगाल सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश दिया है. खुद को बेदाग साबित करने के लिए विमल गुरुंग ने सीबीआई जांच की मांग की है, पर इसमें कोई शक नहीं कि इस वारदात के बाद उनके जनाधार को जोर का झटका लगा है. डेमोक्रेटिक फ्रंट के संयोजक एवं भाजपा के राज्य सचिव दावा शेरपा ने एक राजनीतिक दल के रूप में जनमुक्ति मोर्चे की मान्यता रद्द करने की मांग की है. गुरुंग के रवैये से नाराज़ होकर भाजपा ने भी अलग राह अपनाई है. बताने की ज़रूरत नहीं कि पिछले संसदीय चुनाव में जसवंत सिंह को विमल गुरुंग के समर्थन से ही जीत हासिल हुई थी. फ्रंट के नेता भी सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने वाले हैं. हाल में इन नेताओं ने राज्यपाल एम के नारायणन से भी मुलाक़ात कर पहाड़ पर लोकतंत्र बहाल करने की गुहार लगाई थी.

आंदोलनों की गर्द से सिक्किम की भी सांस फूल रही है. पिछले साल शराबबंदी के नाम पर सिक्किम से आने वाले पर्यटकों की तलाशी ली गई. बंद के चलते सिक्किम कई–कई दिनों तक देश से कटा रहता था. कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गईं और सरकार ने केंद्र से गुहार लगाई. अभी भी हालात बेहतर नहीं हुए हैं. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के महासचिव एवं प्रवक्ता भीम दाहाल ने चौथी दुनिया को बताया कि मदन तामांग की हत्या लोकतंत्र की हत्या है. उनके मुताबिक़, सिक्किम में अभी 50 हज़ार करोड़ की निवेश योजनाएं चालू हैं और इन्हें बरक़रार रखना मुश्किल हो रहा है. दार्जिलिंग में अशांति के चलते अभी सिक्किम की कुल आबादी से डेढ़ गुना की तादाद में पर्यटक आ रहे हैं. अगर बंद और पथावरोध जारी रहा तो पर्यटन उद्योग चौपट हो जाएगा. सवाल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहा है. दिनदहाड़े खुखरी लहराते हुए 40–50 हमलावर आते हैं, एक नेता का कत्ल कर देते हैं और 40 पुलिसवाले वहां

फोटो– रॉबिन गिरि

इस दृश्य को देख रहे होते हैं. यह बात हजम नहीं होती. मदन के सुरक्षागार्डों की गोलियों से दो हमलावर जख्मी होते हैं, पर पुलिस की बंदूक़ों से गोली नहीं निकलती. उत्तर बंगाल के आईजी के एल टामटा ने यह कहकर हाथ उठा दिया कि हमने पुलिस बल तैनात कर दिया था. आप राज्य सरकार से पूछिए कि उन लोगों ने गोली क्यों नहीं चलाई? चौथी दुनिया को उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि जब जांच होगी, तब देखा जाएगा कि क्या वाकई पुलिस उन्हें बचा सकती थी? अस्सी के दशक से शुरू हुए गोरखालैंड आंदोलन में अब तक 300 से ज़्यादा राजनीतिक हत्याएं हुई हैं. इनमें 1989 में माकपा के विधायक टी एस गुरुंग, माकपा की छात्र शाखा एसएफआई की नेता रेखा तामांग एवं गोरखा लीग के नेता सुदर्शन शर्मा की हत्या हुई. मार्च 1999 में पर्वतीय परिषद के सदस्य रुद्र जूमर और 2001 में नरेन राई एवं जीएनएलएफ नेता सी के प्रधान की हत्या कर दी गई. अभी हाल में पर्वतीय परिषद के एक सदस्य की भतीजी किरण ठकुरी की हत्या हुई थी. मदन की हत्या के सिलसिले में विमल गुरुंग, उनकी पत्नी आशा गुरुंग एवं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कई बड़े नेताओं को हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोपी बनाया गया है और हत्यारों की धरपकड़ जारी है. इस सिलसिले में सिक्किम सरकार से भी मदद मांगी गई है.

विमल गुरुंग ने कहा है कि अगर एक भी काडर को गिरफ़्तार किया गया तो पार्टी जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. हत्या के लिए गुरुंग ने राज्य सरकार और गोरखा लीग के एक धड़े को ही दोषी ठहराया है. गुरुंग ने कहा कि पार्टी के गोरखालैंड आंदोलन को नुक़सान पहुंचाने के लिए यह हत्या करवाई गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दिन गोरखा लीग के काडर माओवादियों द्वारा दिए गए हथियारों से लैस थे. बंगाल सरकार इस बहाने विमल गुरुंग को अलग–थलग करने में जुट गई है. उत्तर बंगाल के मुख्यमंत्री माने जाने वाले एवं नगरपालिका मामलों के मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि अब जनमुक्ति मोर्चा ने जनाधार खो दिया है और देखना होगा कि उसे त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल किया जाए या नहीं. विमल गुरुंग की दबंगई ही आज उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बनकर उभरी है. वर्षों से निष्क्रिय माकपा ने 24 मई को अपनी जोनल कमेटी की बैठक बुलाई. डेमोक्रेटिक फ्रंट भी अपनी रणनीति बना रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

इस समय जलस्तर 746 मीटर पर पहुंच चुका हैं. माना जा रहा है कि यदि एक पखवारे के भीतर वर्षा न हुई तो विद्युत उत्पादन ठप हो सकता है.

जाति, जनगणना और आरक्षण

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

निखिल आनंद

जाति भारतीय समाज की जड़–ज़मीन से जुड़ी एक बड़ी हक़ीक़त है, पर अफ़सोस कि मौजूदा बौद्धिक वर्ग बहस में सबसे कम शामिल है. पढ़े–लिखे लोग यानी बुद्धिजीवी, जिनमें समाजशास्त्री एवं राजनीतिक विद्वान भी शामिल हैं, इस मसले पर बहस करने से कतराते नज़र आते हैं, मानों इससे उन्हें जातिवादी करार दिया जाएगा. शायद इसी वजह से जाति के सवाल पर अधिकतर लोग विनम्र दिखने की कोशिश में चुप रहते हैं. लेकिन बात वही है कि मर्ज छुपाने से बढ़ता है तो फिर उस पर बातचीत कर हल ढूंढने की कोशिश क्यों न की जाए. हाल में सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर सहमति व्यक्त की है. पर वस्तुस्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यह जनगणना पूरी तौर पर जाति आधारित होगी या सिर्फ़ ओबीसी की. आश्चर्य है कि एक ओर जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और दूसरी ओर सरकार संसद में बहस कराने और आश्वासन देने के बाद भी निर्णय में देरी कर रही है. इससे पूरी प्रक्रिया बाधित होगी. सरकार की मंशा ज़ाहिर करने के बाद अब कई बुद्धिजीवी भी उसके पक्ष और विपक्ष में अपने–अपने तर्कों और पूर्वाग्रहों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं. कुछ लोगों का समर्थन सिर्फ़ ओबीसी की गिनती करने के पक्ष में दिखता है. सवाल यह उठता है कि क्या करोड़ों रुपये ख़र्च करके कराई जा रही इस जनगणना का संदर्भ सिर्फ़ आरक्षण से है अथवा यह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास से भी जुड़ी है.

अगर सिर्फ़ ओबीसी आधारित जनगणना होती है तो यह मंडल के नाम पर चल रही राजनीति को आगे खींचने की तुच्छ कोशिश होगी. जनगणना में देश के हर नागरिक की सामाजिक (जाति) और आर्थिक जानकारी का आंकड़ा होना चाहिए. इसका मतलब यह नहीं कि सब पर जाति थोपी जाए. जिन्हें जाति में विश्वास नहीं है या फिर वे इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, उनके लिए भारतीय या फिर अन्य का विकल्प भी दिया जाए. जनगणना के बाद सरकार मंडल सूची के आधार पर ओबीसी की संख्या जान सकती है और एससी–एसटी की संख्या भी. देश में कई ऐसे जनजातीय समुदाय और भाषाएं हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. उनकी जनसंख्या का पता लगे और सरकार उनकी हिफ़ाज़त के लिए काम करे. कई समुदाय अब भी सरकारी सूची में नहीं हैं या फिर घुमंतू जातियां हैं. इनकी सामूहिक आबादी करोड़ों में है, उनकी संख्या का भी पता लगे और योजनाओं में उन्हें शामिल किया जाए. किन्नरों को अभी तक पुरुष की श्रेणी में गिना जाता है, उनकी पहचान भी अलग होनी चाहिए. हम इस तरह के आंकड़ों को समस्या समझना छोड़ दें, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर देश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास की सही पृष्ठभूमि तैयार हो सकती है.

देश में जाति का जन्म आधारित सिद्धांत है, जो भी जिस जाति में पैदा होता है, उसी में मर जाता है. यह एक जड़वादी व्यवस्था है. समाज में सब कुछ बदल सकते हैं, यहां तक कि धर्म भी, पर जाति नहीं बदल सकते. समाज में आत्म स्वाभिमान और सम्मान जाति के आधार पर है और इसका एक उच्च जातिगत रुझान है. कई बुद्धिजीवी ख़ासकर नई आर्थिक व्यवस्था के आने के बाद ज़ोर–शोर से वर्गवाद के सिद्धांत को भारतीय समाज पर थोपने में लगे हैं. देश में अगर अभिजात्य वर्ग का उभार हो रहा है तो भी उसका जातिगत संदर्भ मौजूद है. जाति के संदर्भ में वर्गवाद की चर्चा अवश्य होनी चाहिए, पर वर्ग के नाम पर जाति की समूची अवधारणा को ख़ारिज करना बौद्धिक साजिश से कम नहीं है. देश के किसी भी अख़बार का मैट्रिमोनियल पेज देखें तो पता चल जाएगा. मानवाधिकारों के उल्लंघन और बलात्कार के मामलों का अध्ययन करें तो सबसे ज़्यादा दलित और उसके बाद पिछड़ी जाति के लोग पीड़ित हैं. मंडल के बाद दलित–पिछड़ी जातियों में जो गति आई है, उस पर जातिवाद का लेबल चिपका देना बौद्धिक मठाधीशों की एक सहज प्रवृत्ति हो सकती है, पर इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाएं मज़बूत हुई हैं, यह भी क़ाबिले ग़ौर है. हालांकि दलित–पिछड़े नेताओं की पहली जमात बौद्धिक नेतृत्व अभी तक नहीं दे पाई है, पर समाज में इन प्रतीकों के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता. एक नई बहस इन दिनों शुरू है, उच्च जाति के ग़रीबों को अलग आरक्षण देने को लेकर. अगर कभी भविष्य में इसकी व्यवस्था होती भी है तो क्या सरकार इस बात को रोकने में समर्थ है कि सक्षम सवर्ण इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे. इसलिए एक ऐसी जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसमें देश के सभी नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का ज़िक्र हो, ताकि आरक्षण के लाभ के लिए जाति और आर्थिक आधार के दुरुपयोग को रोका जा सके. अभी भी दलित और ओबीसी के आरक्षण के दुरुपयोग के मामले कम नहीं हैं.

ओबीसी जनगणना करा देने मात्र से जाति आधारित सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, ऐसा भी नहीं है. कई जातियों और उपजातियों की तरफ़ से दलित एवं ओबीसी में शामिल करने को लेकर मांग और आंदोलन होते रहते हैं. सरकार भी समय–समय पर ऐसे कई समूहों को आरक्षण सूची में शामिल करती रही है. इस संदर्भ में जाति आधारित जनगणना का एक विकल्प नज़र आता है. सारी पार्टियां आरक्षण की अवधारणा को स्वीकार करती हैं, लेकिन यह कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि आरक्षण देश की जातिगत समस्याओं का एक स्थायी समाधान है. लिहाज़ा इस सकारात्मक भेदभाव नीति को तात्कालिक ज़रूरत समझते हुए भविष्य में इसके स्थायी समाधान पर काम करना होगा. भविष्य में आरक्षण से परे किसी भी नई नीति पर काम करने अथवा नीति और योजना बनाने के लिए जातीय जनगणना के रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण आधार होंगे. एक बड़ा तबका यह प्रचारित करने में लगा है कि जातीय जनगणना से देश में जातिवाद बढ़ जाएगा. इस प्रकार की विविधता पश्चिमी देशों सहित दुनिया भर में है. अमेरिका एवं ब्रिटेन में भी इस प्रकार की जनगणना होती है, जहां ब्लैक, व्हाइट, हिस्पैनिक एवं एशियन सभी के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं. क्या इन देशों में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है? भारत में भी धर्म के आधार पर जनगणना होती रही है. हाल में एक सर्वेक्षण द्वारा सरकार ने जानकारी एकत्र की कि देश की नौकरियों में अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है. तो क्या इससे धर्मान्धता लोकतंत्र पर हावी हो गई? हर जनगणना में हिदुओं की आबादी देश में सबसे ज़्यादा दिखाई जाती है. इस संदर्भ में, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, महज़ एक अवधारणा हो सकती है, पर सबको मालूम है कि यह संभव नहीं और ऐसे विचार हर चुनाव में मात खाते हैं. जो लोग धर्म निरपेक्षता के समर्थक हैं, उन्हें सामाजिक न्याय और समानता का तत्व स्वीकार करने में क्या दिक़्क़त हो सकती है. अगर देश में जाति आधारित जनगणना ग़लत है तो धर्म आधारित जनगणना के पक्ष में अलग बौद्धिक दलील क्या है?

हाल में राजेंद्र सच्चर और रंगनाथ मिश्र ने अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित दो अलग–अलग रिपोर्ट पेश की. उसके बाद से देश भर में अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है. कई प्रगतिवादी और समाजवादी इस मुहिम में शामिल हैं. बहुत कम लोगों को याद होगा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी ने मंडल कमीशन के बाद के दौर में मुस्लिम आरक्षण का मामला उठाया था, तब समाजवादी नेता मधु लिमए ने उनकी इस बात का विरोध किया था कि धर्म आधारित आरक्षण संविधानसम्मत नहीं है और अगर वह इतने ही चिंतित हैं तो सभी अल्पसंख्यक समुदायों के दलितों एवं ओबीसी को उनके हिंदू भाइयों की तरह बराबरी का दर्जा क्यों नहीं दिला देते. मधु लिमए का मानना था कि धर्म एक ग्लोबल फेनोमेना है, वहीं जाति एक स्थानीय फेनोमेना. इस नाते धर्मान्धता हमेशा जातिवाद से ज़्यादा ख़तरनाक होती है. भारतीय समाज के हर जानकार को पता है कि यहां हर धर्म जातियों में विभाजित है और उसमें दलित–पिछड़े हैं. चाहे वह इस्लाम धर्म हो या ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन. अल्पसंख्यक पिछड़ी जाति को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिला है, पर उनके दलित अभी भी वंचित हैं. देश के बुद्धिजीवी अल्पसंख्यक समुदाय के दलितों–पिछड़ों को हिंदुओं के बराबर अधिकार देने की बात क्यों नहीं करते. इस संदर्भ में भी जाति आधारित जनगणना एक बेहतर आंकड़ा देगी.

किसी भी राजनीतिक दल के लिए धर्म और जाति के नाम पर खेल करना आसान है, लेकिन जातिगत आंकड़े इस पूरे खेल को ख़त्म कर देंगे. तब कोई भी पार्टी और सरकार हाशिए पर पड़े लोगों के हक़ में नीतिगत और विकास से जुड़े फ़ैसले लेने के लिए बाध्य होगी. नई आर्थिक नीति और सूचना क्रांति के बाद हर समाज की जितनी उत्सुकता राजनीतिक भागीदारी को लेकर है, उससे कहीं ज़्यादा अर्थव्यवस्था में भागीदारी को लेकर हैं. ऐसे में क्या ग़लत है कि हर समाज, ख़ासकर दलितों–पिछड़ों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक बराबरी मिले. इन्हें वंचित रखने की कोई भी दलील शर्मनाक है. जाति समाज की एक क्रूर हक़ीक़त है. जाति समाज में बहुसंख्यक तबके की निजी पहचान से जुड़ा मसला है. सीधे तौर पर इसे ख़ारिज़ करना आगे बढ़ रहे दलित–पिछड़े समाज के ख़िलाफ़ एक बौद्धिक साजिश है, पहचान से वंचित और अंततः हाशिए पर बनाए रखने की. लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ का अध्ययन करें तो एक ख़ास तबके का वर्चस्व साफ नज़र आता है. मीडिया भी इस जातिगत पूर्वाग्रह से परे नहीं है. जाति बहस और विमर्श से टूटेगी. ज़ाहिर है, इसमें लंबा वक़्त लगेगा. इस मुहिम में वास्तविक प्रगतिवादियों की बड़ी भूमिका होगी, जिनके चेहरे पर मुखौटा न हो और जिनकी नीति एवं नीयत में कोई फ़र्क़ न हो. देश का सामाजिक विकास और उसमें दलितों, पिछड़ों एवं वंचितों की भागीदारी जातिगत जनगणना के माध्यम से ही संभव है. इससे जाति के नाम पर चल रही अन्यथा राजनीति और ग़ैर ज़रूरी जातिगत मांगों पर भी रोक लगेगी. जनगणना से मिले आंकड़ों का प्रयोग समाजशास्त्रियों, नीति निर्धारकों एवं सरकार द्वारा देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में किया जा सकता है. अगर इस बार जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो फिर यह बहस दस सालों के लिए पीछे चली जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में बिजली संकट गहराया

देश की अति महत्वाकांक्षी टिहरी बांध परियोजना में लगातार गिरते जलस्तर से किसी भी क्षण विद्युत उत्पादन ठप होने की आशंका बढ़ती जा रही है. इस बांध में अब विद्युत उत्पादन के लिए मात्र छह मीटर जल शेष रह गया है. जानकारों का मानना है कि अब तो सब कुछ मानसून पर ही निर्भर है. समय से मानसून न आने पर आने वाले दिनों में किसी भी दिन विद्युत उत्पादन ठप हो सकता है.

जलसंकट के चलते इन दिनों इस परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन में भारी कमी दर्ज की जा रही है. इससे पूरे उत्तराखंड सहित केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बिजली की भारी किल्लत उठानी पड़ रही है. इस वर्ष हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फबारी के साथ वर्षा के भी कम होने और महाकुंभ 2010 में बांध का जल स्नान के लिए छोड़े जाने से पानी की भारी कमी दर्ज की गई है. जानकारों का मानना है कि यदि टिहरी बांध से हरिद्वार कुंभ के लिए पर्याप्त जल न छोड़ा जाता तो आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान का सुख न मिल पाता. जानकार कहते हैं कि इस बार इस बांध ने ही गंगा मां की लाज बचा ली. उनका मानना है कि बांध में पानी की कमी का असर सीधे टिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ देश के नौ राज्यों की बिजली आपूर्ति पर भी पड़ेगा. तकनीकी विभाग के लोग मानते हैं कि 740 मीटर जलस्तर पर ही टर्बाइन चलती है, जिससे विद्युत उत्पादन संभव हो पाता है. इस समय जलस्तर 746 मीटर पर पहुंच चुका हैं. माना जा रहा है कि यदि एक पखवारे के भीतर वर्षा न हुई तो विद्युत उत्पादन ठप हो सकता है. साथ ही पीने के पानी का संकट भी इस बांध से जुड़े राज्यों को झेलना पड़ सकता है. पानी की कमी की वजह यह बताई जा रही है कि बांध से रोज़ाना 150 मीटर पानी ही छोड़ने की व्यवस्था थी, जिसके सापेक्ष कुंभ को देखते हुए रोज़ाना 300 मीटर पानी छोड़ा गया. इस बांध में 75 प्रतिशत केंद्र एवं 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी तय की गई थी. उत्तर प्रदेश के विभाजन के बाद उसके हिस्से में से 50 प्रतिशत हिस्सेदारी उत्तराखंड को मिली है, जिसके हिसाब से इस राज्य को 148 मिलियन यूनिट बिजली प्राप्त होती है. टिहरी बांध का जलस्तर गिरने से राज्य की जनता के माथे पर पसीना छलछला रहा है. तपती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और वे अब चातक की तरह आकाश की ओर निहार रहे हैं.

जलसंकट के चलते इन दिनों इस परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन में भारी कमी दर्ज की जा रही है. इससे पूरे उत्तराखंड सहित केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार को भी बिजली की भारी किल्लत उठानी पड़ रही है. इस वर्ष हिमालयी क्षेत्र में कम बर्फबारी के साथ वर्षा के भी कम होने और महाकुंभ 2010 में बांध का जल स्नान के लिए छोड़े जाने से पानी की भारी कमी दर्ज की गई है.

राजकुमार शर्मा
feedback@chauthiduniya.com

खास बात यह देखी जा रही है कि किसानों, कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याएं अलग-अलग होने के बावजूद सभी तबके के लोग एकजुट हो रहे हैं.

पंजाब

दमन के ख़िलाफ जनता में उबाल

जगदीश यादव

देश का पेट भरने वाला पंजाब इन दिनों आंदोलनों और बादल सरकार द्वारा दमन के लिए काफी चर्चा में है. राज्य पुलिस किसी भी तरह के आंदोलन और विरोध के स्वर को कुचलने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपना रही है. इसका खुलासा जनहस्तक्षेप द्वारा वहां भेजे गए बुद्धिजीवियों के एक दल ने किया. जांच दल में शामिल डी यू के प्रोफेसर डॉ. एन भट्टाचार्य, वरिष्ठ पत्रकार जसपाल सिंह सिद्धू एवं अनिल दूबे ने 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक पंजाब का दौरा किया. जांच दल ने गुरुदासपुर के खन्ना चमियारा, अमृतसर के भिंडी सैदा एवं अजनाला आदि गांवों के अलावा बटाला और मोगा ज़िलों का दौरा किया. पंजाब पिछले कई दशकों से हरित क्रांति के नायक, देश के अन्नदाता एवं बड़ी संख्या में एनआरआई तैयार करने वाले राज्य के रूप में जाना जाता रहा है, किंतु यही पंजाब अब एक नई करवट लेता दिखाई दे रहा है. जांच दल के अनुसार, राज्य में कर्मचारियों, छात्रों एवं किसानों के बीच एक नई हवा चल रही है. विद्युत कारपोरेशन का विभाजन हो या शिक्षण संस्थानों का निजीकरण, छात्रों को बस पास की मांग का मामला हो या ज़मीन पर किसानों के हक़ का, चारों तरफ़ विरोध की हवा बहती दिखाई दे रही है. इन आंदोलनों को कुचलने के लिए पंजाब की गठबंधन सरकार एक ही तौर-तरीक़ा अपना रही है और वह है दमन का. सरकार सुरक्षाबलों के साथ-साथ धार्मिक एवं जातीय सेनाओं का भी इस्तेमाल कर रही है. खन्ना चमियारा गांव में एसपीजीसी की हथियारबंद टास्क फोर्स द्वारा फायरिंग कर दो किसानों को मौत के घाट उतार देने का मामला हो या फिर बीती 16 फरवरी को अमृतसर ज़िले के भिंडी सैदा गांव में भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राही के कार्यकर्ता कामरेड साधु सिंह की हत्या का, सभी मामलों में स्थानीय पुलिस एवं अकाली- भाजपा गठबंधन के नेताओं एवं उनके समर्थकों की भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है. देश के अन्य भागों की तरह पंजाब में भी इस वक़्त ज़मीन का सवाल प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. सामंत-पुराने जमींदार गांवों में भू-माफ़ियाओं एवं कॉरपोरेट जगत और शहरों में राजनेताओं के इशारे पर बल प्रयोग द्वारा ज़मीनों पर क़ब्ज़ा करते जा रहे हैं. गुरुदासपुर ज़िले के खन्ना चमियारा गांव के हरपाल सिंह ने बताया कि 12 सौ एकड़ कृषि भूमि यहां ज्वलंत मुद्दा है. पूर्व में यह ज़मीन गुरुद्वारों के महंतों की होती थी, जिन्हें ब्रिटिश शासन का समर्थन प्राप्त था. 1921 में महंतों के ख़िलाफ़ हुए आंदोलन के दौरान फायरिंग में बहुत से लोग मारे गए. उन दिनों अकाली दल ने गुरुद्वारों में सुधार का आंदोलन चलाया था. चूंकि यह ज़मीन बंजर और अनुपयोगी थी, इसलिए समझौते के तहत 70 वर्ष पूर्व इस ज़मीन को एसजीपीसी ने स्थानीय ग़रीबों एवं दलितों को बटाईदारी के तौर पर दे दिया. बाद में लोगों ने इस ज़मीन पर कड़ी मेहनत कर इसे उपजाऊ बना दिया. अब इसी ज़मीन पर एसजीपीसी की नज़रें टिक गई हैं. हरपाल सिंह ख़ुद एक बटाईदार हैं. उनका कहना है कि 70 वर्ष पूर्व हुए समझौते के तहत बटाईदारों को एसजीपीसी को कुछ किराया देना था और एसजीपीसी को प्राप्ति की रसीद देनी थी. इधर कुछ वर्षों से एसजीपीसी ने किराया लेना बंद कर दिया तो किसानों ने किराया स्थानीय प्रशासन के पास जमा करना शुरू कर दिया, क्योंकि पांच वर्ष तक किराया न देने पर किसान का हक़ समाप्त हो जाता है. गांव के सरपंच किसानों से अलग धार्मिक सोच रखने के कारण पैसा गुरुद्वारे में ही जमा कराते रहे, लेकिन रसीद नहीं दी जाती थी. अंतत: उन्हें ज़मीन खाली करने की नोटिस दे दी गई. 30 नवंबर 2009 को हथियारबंद एसजीपीसी टास्क फोर्स के 250 लोग विभिन्न गुरुद्वारों के प्रमुखों, अवतार सिंह मक्कड़, सचिव दिलमेध सिंह एवं कश्मीर सिंह के साथ ज़मीन खाली कराने के लिए खन्ना चमियारा गांव पहुंचे तो किसानों ने विरोध किया. इस पर टास्क फोर्स ने फायरिंग कर दी, जिसमें किसान बलविंदर और कश्मीर सिंह मारे गए और दर्जनों किसान घायल हो गए. टास्क फोर्स ने सिर्फ़ बच्चों एवं महिलाओं को ही नहीं पीटा, बल्कि पालतू पशुओं को भी गोली मार दी. घंटों बाद ज़िले के पुलिस अधीक्षक मौक़े पर पहुंचे, तब तक टास्क फोर्स का तांडव जारी रहा. कीर्ति किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान डटे रहे तो एसपी ने पुलिस संरक्षण में टास्क फोर्स के हमलावरों को सुरक्षित गांव से बाहर निकाल दिया. पुलिस ने किसानों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की. भारी विरोध के बाद सिर्फ़ 19 लोगों के ख़िलाफ़ पुलिस ने स्वयं मामला दर्ज किया, 10 मुख्य आरोपियों को साफ छोड़ दिया गया. किसानों का कहना है कि जब-जब राज्य में अकाली दल सत्ता में आता है, तब-तब उन पर गाज गिरती है.

एक अन्य मामला भी जांच दल के सामने आया. रावी नदी के किनारे लगभग 8 किमी चौड़ी और 150 किमी लंबी कछार ज़मीन की पट्टी तैयार हो गई है, जो ख़ुद में एक बड़े किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि समेटे है. अपने बहाव के रुख़ में बदलाव करते हुए रावी नदी खिसकते-खिसकते पाकिस्तान की सीमा के समीप चली गई है. इस ज़मीन को किसानों ने खेती के लायक़ बना दिया है. कासा एवं सरकंडों को साफ करके ज़मीन समतल कर दी गई है, जो अब उपजाऊ बन गई है. पूरे इलाक़े में 22 हज़ार किसान उस पर खेती कर रहे हैं. किसानों ने गदावरी पद्धति से इस पर खेती की है और वे सरकार को टैक्स भी देते रहे हैं, लेकिन ब्लॉक एवं तहसील प्रमुख किसानों से चालीस-पचास हज़ार रुपये प्रति एकड़ की मांग करते हैं, जिसके चलते अधिकांश किसान ज़मीन अपने नाम नहीं करा पा रहे हैं. इधर किसानों की फ़सलें नष्ट करने एवं जलाने की घटनाएं आम हो गई हैं. भू-स्वामियों, जिनमें विभिन्न दलों के स्थानीय नेता भी शामिल हैं, की नज़र इस ज़मीन पर है. किसान भी संगठित हैं और विरोध कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बीती 16 फरवरी को किसान नेता साधु सिंह की हत्या कर दी गई. किसानों के अनुसार, इस हत्या में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व विधायक वीर सिंह लोकोके का हाथ है, पर पुलिस लोकोके को निर्दोष करार देने में जुटी है. किसानों द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पूर्व विधायक लोकेके, थानाध्यक्ष कुलविंदर सिंह, रसपाल सिंह एवं सर्वजीत सिंह को अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन इनमें से किसी की गिरफ़्तारी नहीं हुई. जांच दल द्वारा पूछे जाने पर एसपी (ग्रामीण) ने कहा कि लोकेके के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है. पुलिस का रवैया यह है कि किसान कार्यकर्ता सुखसा सिंह की न्यायिक हिरासत में मौत के बाद भी कोई जांच-पड़ताल नहीं की गई. रावी नदी के किनारे स्थित यह ज़मीन अमृतसर, गुरदासपुर एवं तरनतारन आदि ज़िलों में है, लेकिन संघर्ष की शुरुआत अमृतसर के पिंदाऔलख से हुई. यहां काम कर रहे किसान संगठनों का कहना है कि 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की दर किसानों के लिए बहुत ज़्यादा है. ऐसे में सरकार धनराशि कम करे या इसे किस्तों में अदा करने की अनुमति दे. कृति किसान यूनियन के मास्टर मालविंदर सिंह के अनुसार, राज्य सरकार कोई नीति नहीं बना रही है, इससे क्षेत्र में असंतोष फैल रहा है. जांच दल ने छात्रों और छात्र नेताओं से भी संपर्क किया. छात्रों में सरकार और पुलिस को लेकर खासा आक्रोश है. आंदोलन का मुद्दा छात्रों के लिए रियायती पास का है. पंजाब ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन छात्रों को रियायती पास देता है, लेकिन राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन का निजीकरण कर दिया है और निजी बसें छात्रों को पास की अनुमति नहीं दे रही हैं. इसे लेकर मोगा ज़िले के छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था. कई बार प्रशासन के साथ छात्रों की वार्ता भी हुई, पर परिणाम शून्य रहा. उल्टे कई छात्र नेताओं को जेल भेज दिया गया. छात्रों ने बताया कि पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरमुख सिंह मान, लखवीर सिंह, बलजीत सिंह, निर्मल सिंह, हरजिंदर कुमार एवं बलजीत जेल में हैं. पुलिस ने 11 छात्रों के ख़िलाफ़ नामजद एफआईआर दर्ज कर रखी है. आईटीआरई के निजीकरण के ख़िलाफ़ भी छात्र आंदोलित हैं. 30 मार्च को छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज के बाद नौ छात्र नेताओं को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया. विरोधस्वरूप छात्रों ने 26 अप्रैल को पूरे पंजाब में रैली निकाल कर प्रदर्शन किया. राजेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह एवं जसविंदर कौर ने बताया कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुख्यमंत्री बादल के परिवार के पास है. इतना ही नहीं, मोगा स्थित महिला आईटीआई के आधे परिसर में सरकार ने पुलिस लाइन बना दी है, जहां पुलिस ने छात्राओं का पढ़ना-लिखना दूभर कर रखा है. पूरे पंजाब में ख़ास बात यह देखी जा रही है कि किसानों, कर्मचारियों एवं छात्रों की समस्याएं अलग-अलग होने के बावजूद सभी तबके के लोग एकजुट हो रहे हैं. नवां शहर में बिजली कर्मचारियों के समर्थन में वकीलों के संगठन डेमोक्रेटिक लायर्स फोरम, किसान संगठन और छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. बिजली कर्मचारियों के समर्थन में आए छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में उनकी जमकर पिटाई की और कपड़े उतरवा कर अपमानित किया. आईएफटीयू नेता गुरमीत सिंह बखतपुरा पर पुलिस ने जानलेवा हमला किया. बीते 15 मार्च को पुलिस ने रात के वक़्त बखतपुरा के घर पर छापा मारा. उसी दौरान यह 24 वर्षीय नेता दो मंजिला मकान से नीचे गिर गया. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पुलिस ने न तो ख़ुद उन्हें अस्पताल भेजा और न ही जाने दिया, बल्कि उल्टे गुरमीत सिंह को हथकड़ी और लगा दी गई. गुरमीत फाउंडरी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे. सूत्रों का कहना है कि गुरमीत के ख़िलाफ़ यह पुलिसिया कार्रवाई स्थानीय विधायक एवं ट्रांसपोर्टर जगदीश राज साहनी के इशारे पर की गई.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... राठौर, रुचिका और पुलिस ! ...धीर

अव्यवस्था का आलम यह रहा कि ज़िलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी धाम से पांच किलोमीटर पहले ही अपने सरकारी वाहन छोड़कर पैदल चलना पड़ा.

चार धाम यात्रा अव्यवस्था का शिकार

राजकुमार शर्मा

देवभूमि उत्तराखंड में धर्म एवं आस्था की मिसाल पेश कर पर्यटन को एक पहचान देने वाली चार धाम यात्रा सरकारी उपेक्षा और अव्यवस्था की भेंट चढ़ कर राम भरोसे चल रही है. इसमें प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यमुनोत्री–गंगोत्री सहित केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं. अक्षय तृतीया को यमुनोत्री एवं गंगोत्री, 18 मई को भगवान केदारनाथ और 19 मई को भगवान बद्रीनाथ के कपाट परंपरागत तरीक़े से श्रद्धालुओं–भक्तों के लिए खोले गए. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के समक्ष राज्य सरकार की सारी व्यवस्थाएं बौनी सिद्ध हुईं. गंगोत्री धाम में यात्रा के पहले दिन ही पांच किलोमीटर तक लगे जाम ने सरकार के दावे खोखले साबित कर दिए. मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने धाक जमाने के लिए अपने राजनीतिक आका लालकृष्ण आडवाणी को सरकारी कार्यक्रम में आमंत्रित किया. इससे जनता को खासी परेशानी उठानी पड़ी. आडवाणी को पट खुलने के पहले दिन ही गंगोत्री धाम में स्पर्श गंगा अभियान में बुलाया गया. इस निर्णय के चलते राज्य सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई.

अव्यवस्था का आलम यह रहा कि ज़िलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को भी धाम से पांच किलोमीटर पहले ही अपने सरकारी वाहन छोड़कर पैदल चलना पड़ा. महाकुंभ 2010 के बाद सूबे में शुरू हुई चार धाम यात्रा के अवसर पर हज़ारों भक्तों ने पतित पावनी गंगा, कष्टनाशनी यमुना, भगवान केदारनाथ एवं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन परंपरागत ढंग से जयकारे के साथ किए. इस अवसर पर सेना के माहर रेजीमेंट के जवानों द्वारा बैंड पर बजाई गई धुन सुनकर श्रद्धालु झूम उठे. गंगा मंदिर में जलने वाले अखंड दीप का दर्शन करके भक्तों ने ख़ुद में नई ऊर्जा का अनुभव किया. गंगोत्री एवं यमुनोत्री दोनों ही धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं. चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है. इस यात्रा की औपचारिक शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वी सी खंडूरी ने ऋषिकेश से 250 बसों के एक जत्थे को हरी झंडी दिखाकर की थी. यमुनोत्री समुद्र तल से 4421 मीटर और गंगोत्री 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं. इस मौक़े पर गंगा–यमुना एवं बद्री–केदार मंदिरों को फूलों से सजाया गया था.

राज्य सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्था को लेकर लंबे–चौड़े बयान दिए थे. मुख्यमंत्री निशंक ने पत्रकार वार्ता में सुव्यवस्था की बात कही थी, जो जनता को कहीं दिखाई नहीं दी. एक दिन बाद गंगोत्री में होने वाले गंगा स्पर्श कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को शामिल होना था. इसी वजह से राज्य के अनेक नेताओं ने भी यात्रा शुरू होने से पहले ही गंगोत्री में डेरा डाल दिया. नतीजतन प्रशासन वीआईपी सुरक्षा में ही व्यस्त हो गया. यात्रियों की अनदेखी करते हुए गंगोत्री धाम को पुलिस छावनी में बदल डाला गया. लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहे. ज़रूरत से ज़्यादा पुलिस बल की मौजूदगी ने जनता को निराश किया. आडवाणी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ख़ुश रखने की हरसंभव कोशिश करने वाली निशंक सरकार की श्रद्धालुओं के मध्य जमकर किरकिरी हुई. यात्रा के पहले दिन ही आडवाणी के गंगोत्री धाम पहुंचने के कारण हज़ारों यात्रियों को बह्मखाल, धरासू, डूंडा, मातली बड़ेथी, उत्तरकाशी, नेथाला, मनेरी, भटवाड़ी, डबराणी एवं हर्शिल में पुलिस ने रोक दिया. पूरे पहाड़ी मार्ग में यात्रियों को 12 से 20 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा. यात्रा मार्ग में दुकानदारों ने मौक़े का लाभ उठाकर यात्रियों से मनमाने दाम वसूले. सैकड़ों यात्रियों को अपने वाहनों में ही भूखे–प्यासे रहकर रात गुज़ारनी पड़ी. हज़ारों तीर्थ यात्रियों के लिए आडवाणी की यात्रा पूरी तरह से जी का जंजाल सिद्ध हुई. इस सरकारी आयोजन ने यात्रा के पहले दिन ही होटल, घोड़ा, कंडी, पालकी, पिट्ठू वालों को चांदी काटने का मौक़ा उपलब्ध करा दिया. इन लोगों ने जनता से पांच से दस गुना किराया वसूल किया. हज़ारों तीर्थ यात्रियों को गंगोत्री–यमुनोत्री की यात्रा मध्य में ही छोड़कर आगे का रुख़ करना पड़ा.

पहले ही चरण में दो–तीन दिनों तक गंगोत्री से यमुनोत्री तक की यात्रा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त रही. सरकारी अव्यवस्था ने यात्रियों का उत्साह ठंडा कर दिया. बदहाल सड़कें भी यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनीं. उत्तरकाशी से गंगोत्री तक 20 किलोमीटर सड़क की हालत इतनी खस्ता है कि वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है. सरकार ने जगह–जगह सड़क चौड़ीकरण का बोर्ड लगा रखा है. गंगोत्री के यात्रा मार्ग में बदहाल एवं धूल भरी सड़कों से गुज़रने में यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है. पदयात्रा करके धाम तक पहुंचने का संकल्प करने वाले यात्रियों का और भी बुरा हाल हो रहा है. यमुनोत्री के पैदल मार्ग में जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक प्रबंधन की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. चार धाम यात्रा समिति द्वारा यात्रियों को सुविधा देने की घोषणा हवा हवाई सिद्ध हो रही है. यात्रा मार्ग में जगह–जगह लगे पायलट बाबा एवं समिति के अध्यक्ष सूरतराम नौटियाल के बोर्ड के प्रति जनता में इतना आक्रोश है कि कई जगह यात्रियों ने दोनों के चित्रों पर पत्थर मार कर उन्हें बदरंग बना दिया.

केदारनाथ मार्ग पर स्थित यात्री विश्रामगृहों की हालत पूरी तरह खस्ता है. भगवान बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को कुछ दूर तक चौड़ी सड़कें ज़रूर मिल रही हैं, किंतु जोशीमठ के बाद धाम तक सड़कों की बदहाली ने उनमें भय पैदा कर दिया है. मार्ग में कई जगहों पर यात्री विश्रामगृह का निर्माण तो किया गया है, किंतु उन पर कहीं वन विभाग तो कहीं दबंगों का क़ब्ज़ा है. यात्रा की दुर्गमता हर बार यात्रियों में रोमांच पैदा करती थी, लेकिन इस बार वह धर्म एवं संस्कृति के नाम पर बनी सूबे की सरकार के प्रति नफ़रत पैदा कर रही है. बद्रीनाथ धाम में यात्रियों के लिए बनाया गया यात्री शेड पूरी तरह उजड़ चुका है. यात्रा के पहले दिन ही बद्रीनाथ धाम में हुई बारिश एवं बर्फबारी से सैकड़ों यात्री तंग हो गए. यात्रियों के लिए तैनात प्रशासनिक अमले का काम मात्र रसूखदारों को सुविधा प्रदान करना और लाइन में लगी जनता के लिए परेशानी खड़ा करना रह गया है. वीआईपी के आगे यात्रियों की कोई गिनती नहीं है. बद्रीनाथ धाम में तैनात सेना के जवान भी अपने अफसरों के परिवारों की सेवा में लगे हैं. स्थानीय लोगों एवं प्रशासन का एक ही मक़सद है कि छह माह तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान ही बारह माह की मोटी कमाई का जुगाड़ कर लिया जाए.

मुख्यमंत्री निशंक ने जनता को नकार कर अपने आका की मुक्ति का जो रास्ता यात्रा के पहले दिन ही तलाशा, उससे इस यात्रा के प्रति सरकार का रवैया स्पष्ट हो गया. प्रदेश के अति महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ की सनातन पीठ पर तीन–तीन शंकराचार्यों की दावेदारी जनहित को भुलाकर अपना हित साधने में लगी है. देवभूमि के जोशीमठ स्थित ज्योर्तिपीठ पर भारी मठ बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले स्वरूपानंद, वासुदेवानंद एवं माधवाश्रम महाराज का पीठ के स्वामित्व को लेकर आपस में ही लड़ना सनातन धर्म की अवधारणा को चोटिल कर रहा है. आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के चारों कोनों में चार पीठों की स्थापना करके सनातन धर्म की रक्षा एवं एकता का जो सपना देखा था, वह भी इन तीन दावेदारों की नासमझी के कारण तार–तार हो रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन वीआईपी सुरक्षा में ही व्यस्त हो गया. यात्रियों की अनदेखी करते हुए गंगोत्री धाम को पुलिस छावनी में बदल डाला गया. लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहे. पुलिस जनता को निराश किया. आडवाणी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ख़ुश रखने की हरसंभव कोशिश करने वाली निशंक सरकार की श्रद्धालुओं के मध्य जमकर किरकिरी हुई.

ऐसा भी क्या डर था, जिसने दिल्ली सरकार को अफजल की फांसी की सज़ा को अधर में लटकाने पर मजबूर किया?

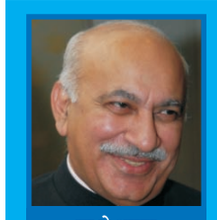

एम जे अकबर

क्या मीडिया सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ताक़तवर है?

सर्वोच्च न्यायालय अपने नाम, जो इसे सर्वोच्च बताता है, के मुक़ाबले कम ही सर्वोच्च है. यह फांसी की सजा तो सुना सकता है, लेकिन ख़ुद फांसी नहीं दे सकता. सरकार अदालत के आदेश को न मानने की हिम्मत तो नहीं करती, लेकिन सरकार के पास उसे उलटने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है. यही कारण है कि अफजल गुरु का मामला अब तक लटका हुआ है. इस तरह के मामले को लटकाने के लिए चाल धीमी कर देना एक बेहतरीन उपाय है. अफजल मामले में भी ऐसा ही हुआ. चार साल में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को एक औपचारिक पत्र और 15 स्मरण पत्र भेजे, ताकि वह अफजल की दया याचिका पर अपनी राय देकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल के पास भेज सके. निश्चित तौर पर पत्र भेजने का यह खेल सरकारी काहिली नहीं, बल्कि ब्लैकमेलिंग का खेल है.

ऐसा भी क्या डर था, जिसने दिल्ली सरकार को अफजल की फांसी की सजा को अधर में लटकाने पर मजबूर किया? जैसा कि अक्सर होता है कि ग़लती से कोई आदमी एक ऐसा सुराग़ दे देता है, जिससे आपके सवालों का जवाब मिल जाता है. 18 मई को जब दिल्ली सरकार ने इस मामले पर चार साल की देरी के बाद कार्रवाई शुरू की, तब इसके एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि अफजल गुरु को फांसी देने से दिल्ली सरकार को कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर फांसी की सजा दी जाती है तो ऐसे हालात के लिए क़ानून व्यवस्था की समीक्षा केंद्र सरकार को ज़रूर कर लेनी चाहिए. अब इस तर्क का क्या अर्थ है?

क्या वह अधिकारी यह बताना चाहता था कि अफजल गुरु को फांसी देने से दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर आएगी, सार्वजनिक संपत्ति को नुक़सान पहुंचाएगी और राजधानी ठहर सी जाएगी, क्योंकि वह एक आतंकवादी को फांसी देने से गुस्से में थी. या फिर वह अधिकारी ऐसा मानता था कि ऐसी स्थिति में अफजल के आतंकी साथी कोई बड़ा हमला कर देंगे. आतंकवादी किसी फाइल की धीमी चाल या अफजल के जीवन या मौत का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. ये बातें उन आतंकियों और उनके नापाक इरादों के लिए मायने नहीं रखतीं. इस गर्मी में भी पाक अधिकृत कश्मीर से घुसपैठ की

ख़बरें आ ही रही हैं. आएदिन कश्मीर में सेना के साथ मुठभेड़ हो ही रही है. कांबिंग ऑपरेशन के दौरान कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है.

फिर ऐसी क्या बात है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार के यह अधिकारी इतने चिंतित थे? क्या वह केंद्र सरकार को इस बात की चेतावनी दे रहा था कि फांसी देने से भारत के मुसलमान भड़क उठेंगे और हिंसा के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देंगे और सर्वशक्तिमान भारत की सरकार को भयभीत कर देंगे. चिदंबरम पिछले 18 महीनों में, जबसे वह गृहमंत्री हैं, जब भी चाहते अफजल की फाइल पर कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मानों दिल्ली की सरकार पाकिस्तान में बसी हो और अफजल मामले पर नियमित रूप से उसे डोजियर भेजा जाए. चिदंबरम ने इस मसले पर इसलिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वह कुछ करना ही नहीं चाहते थे. चार सालों तक कुछ भी नहीं हुआ.

यह सिर्फ़ वक़्त की बात थी. जब सूचना का अधिकार क़ानून के तहत किसी ने अफजल की दया याचिका मामले से संबंधित जानकारी निकाल ली और यह मामला लोगों के बीच आ गया. जब यह दस्तावेज़ एक टीवी चैनल के हाथ लगा तो ज़ाहिर है यह ख़बर आई कि राजनीतिक वजहों से अफजल मामले को लंबा खींचा जा रहा है. जब आम लोगों के बीच यह मामला गरमाने लगा और सरकार को उकसाया गया, तब जाकर सालों से सुस्त पड़ी फाइल सरकने लगी.

सरकार जिसे चाहेगी, उसे बचाएगी और जिसे चाहे सजा दे सकती है. हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है. उसने 1984 के सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को 25 सालों से बचा रखा है. सीबीआई ने कहा कि आरोप तय करते समय धारा 499 की जगह 399 लगा दी गई. आख़िर वे सारे पुरस्कार विजेता मानवाधिकारवादी कहां हैं, जो दंगों के आरोपियों को ढूंढते फिरते हैं? शायद वे लोग अब 1984 की 30वीं वर्षगांठ पर मिलेंगे.

हम लोगों के पास एक क़ानून है, जो कम उम्र के बच्चों को जेल भेजने से रोकता है. 2014 तक एक ऐसा क़ानून होना चाहिए, जिससे एक ऐसा आदमी, जिसकी उम्र रिटायरमेंट की उम्र से ज़्यादा हो और अगर कोई सज़ा मिले तो उसे जेल न जाना पड़े, बल्कि अपने एसी कमरे में ही रहकर अपनी सजा गुज़ार दे. इससे सज्जन कुमार को काफी फ़ायदा होगा, अगर तब तक ईश्वर अपना निर्णय नहीं सुना देता. और जब तक मीडिया हस्तक्षेप नहीं करता, सज्जन कुमार के मामले में भी बहुत देर हो सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

एचआईवी संक्रमण : बीमारी से ज़्यादा अभिशाप

एचआईवी संक्रमित लोगों के प्रति अलग नज़रिया और सामाजिक स्तर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार कोई नई बात नहीं है. यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है. इस जानलेवा बीमारी को अभिशाप की नज़रों से देखने से न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि इससे पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का भी उल्लंघन होता है. बावजूद इसके ताज्जुब की बात तो यह है कि एचआईवी से मुक़ाबले के लिए बनी राष्ट्रीय योजनाओं में इस पहलू को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है.

राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों के अंतर्गत इस दिशा में विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है. यदि सभी संबद्ध पक्ष मिलकर मज़बूती से इसके लिए क़दम उठाएं तो इस रोग की रोकथाम, सही इलाज, मरीजों की देखभाल और उन्हें मदद पहुंचाने का लक्ष्य वास्तविक रूप में हासिल किया जा सकता है. इस काम में संयुक्त राष्ट्र संघ, धन मुहैया कराने वाली संस्थाओं और अन्य सहयोगी निकायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. उक्त सारी ताक़तें विभिन्न देशों को नीति निर्माण, तकनीक, संसाधनों की पहचान और अन्य तरीक़ों से मदद पहुंचा कर एचआईवी से जुड़े कलंक एवं भेदभाव को कम करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इन प्रयासों से न केवल विभिन्न देश मिलेनियम डेवलपमेंट गोल–6 का वैश्विक लक्ष्य हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं, बल्कि मानवाधिकारों की रक्षा भी होगी, एचआईवी पीड़ित लोगों को समाज में इज़्ज़त के साथ रहने का मौक़ा मिल सकेगा और एचआईवी संक्रमण को नियंत्रित करने में भी सफलता हासिल होगी.

राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों के अंतर्गत इस दिशा में विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है. यदि सभी संबद्ध पक्ष मिलकर मज़बूती से इसके लिए क़दम उठाएं तो इस रोग की रोकथाम, सही इलाज, मरीज़ों की देखभाल और उन्हें मदद पहुंचाने का लक्ष्य वास्तविक रूप में हासिल किया जा सकता है. इस काम में संयुक्त राष्ट्र संघ, धन मुहैया कराने वाली संस्थाओं और अन्य सहयोगी निकायों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है.

इसके लिए पहली आवश्यकता यह है कि एचआईवी के साथ जुड़े अभिशाप और पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव के स्वरूप को समझा जाए. इसकी वजहों की पहचान की जाए और एचआईवी से मुक़ाबले के लिए चलाए जा रहे अभियान पर इसके पड़ने वाले असर को वास्तविक धरातल पर समझने की कोशिश की जाए. संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को इसके लिए नेतृत्वकारी भूमिका में आने की ज़रूरत है. उसे विभिन्न देशों को यह समझाना होगा कि वे अपने राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों में इसकी महत्ता को समझते हुए इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताएं और इसे दूर करने की दिशा में व्यापक प्रयास करें. यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि नज़रिए में बदलाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार को कम करना राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रमों के लक्ष्यों में शामिल हो. कार्यक्रमों की योजना बनाते समय ही इसके लिए अलग से रणनीति बनाई जाए और धनराशि की व्यवस्था की जाए. योजनाओं के लिए नीति निर्माण के स्तर पर ही इस अभिशाप की वजहों की पहचान करनी होगी, जैसे इसके प्रति लोगों में जागरूकता की कमी एवं विपरीत परिणाम, समाज में फैला यह डर कि साधारण संपर्क से भी एचआईवी का संक्रमण होता है और एचआईवी को आमतौर पर अनैतिक व्यवहार के साथ जोड़ कर देखने की आदत आदि. समाज में व्याप्त इन धारणाओं को दूर करने के लिए बहुआयामी रवैया अपनाना होगा. इनके ख़िलाफ़ विभिन्न स्तरों पर एक साथ प्रयास करने होंगे, तभी वांछित परिणाम हासिल हो सकते हैं. नो योर राइट्स अभियान जैसे कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक बदलाव के लिए संवाद को बढ़ावा देना होगा और आम लोगों को इसके पक्ष में लामबंद करना होगा. सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देकर एचआईवी संक्रमित लोगों के साथ मेलजोल के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है. मीडिया में इसके ख़िलाफ़ अभियान चलाने, मशहूर शख्सियतों को जोड़ने और पीड़ित लोगों के लिए क़ानूनी मदद की व्यवस्था करने से एचआईवी के प्रति लोगों के नज़रिए में बदलाव संभव हो सकता है. लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त सभी उपाय हर देश में एक समान रूप से सफल नहीं हो सकते. विभिन्न देशों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल रवैये के चुनाव में काफी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है. हर देश को अपने राष्ट्रीय एड्स निरोधी अभियान में इन उपायों को इस तरह जगह देनी होगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल हो सके. लेकिन कार्यक्रमों के चुनाव और उन्हें लागू करने भर से उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं किया जा सकता. इसके लिए आवश्यक है कि कार्यक्रमों की प्रभावशीलता के आकलन के लिए भी उचित व्यवस्था हो. यह व्यवस्था कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय ही करनी होगी. इसका फ़ायदा यह है कि एक निश्चित समय सीमा के बाद अभियान की कामयाबी–नाकामयाबी का मूल्यांकन कर उसमें तदनुरूप बदलाव किए जा सकते हैं एवं उन्हें और ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय एवं सभी देशों के राष्ट्रीय एड्स निरोधी अभियानों में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि साल 2010 तक एचआईवी की रोकथाम, इलाज, देखभाल और मदद के कार्यक्रम विश्व के हर कोने तक पहुंच जाएंगे. लेकिन यह लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है, जबकि सभी देश इस मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर करें. 1980 के दशक के अंत से लेकर 2005–06 में इस वैश्विक लक्ष्य को अपनाए जाने तक तमाम विशेषज्ञों एवं इस क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ताओं ने बार–बार कहा है कि एचआईवी से मुक़ाबले में सबसे बड़ी बाधा उससे जुड़ी अभिशाप की भावना और पीड़ित लोगों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार ही है. पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर फैल चुकी यह समस्या समाज के विभिन्न स्तरों पर अलग–अलग रूपों में विद्यमान है. एचआईवी पीड़ित लोगों के ख़िलाफ़ ऐसी भावना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामुदायिक, संस्थागत, मीडिया और यहां तक कि सरकारी नीतियों और व्यवहार के स्तर पर भी देखने को मिलती है. हालांकि सभी राष्ट्र इसकी व्यापक मौजूदगी और इसके कुप्रभावों से अच्छी तरह वाक़िफ़ हैं और इसे स्वीकार भी करते हैं, लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इसके बावजूद शायद ही किसी देश ने इसे दूर या कम करने के लिए अपने कार्यक्रमों में अपेक्षित फेरबदल किया हो. सच्चाई तो यह है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम में इसे प्राथमिकता के आधार पर उद्देश्य के रूप में नहीं अपनाया गया है. जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक एचआईवी की रोकथाम, इलाज, देखभाल और सहायता का वैश्विक लक्ष्य हासिल करना दूर की कौड़ी साबित होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

बेकारी की समस्या

पूरे विश्व में शोर है कि मंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन तमाम योजनाओं के बावजूद हमारे देश में बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है. रूबी अरुण का आलेख–प्रधानमंत्री नहीं जानते, देश में कितने बेरोज़गार इसी सच्चाई पर रोशनी डालता है. लेख बताता है कि सरकार इस गंभीर मसले पर किस कदर उदासीन है और सिर्फ़ जनता को बहलाने–फुसलाने का काम चल रहा है. हक़ीक़त में बेकारी से निबटने के कोई इंतज़ाम नहीं किए जा रहे.

–अश्विनी कुमार, *जैसलमेर, राजस्थान.*

मामलों पर गंभीर नज़र

चौथी दुनिया मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं. मुझे यह बहुत अच्छा लगता है. आप हर अंक में एक ख़ास विषय पर चर्चा करते हैं. आज जबकि दूसरे तमाम पत्र–पत्रिकाएं समाज की रंगीनियों को छापने की होड़ में हैं तो चौथी दुनिया समाज एवं आम आदमी से जुड़े किसी गंभीर विषय पर पहल करता है और पाठकों के बीच सवाल छोड़ देता है. सवाल छोड़ने की वजह से लोगों को यह अच्छा लगता है.

–रमेश चंद्र, *रोहतक, हरियाणा.*

और जनपयोगी बनाएं

मैंने पहली बार 3 मई–9 मई का चौथी दुनिया पढ़ा. मन प्रसन्नता से भर गया. इस अख़बार में वर्तमान स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है. बच्चों की कहानियां, घर–परिवार और स्वास्थ्य से संबंधित आलेख–परिचर्चाएं आदि प्रकाशित करके इसे और भी जनोपयोगी बनाया जा सकता है.

–आनंद मोहन रिछारिया, *सागर, मध्य प्रदेश.*

अख़बार क़ाबिले तारीफ़

चौथी दुनिया मैंने पहली बार चेन्नई में देखा और पढ़ा. यह समाचारपत्र पत्रकारिता धर्म का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है. इसमें प्रकाशित लेख पठनीय एवं सराहनीय हैं. इनका मक़सद समाज को आईना दिखाना है. ये प्रत्येक राष्ट्रभक्त नागरिक की आंखें खोलते हैं. संपादक को ऐसे लेख प्रकाशित करने के लिए बधाई.

–डॉ. पी आर वासुदेवन शेष, *चेन्नई.*

किसान–मज़दूरों को आपस में लड़ाने की साजिश

हमारे देश की संसद एवं विधानसभाओं में बटाईदारी मसले पर लंबी–चौड़ी बातें होती हैं, लेकिन फिर यह सवाल ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है. राज्य सरकार ईमानदारी से बटाईदारी बिल पर काम करने को तैयार नहीं है. चौथी दुनिया के 10 मई के अंक में बिहार में इसकी स्थिति का सही आकलन किया गया है कि यह एक चुनावी हवा है और कुछ नहीं. सरकार भूमि सुधार के लिए गठित बंदोपाध्याय समिति की अनुशंसा को भी नहीं मानती. छोटे किसान भी अपना खेत बटाई पर देकर बाहर मज़दूरी के लिए चले जाते हैं. इस बिल के संबंध में ज़मीन की सीमा भी स्पष्ट होनी चाहिए.

–शंकर शर्मा, *बेगूसराय, बिहार.*

बड़े पत्रकार, बड़े दलाल

हाल में आपके अख़बार में छपा आलेख–बड़े पत्रकार, बड़े दलाल पढ़ा. सारी बातें सच लिखी गई हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है. इस पेशे में दलाली बहुत अंदर तक घुस चुकी है. मैं इसकी वजह किसी हद तक प्रबंधन को मानता हूं. अगर आप बहुत छोटे स्तर पर देखें तो कई चैनलों के ऐसे स्ट्रिंगर मिल जाएंगे, जिन्हें चैनल वाले एक पैसा नहीं देते. एक ने स्ट्रिंगर ने मुझे बताया कि उससे कहा गया कि तुम्हें आईडी दे दी गई है, अब तुम ख़ुद कमाओ और हो सके तो चैनल को भी कुछ बिजनेस दो. वरना ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाओगे. जब यह दशा होगी तो दलाली होना तय है. हालांकि मैं यह कहकर दलाली की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो रहा है.

–विवेक वाजपेयी, *एस–वन न्यूज़, नोएडा.*

नींद में विपक्ष

24–30 मई की आवरण कथा–विपक्ष सो रहा है, समसामयिक विषय पर एक सशक्त लेखन है. वास्तव में किसी प्रजातांत्रिक देश को एक ऐसे विपक्ष की ज़रूरत होती है, जो सत्तापक्ष की ग़लतियों–कमज़ोरियों की ओर इशारा कर सके. अफसोस कि हमारे देश का मौजूदा विपक्ष अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रहा है. यही वजह है कि हर तरफ़ समस्याओं की भरमार होने के बावजूद कहीं से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही.

–राजेंद्र मिश्र, *रायबरेली, उत्तर प्रदेश.*

ग़रीबों की क़िस्मत

24–30 मई का अंक मिला. आलेख–रोटी के नाम पर धोखा पढ़कर मालूम हुआ कि ग़रीबों के नाम पर बनाई–चलाई जाने वाली योजनाओं में कितना घालमेल चल रहा है. देश को आज़ादी हासिल हुए छह दशक से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन ग़रीबों के हिस्से में सिरिफ़ बदहाली–बेबसी ही आ रही है. समझ में नहीं आता कि हमारे अगुवा सही दिशा में सोचना–चलना आख़िर कब शुरू करेंगे.

–रजनीकांत पांडेय, *ईमेल से.*

मुइवा की जिद और केंद्र सरकार

आलेख–मुइवा, मणिपुर और केंद्र की दोहरी नीति पढ़ा. लेखक ने विषय पर बड़ी बेबाकी से रोशनी डाली है. मुइवा की मणिपुर जाने की जिद ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया. जब उनका आना मणिपुर के हित में नहीं है अथवा उनके आगमन से क्षेत्र का अमन–चैन प्रभावित हो सकता है, यह जानने के बाद तो केंद्र को उनके दौरे का समर्थन कतई नहीं करना चाहिए. साथ मुइवा को भी इस तरह की जिद नहीं करनी चाहिए.

–विलास ठाकुर, *जनकपुरी, नई दिल्ली.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

प्याज़ भी खाए और जूते भी

विनम्रता से अपनी बात एक कहावत से शुरू करना चाहते हैं. कहावत है कि प्याज़ भी खाया और जूते भी खाए. आप में से बहुत से इसके पीछे की कहानी से परिचित होंगे, फिर भी हम उनके लिए लिख रहे हैं, जो इस कहावत की उत्पत्ति नहीं जानते. किसी बड़ी ग़लती पर बादशाह ने सज़ा सुनाई कि ग़लती करने वाला या तो सौ प्याज़ खाए या सौ जूते. सज़ा चुनने का अवसर उसने ग़लती करने वाले को दिया. ग़लती करने वाले शख़्स ने सोचा कि प्याज़ खाना ज़्यादा आसान है, अत: उसने सौ प्याज़ खाने की सज़ा चुनी. उसने जैसे ही दस प्याज़ खाए, वैसे ही उसे लगा कि जूते खाना आसान है तो उसने कहा कि उसे जूते मारे जाएं. दस जूते खाते ही उसे लगा कि प्याज़ खाना आसान है, अत: उसने फिर प्याज़ खाने की सजा चुनी. दस प्याज़ खाने के बाद फिर उसने कहा कि उसे जूते मारे जाएं. फ़ैसला न कर पाने की वजह से उसने सौ प्याज़ भी खाए और सौ जूते भी. यहीं से इस कहावत का प्रचलन प्रारंभ हुआ. आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कह सकते हैं कि झारखंड में उसने सौ जूते भी खाए और सौ प्याज़ भी.

लालकृष्ण आडवाणी के भाजपा का नेता रहते यह हुआ. अगर उनसे चूक हुई तो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली क्या कर रहे थे. राजनाथ सिंह तो भाजपा के अध्यक्ष रह चुके थे और झारखंड मामलों के मुखिया थे. सुषमा स्वराज ने जगजीवन राम और जार्ज फर्नांडिस के सानिध्य में राजनीति सीखी और फिर भाजपा में गईं तथा अपनी बोलने की ताक़तवर शैली और कुशलता की वजह से आज संसद में विपक्ष की नेता हैं. अरुण जेटली छात्र आंदोलन में तो प्रखर थे ही, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, अपने तर्कों से अक्सर हारी बाज़ी जीत लेते हैं, चाहे बाज़ी ग़लत ही क्यों न हो. जब झारखंड में फ़ैसला हो गया कि समर्थन वापस लेना है तो उसे क्यों रोकने में इन्होंने साथ दिया. राजनाथ सिंह के घर, बाहर, रांची में हर जगह भाजपा नेता बैठे और कैसे उनका मुख्यमंत्री बने, इसके लिए सारी कुशलता ख़र्च कर दी.

क्यों मुख्यमंत्री पद चाहती थी भाजपा, इसका जवाब तलाशना चाहिए. अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते मधु कोड़ा ने जिस तरह संपत्ति इकट्ठी की, वह भारत की राजनीति के निम्नतम उदाहरणों में से एक है. लक्ष्मी मित्तल के प्रतिनिधि के रूप में मधु कोड़ा काम कर रहे थे और उसकी क़ीमत वसूल कर रहे थे. लक्ष्मी मित्तल के लोग ही मधु कोड़ा को मिलने वाले पैसे को दक्षिण एशियाई देशों में लगा रहे थे. क्या अर्जुन मुंडा भी इसी श्रेणी में हैं और मित्तल के वित्तीय हितों की देखभाल के लिए किसी भी क़ीमत पर भाजपा का, वह भी वह ख़ुद मुख्यमंत्री बनें, यह चाहते थे? सारी ताक़त इसी बात के लिए ख़र्च हुई कि किसी भी तरह भाजपा की सरकार बन जाए. इसके पीछे कोई भाजपा का या संघ का सिद्धांत नहीं था, हिंदू या राज्य की जनता का हित नहीं था, क्योंकि अगर होता तो शिबू सोरेन के खेद प्रकट करने के बाद सरकार चलने देनी चाहिए थी. लेकिन अगर उन्होंने खेद प्रकाश स्वीकार नहीं किया और सरकार गिराने का फ़ैसला किया तो सरकार गिरानी चाहिए थी या समर्थन वापस करना चाहिए था. फ़ैसला लेने के बाद पलटने के पीछे एक ही सिद्धांत रहा और वह था वित्तीय सिद्धांत.

यशवंत सिन्हा और रघुबर दास भी मुख्यमंत्री पद की होड़ में थे और जब यह तय हो गया कि अर्जुन मुंडा भाजपा के उम्मीदवार होंगे, तभी ये दोनों ख़ामोश हुए. कम से कम यशवंत सिन्हा को तो अपने को इस भोंडे नाटक से अलग रखना चाहिए था, पर मुख्यमंत्री पद की धूमिल आशा ने उन्हें भी हास्यास्पद बना दिया. कहां गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राजनैतिक शुचिता का सिद्धांत. उन्होंने तो नितिन गडकरी को इसलिए अध्यक्ष बनवाया था कि भाजपा को उस चेहरे की पहचान फिर से मिल जाएगी, जो ग़ायब हो गई है. संघ का मानना था कि आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने की लालसा ने भाजपा को उसके मूल सिद्धांतों से दूर कर दिया है. इसीलिए मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता और संघ की नीतियों के पैरोकार को बेरहमी से किनारे लगा दिया गया. कौन सा नया चेहरा सामने आया भाजपा का, उसका एक ही नाम है, जिसे कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की धुंधली कुर्सी पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार चेहरा. अर्जुन मुंडा तो अपने लिए शिबू सोरेन को मनाने के लिए उनके घर तक गए और वापस आकर कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ़ उनके नाम पर पद त्याग कर सकते हैं. लंदन में बैठे स्टील किंग के अरबों रुपये के दबाव और भाजपा के कुर्सी लेने के दांव को किसने विफल कर दिया? केवल और केवल शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने. दोनों को राजनीति के जोड़तोड़ का बहुत पता नहीं है, पर दोनों ने जिस तरह पूरी भाजपा को मूर्ख बनाया, वह समझने लायक़ है. इनके सामने आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू पानी मांग गए.

कांग्रेस ने थोड़ी समझदारी दिखाई और अपने को इस कवायद से अलग रखा. सुबोधकांत सहाय मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर वह शिबू सोरेन को भी जानते थे. कांग्रेस ने भाजपा को पूरी तरह सिद्धांत छोड़ कुर्सी के लिए सब कुछ करने के लिए खुला मैदान देने का फ़ैसला कर लिया. सवाल भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी का है. उनके भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला संकट भाजपा के सामने आया और उसी में वह असफल हो गए. बीच में ही पार्टी को संकट में छोड़ वह नीदरलैंड के शहर एम्सटरडम चले गए. जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता संकट के समय मैदान में नेतृत्व के लिए खड़ा न हो, वह पार्टी इसी गति को प्राप्त होती है. इसे गडकरी नहीं समझते, बल्कि उनकी पार्टी के कुछ नेता ज़रूर समझते होंगे. सारे संकट में आडवाणी का चुप रहना और कोई दख़ल न डालना भी आश्चर्य पैदा करता है. पर इस सारी जंग में झारखंड कहां है. एक ऐसा प्रदेश, जिसमें खनिज पदार्थों का अकूत ख़ज़ाना है, जिसे बेच कर देसी और विदेशी खरबपति हो रहे हैं, वहां लोगों की बड़ी आबादी के पास न काम है और न दोनों वक़्त की रोटी. बुनियादी सुविधाओं का पूर्णत: अभाव है. विकास के नाम पर दिनोंदिन पिछड़ापन बढ़ रहा है. सड़क, अस्पताल, स्कूल की तलाश का काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके लिए कोई प्रतिबद्ध ही नहीं है. आदिवासी बद से बदतर होते जा रहे हैं.

क्यों मुख्यमंत्री पद चाहती थी भाजपा, इसका जवाब तलाशना चाहिए. अर्जुन मुंडा के मुख्यमंत्री रहते मधु कोड़ा ने जिस तरह संपत्ति इकट्ठी की, वह भारत की राजनीति के निम्नतम उदाहरणों में से एक है. लक्ष्मी मित्तल के प्रतिनिधि के रूप में मधु कोड़ा काम कर रहे थे और उसकी क़ीमत वसूल कर रहे थे. लक्ष्मी मित्तल के लोग ही मधु कोड़ा को मिलने वाले पैसे को दक्षिण एशियाई देशों में लगा रहे थे.

झारखंड के लोगों के ग़रीब तबके ने नक्सलवाद को समर्थन देना शुरू कर दिया है. एक ओर उड़ीसा, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ और तीसरी ओर बिहार, बंगाल. झारखंड की यह पट्टी सुरक्षित और मुक्त क्षेत्र में बदल गई है. अब नक्सलवादियों का हमला बड़े ज़मींदारों पर नहीं हो रहा, बल्कि सरकारी संपत्ति पर हो रहा है. सरकारी संपत्ति का सबसे आसान मतलब रेलवे लाइन है. लाखों किलोमीटर फैली रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए हर क़दम पर सुरक्षाबल खड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे उपलब्ध ही नहीं हैं. इसका निशाना मासूम यात्री बनते हैं. लेकिन इनकी सुरक्षा ग़रीबों को अपना दुश्मन मान कर नहीं की जा सकती. उनकी समस्याओं और उनकी मांगों को समझना होगा. पश्चिमी मिदनापुर में हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर हुई, गृह मंत्रालय ने कहा कि फिश प्लेट उखाड़ने से हादसा हुआ, वहीं रेल मंत्रालय ने कहा कि बम का धमाका हुआ, जिससे दुर्घटना हुई. दोनों मंत्रालय ही एक नहीं हैं. वहीं टेलीविज़न चैनलों ने चिल्लाना शुरू किया कि यह नक्सलवाद नहीं, आतंकवाद है. मारो, नक्सलवादियों को मारो. ग़ैर ज़िम्मेदार टेलीविज़न चैनलों को पता ही नहीं कि अपने लोगों को दुश्मन मान किसी भी चीज़ की हिफ़ाज़त नहीं हो सकती.

चिदंबरम के लिए क़ानून व्यवस्था का मसला है और वह तोप और तलवार लिए खड़े हैं, पर जिस राज्य सरकार को लड़ना है, वह कुछ करना ही नहीं चाहती. उसका सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था लागू करने वाला तंत्र जंग खा चुका है तथा विकास का काम करने वाला विभाग दम तोड़ रहा है. और इस प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए दल लड़ रहे हैं, ताकि लंदन में बैठे खरबपति स्टील किंग की दलाली कर अपने लिए विदेशी बैंकों में करोड़ों रुपये जमा करा सकें. झारखंड एक ऐसा आईना है, जिसमें सबका चेहरा जैसा है, वैसा ही दिखाई दे रहा है.

संपादक

editor@chauthiduniya.com

आतंकवाद : वास्तविकता को पहचानने की ज़रूरत

सैन्य अभियान समस्या का कोई समाधान नहीं है. इस मुद्दे के साथ कई पहलू जुड़े हैं, जिनके लिए एक बहुआयामी नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है. यह मुद्दा धार्मिक तो है ही, इसके साथ-साथ राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक भी है. आवश्यकता इस बात की है कि एक बहुआयामी राजनीतिक और समझौतावादी रुख़ के साथ ही इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की जाए. तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अफ़ग़ान तालिबान द्वारा लड़ाई के एक तरीक़े के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली आत्मघाती विस्फोटों की पद्धति की शिक्षा उन्हें अलक़ायदा से मिली थी. अफ़ग़ान तालिबान पहले वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल के सख़्त ख़िलाफ़ था, लेकिन अपने संदेशों को सुदूर इलाक़ों में पहुंचाने के लिए वह अब इसे एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में देखता है. इसी तरह मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के लिए इंटरनेट भी एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है. इसकी शुरुआत भी अलक़ायदा ने ही की थी. हर जगह सबसे आगे अलक़ायदा ही है. इस तरह अलक़ायदा की अनदेखी कर हम न तो समझौते के बारे में सोच सकते हैं, न ही आतंकवाद के मुद्दे को सुलझा सकते हैं.

एक ही पार्टी के लोग किसी एक मुद्दे पर अलग-अलग तरीक़े से सोच सकते हैं. हम यदि इस तथ्य की सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के ऐताज हसन और बाबर अवन द्वारा अपनाई गई नीतियों की ओर देखना चाहिए. यही अंतर मुल्ला उमर, हकीमुल्लाह महसूद और ओसामा बिन लादेन की रणनीतियों में भी नज़र आता है. राष्ट्रीय स्तर की हर

लंबे समय से चल रही अशांति और अस्थिरता के दौर ने इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच छुप-छुपकर लड़ी जा रही लड़ाई के मैदान में तब्दील कर दिया है. डूरंड रेखा के दोनों ओर सरकार का कोई ज़ोर नहीं चलता, बल्कि अलग-अलग देशों की ख़ुफ़िया सेवाओं की गतिविधियां अपने चरम पर हैं. कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, यह जानना बेहद मुश्किल है. पाकिस्तान के अलावा रॉ, सीआईए, मोसाद और रूसी एवं ईरानी ख़ुफ़िया एजेंसियां भी इस इलाक़े में सक्रिय हैं.

राजनीतिक और धार्मिक पार्टी स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होती है. हमारी राजनीतिक पार्टियां पंजाब में काला बाघ बांध का समर्थन करती हैं, लेकिन सिंध में इसके ख़िलाफ़ विरोध सभाएं आयोजित करती हैं. यही अंतर हमें अलक़ायदा, टीटीपी और अफ़ग़ान तालिबान की गतिविधियों में भी दिखाई पड़ता है. लेकिन जिहाद और शरीयत पर आधारित उनकी विचारधारा ही केवल एक नहीं है, वह एक ही दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ाई भी लड़ते हैं. अंतर सिर्फ़ इतना है कि जहां अलक़ायदा अमेरिका और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, वहीं अफ़ग़ान तालिबान की गतिविधियां अफ़ग़ानिस्तान में सीमित हैं, जबकि टीटीपी का पहला निशाना पाकिस्तान है. अलक़ायदा को अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ग़ान तालिबान और पाकिस्तान में टीटीपी के सहयोग की ज़रूरत है और बदले में वह इन दोनों की मदद करता है.

लंबे समय से चल रही अशांति और अस्थिरता के दौर ने इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियों के बीच छुप-छुपकर लड़ी जा रही लड़ाई के मैदान में तब्दील कर दिया है. डूरंड रेखा के दोनों ओर सरकार का कोई ज़ोर नहीं चलता, बल्कि अलग-अलग देशों की ख़ुफ़िया सेवाओं की गतिविधियां अपने चरम पर हैं. कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, यह जानना बेहद मुश्किल है. पाकिस्तान के अलावा रॉ, सीआईए, मोसाद और रूसी एवं ईरानी ख़ुफ़िया एजेंसियां भी इस इलाक़े में सक्रिय हैं. संभव है कि आतंकियों का एक छोटा सा वर्ग भी अंजाने में या जानबूझ कर इन एजेंसियों के लिए काम कर रहा हो, लेकिन अधिकांश आतंकवादी अपनी विचारधारा से इस कदर प्रभावित हैं कि वह अपने उद्देश्यों से भटक नहीं सकते. अलक़ायदा और टीटीपी की कमान अब अतिवादी शक्तियों के हाथों में है. अमेरिका और उसके मुस्लिम सहयोगियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ना उनके विश्वास से जुड़ा है. उनका कहना है कि यदि बाबराक कारमल, डॉ. नजीबुल्लाह एवं उनके मुस्लिम समर्थकों जैसे सोवियत संघ के सहयोगियों के ख़िलाफ़ लड़ाई एक जिहाद था, तो मौजूदा समय में हामिद करजई एवं अमेरिका समर्थक अन्य मुस्लिम सहयोगियों के ख़िलाफ़ जंग को पवित्र लड़ाई क्यों न माना जाए. हाल के दिनों में अमेरिका से पहले अरब देशों और पाकिस्तान को निशाना बनाने की सोच भी अपनी जड़ें गहरी करती जा रही है. इसके साथ ही बदले की भावना भी लगातार बढ़ती जा रही है.

उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने उनके साथ धोखा किया है. पहले वह केवल सरकारी अधिकारियों और सेना के जवानों को ही निशाना बनाते थे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आ गया है. वे सोचते हैं कि जो कोई भी उनका विरोध करता है, उसे जीने का कोई हक़ नहीं है. प्रोपेगेंडा के लिए जो मसाला अब तैयार करके प्रचारित किया जा रहा है, वह इसी सोच पर आधारित है. अफ़ग़ान तालिबान की तरह पाकिस्तानी तालिबान का एक हिस्सा भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई के पक्ष में नहीं है, लेकिन बहुमत अब अलक़ायदा के रवैये के समर्थन में है. महसूद समर्थक गुट के अलावा जिहादियों का वह तबका जो जनजातीय इलाक़ों से वापस अपने घर लौट रहा है, पूरी तरह अलक़ायदा की सोच की गिरफ़्त में आ चुका है. यह तबका अफ़ग़ान तालिबान के मुक़ाबले अलक़ायदा से ज़्यादा प्रभावित है. शुरुआत में यह दावा किया गया कि जनजातीय इलाक़ों में कोई विदेशी नहीं है, लेकिन जब यह दावा झूठा प्रमाणित हो गया तो हम दूसरे बहानों की तलाश करने लगे. यह प्रचारित किया जाने लगा कि बैतुल्लाह महसूद वास्तव में एक अमेरिकी एजेंट है, लेकिन जैसे ही अमेरिकी द्रोण हमला शुरू हुआ, हम मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए. अब टीटीपी और महसूद के बारे में तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उनकी धमकियों को कोरी लफ्फाजी बताने की कोशिशें हो रही हैं. उनकी क्षमताओं पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं. लेकिन एक अरबी आत्मघाती हमलावर के माध्यम से खोस्त स्थित सीआईए केंद्र को तबाह कर अमेरिका के मुंह पर जो तमाचा इन्होंने लगाया है, क्या उसके बाद भी हम इनकी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं? मिशन पर रवाना होने से पहले आत्मघाती हमलावर के साथ हकीमुल्लाह महसूद का वीडियो टीटीपी और अलक़ायदा के बीच नज़दीकी रिश्तों की तस्दीक करता है.

वास्तविकता यह है कि टीटीपी की मज़बूती में ही अलक़ायदा की भी मज़बूती है और इसका उल्टा भी इतना ही सत्य है. यही बात अलक़ायदा और अफ़ग़ान तालिबान पर भी लागू होती है. इसलिए यह ज़रूरी है कि तीनों के ख़िलाफ़ एक ही तरह की रणनीति बनाई जाए. यदि अलक़ायदा के ख़िलाफ़ ताक़त का इस्तेमाल किया जाता है तो हम टीटीपी या अफ़ग़ान तालिबान के साथ समझौता या दोस्ताना व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकते. यदि हम अफ़ग़ानिस्तान में अफ़ग़ान तालिबान की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं तो पाकिस्तान में टीटीपी के ख़िलाफ़ संघर्ष नहीं छेड़ सकते. एक इलाक़े में समझौता और दूसरे इलाक़े में सैनिक अभियान, एक गुट के ख़िलाफ़ लड़ाई और दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार की नीति अपनाने से हम निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएंगे. हमें इस मसले की व्यापकता को समझते हुए अपनी घरेलू एवं विदेश नीति पर फिर से विचार करना होगा और इसके अनुरूप इसका एक राजनीतिक समाधान ढूंढने की कोशिश करनी होगी. यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें इसके परिणाम झेलने के लिए भी तैयार रहना होगा.

सलीम साफी

(लेखक पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं)

feedback@chauthiduniya.com

सदियों से लोग अदरक का उपयोग विभिन्न तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए करते हैं, जैसे सर्दी और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार
जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

समस्या है तो समाधान है

चौथी दुनिया का आरटीआई अभियान अब लोगों तक पहुंचने लगा है. हमारे पाठकों और आम जनता ने अपनी समस्याएं अब हमसे बांटनी शुरू कर दी हैं. इसका सबूत है उनके द्वारा भेजे गए पत्र, ईमेल, फोन कॉल्स. यही नहीं, लोग अब हमारे दफ्तर में भी आकर हमसे सलाह ले रहे हैं. यह शुभ संकेत है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कि जनता जागरूक हो रही है और लोकतंत्र के चौथे खंभे के रूप में चौथी दुनिया अपनी भूमिका बख़ूबी निभा रहा है. हम अपने पाठकों को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे इसी तरह अपनी प्रतिक्रियाओं और समस्याओं से हमें अवगत कराते रहेंगे. इस अंक में हमने अपने कुछ पाठकों के पत्र शामिल किए हैं. इन पत्रों में अलग-अलग तरह की समस्याओं का ज़िक्र है. लेकिन समस्याओं से घबराने की ज़रूरत नहीं है. समस्या है तो समाधान भी है. हम ज़्यादातर समस्याओं का समाधान सवाल-जवाब के तहत देने की कोशिश कर रहे हैं. आगे के अंकों में भी हम आपकी समस्याओं का इसी तरह समाधान देते रहेंगे. आप आरटीआई क़ानून का जमकर इस्तेमाल करते रहिए.

आपके सवाल-हमारे जवाब

बकाया वेतन

मैं भारतीय सेना में जेसीओ हूं. मैंने अपने वेतन और अन्य भत्तों की बकाया राशि के लिए वेतन कार्यालय में कई पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. मेरे 75 हज़ार रुपये फंसे हुए हैं. क्या मैं इस मामले में आरटीआई का इस्तेमाल कर सकता हूं?

राकेश चतुर्वेदी, *पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश.*

■ अगर आपने पहले से कोई पत्र इस संबंध में वेतन कार्यालय में भेजा है और उसकी एक कॉपी प्राप्ति रसीद के साथ आपके पास है तो आप एक आरटीआई आवेदन देकर यह पूछ सकते हैं कि अब तक आपके आवेदन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. हां, अपने आरटीआई आवेदन के साथ पहले दिए गए पत्र की एक कॉपी ज़रूर लगाएं.

अपीलीय अधिकारी का पता

मैंने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) से बिजली दर से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं. छह माह बीत जाने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिली. अपील करने के लिए मुझे कोई उपयुक्त पता मालूम नहीं है. कृपया मुझे सही अपीलीय प्राधिकारी का पता बताएं, ताकि मैं अपना आवेदन वहां दे सकूं. **गणेश सिंह,** *नई दिल्ली.*

■ देखिए, आरटीआई क़ानून के तहत हर सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी और उसी विभाग में एक अपीलीय अधिकारी का पद होता है. आवेदन देने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि आपको उस अधिकारी का नाम मालूम हो. बस आपको उस विभाग का पता मालूम होना चाहिए. वैसे 6 माह बीतने के बाद आरटीआई क़ानून के तहत यह संभव नहीं कि अब आप प्रथम अपील कर सकें. हमारा सुझाव है कि आप फिर से एक आरटीआई आवेदन देकर अपना सवाल पूछें.

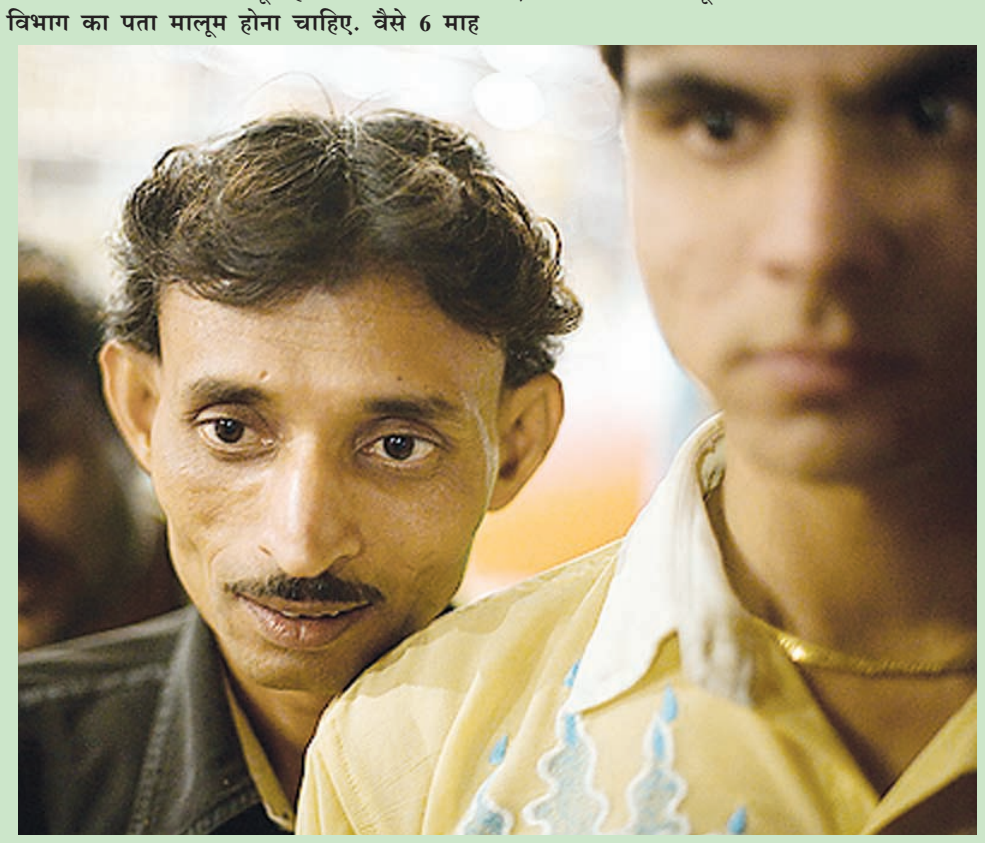

कारखाना संकट में

धनबाद में पहले भारत सरकार का एक उपक्रम बर्न स्टैंडर्स कंपनी लिमिटेड चल रहा था. वर्ष 2000 में इसे सरकार ने बंद कर दिया और कर्मचारियों को वीआरएस दे दिया गया. उस वक़्त वेतन बहुत कम था, इसलिए हम लोगों को बहुत कम पैसा मिला. आज यह कारखाना वीरान पड़ा है. चोर इसका सारा सामान चुराकर ले जा रहे हैं. सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है. वहां सुरक्षाकर्मी भी नहीं हैं. क्या इस मामले में लापरवाह प्रबंधन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं?

रामानंद कुमार, बर्दवान, *पश्चिम बंगाल.*

■ कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है. यह कारखाना जिस मंत्रालय के अधीन आता है, उसमें एक आरटीआई आवेदन देकर सवाल पूछे जा सकते हैं. मसलन, इस कारखाने की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त हैं या सामान की चोरी के लिए कौन ज़िम्मेदार है इत्यादि. आप यह आवेदन ज़रूर डालें, फिर हमें बताएं कि आगे क्या हुआ. हम इस मामले में आपकी हरसंभव मदद करने को तैयार हैं.

स्काई शॉप की धांधली

मैंने फोन पर स्काई शॉप को रूप अमृत जेल के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन पैसा चुकाने के बाद जब वीपीपी पार्सल खोला तो उसमें से रद्दी काग़ज़ निकला. जब कंपनी वालों से संपर्क किया तो गोलमोल जवाब मिला. **सुरेश निहलानी,** *बीजापुर.*

■ आप इसकी शिक़ायत पुलिस और टेलीकॉम विभाग में कर सकते हैं. बाद में अपनी शिक़ायत पर एक आरटीआई आवेदन उक्त जगहों पर देकर पूछ सकते हैं कि आपकी शिक़ायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

शनि के उपग्रह पर जीवन की संभावना

शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है. उसके अनेक उपग्रहों में छठा सबसे बड़ा उपग्रह एन्केलादोस है, जिसे अंग्रेजी में एन्सेलेडस पढ़ा जाता है. संभावना व्यक्त की गई है कि शनि के इस उपग्रह पर बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व है. ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है. वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एन्सेलेडस पर तरल पानी है और जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक सामग्री भी वहां मौजूद है. अमेरिका में बौल्डर स्थित कोलोरैडो विश्वविद्यालय की ग्रह वैज्ञानिक कैरॉलिन पोर्को बताती हैं कि वैसे तो उसकी ऊपरी सतह बर्फ की मोटी तह से ढकी हुई है, जिसमें बड़ी-बड़ी दरारें हैं, लेकिन इन दरारों के बीच से ज्वालामुखी जैसे पानी के स्रोत कई-कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक पानी और बर्फ के फव्वारे छोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि एन्सेलेडस की ऊपरी सतह पर तो -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान है, लेकिन बर्फ की दरारों में वह केवल -70 डिग्री के आसपास है. बर्फ की मोटी तह के नीचे तापमान निश्चित रूप से और ज़्यादा होना चाहिए. हमें अब यह निश्चित जान पड़ता है कि बर्फ के नीचे तरल पानी का ऐसा महासागर होना चाहिए, जिससे गरम स्रोतों को पानी मिलता है. एन्सेलेडस बहुत बड़ा नहीं है. उसका व्यास केवल 504 किलोमीटर है. कुछ साल पहले तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि वह इतना ठंडा और निर्जीव होना चाहिए कि वहां किसी तरह का जीवन नहीं हो सकता है. लेकिन 2005 से, जबसे यूरोपीय अमेरिकी अन्वेषण यान कसीनी ने काफी निकट से उसके कई चक्कर लगाए हैं और उसके चित्र भेजे हैं, तबसे उसे पूरे सौरमंडल में एक बहुत ही दिलचस्प जगह माना जाने लगा है. सोचा जा रहा है कि वहां ऐसी रासायनिक क्रियाएं चल रही हैं, जो शायद जीवन के आरंभिक चरण में हैं. हो सकता है कि वहां सूक्ष्म जीवाणुओं जैसा जीवन शुरू भी हो गया हो.

अदरक खाओ, दर्द दूर भगाओ

मांसपेशियों में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपको अब दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह केवल अदरक खा लेने भर से छूमंतर हो जाएगा. मतलब यह कि अदरक खाइए और दर्द को दूर भगाइए. इतना ही नहीं, अगर आप कसरत करने के बाद रोज़ाना सीमित मात्रा में अदरक खाते हैं तो इससे भी आपको मांसपेशियों के दर्द से राहत मिलेगी.

इसका खुलासा हाल में हुए एक शोध में किया गया है. घरेलू कामकाज या फिर खेलने के बाद आप थक जाते होंगे या फिर मांसपेशियों में दर्द महसूस करते होंगे, लेकिन अदरक का चूर्ण बनाकर एक खुराक रोज़ाना खाने से आपको दर्द से निजात मिल सकती है. हालांकि सदियों से लोग अदरक का उपयोग विभिन्न तरह की बीमारियों से निजात पाने के लिए करते हैं, जैसे सर्दी और पेट से संबंधित बीमारियों के लिए. वैसे भी वैज्ञानिक दर्द निवारक गुण के लिए अदरक को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन अब अदरक मांसपेशियों का दर्द ठीक करने लिए भी काफी उपयोगी है.जियोरजिया यूनिवर्सिटी के मुख्य शोधकर्ता प्रोफेसर पैट्रिक ओ कनॉर ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज, जिससे दर्द से आराम मिलता है, वह लोगों द्वारा स्वागतयोग्य है. हालांकि इससे पहले मांसपेशियों में होने वाले दर्द में इसका क्या प्रभाव पड़ता था, इसका अध्ययन नहीं किया गया था. इसे रासायनिक गुण के कारण भी जाना जाता है. यह ठीक एस्प्रिन की तरह काम करती है. प्रोफेसर ओ कॉनर ने शोध के लिए 34 से 40 लोगों को लगातार 11 दिनों तक दो ग्राम अदरकयुक्त कैप्सूल खिलाए. कैप्सूल खाने वाले अधिकांश लोगों ने आठवें दिन मांसपेशियों के दर्द से राहत की बात स्वीकार की. इस शोध को जर्नल ऑफ पेन में प्रकाशित किया गया है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 7 जून–13 जून 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
अनावश्यक ख़र्चे आपको परेशान कर सकते हैं. आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी. ख़ुद पर भरोसा रखें. आर्थिक मामलों में ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है. इस हफ्ते पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिल सकते हैं. स्वास्थ्य पर अवश्य ध्यान दें.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह इंवेस्टमेंट और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. परिवार के साथ यात्रा का योग बनेगा. दोस्तों और परिवार से सहयोग मिलेगा. कार्यस्थल पर देरी के कारण नीचा देखना पड़ेगा. व्यापारिक लेनदेन में अनुकूल परिणाम मिलेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
व्यवसायिक यात्रा सफल रहेगी. आर्थिक मामलों में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. जोश दिखाने से काम में सफलता मिलेगी. विवाह संबंधी चिंता का समाधान हो सकता है. परिवार में मनमुटाव आपको दुखी कर सकता है. यात्रा का कार्यक्रम बनेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
परिवार में किसी का स्वास्थ्य ख़राब होगा. दिल के मामले अच्छे रहेंगे, लेकिन उम्मीद से कुछ कम. परिवार के साथ कुछ समय बिताएं. बॉस से तारीफ़ मिलेगी. शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग बने हुए हैं.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
आर्थिक मामले फ़ायदेमंद रहेंगे. परिवार के साथ रिश्ते और गहरे होंगे. यात्रा सुखद रहेगी. अगर आप अपने लिए थोड़े से भी सचेत हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. विवाह संबंधी चिंता का समाधान होगा. सार्वजनिक जीवन में आपकी अलग पहचान बनेगी.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह कोई विशेष व्यक्ति आर्थिक मामलों में आपकी सहायता करेगा. उसकी मदद से आपको इंवेस्टमेंट में फ़ायदा होगा. विवाद और मतभेद छोड़ कर समझौतावादी रवैया अपनाएं, सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. बिज़नेस ट्रिप में सफलता नहीं मिलेगी. क़रीबी लोगों के साथ यात्रा करने से ख़ुशी मिलेगी. कामकाज में गति आने से राहत मिलेगी. संबंधों में सुधार के लिए स्वार्थी रवैया त्यागें. प्रियजन के साथ समय व्यतीत करेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. यह यात्रा आपको सफलता दिलाएगी. साझेदारी में लाभ के सौदे होंगे. आर्थिक मामलों और इंवेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दें. अविवाहित वैवाहिक रिश्तों को लेकर उत्साहित रहेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
यात्रा सफल रहेगी और कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे. कोई बड़ा इंवेस्टमेंट न करें. विरोधी परेशान कर सकते हैं. हर कार्य सावधान होकर करें. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. अपनी कमियों को दूर करें, राह आसान होगी. वाणी में मधुरता लाएं.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
दिल के मामले आपको काफी ख़ुशी और शांति देंगे. इस हफ्ते आपको अपने साथी से काफी सहयोग मिलेगा. कानूनी मामले आपके पक्ष में रहेंगे. भावनात्मक परेशानियों से स्वास्थ्य पर बुरा असर होगा. कोई भरोसेमंद व्यक्ति धोखा दे सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
मांगलिक कार्यों में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. व्यवसाय के संबंध में भी अच्छी ख़बर मिलेगी और सफलता आपके क़दम चूमेगी. परिवार के साथ राहत महसूस करेंगे. यात्रा से आपकी चिंताएं कम होंगी.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
जैसे-जैसे हफ्ता ख़त्म होगा, वैसे-वैसे निवेश में फ़ायदा होगा. पेट से संबंधित शिक़ायत हो सकती है. परिवार आपके निर्णयों से सहमत होगा. निजी संबंधों में अनुकूलता संभव है. अचानक हुई कोई घटना आपको आश्चर्य में डाल सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अमेरिकी समाज हर अमेरिकी मुसलमान, चाहे वह अमेरिका में पैदा हुआ हो या कहीं और, की नीयत को संदेह की नज़रों से देखता है.

नेतृत्वविहीन अमेरिकी मुस्लिम समुदाय

यह अब एक रूटीन सा बन गया है और हमें इसकी आदत सी हो गई है. जैसे ही अमेरिकी मीडिया में किसी आतंकी वारदात या गिरफ्तारी की ख़बर आती है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स काउंसिल और काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस जैसे संगठनों की पब्लिक रिलेशंस शाखा की गतिविधियां बढ़ जाती हैं. सफ़ाई से तैयार की गईं प्रेस विज्ञप्तियां बड़े मीडिया घरानों को भेजी जाती हैं, दोषियों की जमकर आलोचना की जाती है और अमेरिकी समाज से यह अपील की जाती है कि कुछ लोगों की शरारतों के चलते देश में रह रहे लाखों मुसलमानों को दोषी न माना जाए. पिछले एक साल के अंदर कई ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मौके आए हैं, जब अमेरिका के मुस्लिम मीडिया को हरकत में आने के लिए मजबूर होना पड़ा. पिछले साल नवंबर में फोर्ट हुड हादसा हुआ, जिसमें एक फिलीस्तीनी अमेरिकी मेजर निदाल हसन ने गोलीबारी करके 13 लोगों को मौत के घाट उतार दिया. इसके एक महीने के अंदर ही डीसी–5 को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया. पाकिस्तानी मूल के उक्त अमेरिकी युवक पाकिस्तान में आतंकवाद की ट्रेनिंग लेने की कोशिश कर रहे थे. फिर हाल के दिनों में फ़ैसल शहजाद का किस्सा प्रकाश में आया. हालांकि फ़ैसल टाइम्स स्क्वायर में विस्फोट करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसकी साधारण जीवनशैली और मिलनसार व्यवहार ने हर मुसलमान की नीयत पर संदेह का परदा चढ़ा दिया है, जो आमतौर पर शांतिप्रिय और क़ानून के दायरे में रहना पसंद करते हैं.

इस घटना के तुरंत बाद अमेरिका के पूर्वी तट वाले इलाक़े में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और ख़बरों में इसके हर पहलू की विवेचना की गई. एक आतंकवादी को आख़िर क्या–क्या चीजें प्रेरित करती हैं, यह जानने की कोशिश में शहजाद की फैशनपरस्त पत्नी एवं पैसों के लेनदेन की चर्चा के साथ–साथ उसके घर को सील करके हर कोने की तलाशी ली गई. उम्मीद के मुताबिक़ अमेरिका की चिंताओं की एक ही वजह है, अमेरिका में रह रहे मुसलमानों द्वारा देश में आतंकी हमलों को संगठित करने और उसे अंजाम देने की क्षमता. ताज्जुब की बात तो यह है कि मुस्लिम अमेरिकी संस्थाएं इस मुद्दे पर प्रभावी तरीके से निबटने में असफल रही हैं. अमेरिकी मुसलमान अपने समुदाय के अंदर तेज़ी से फैल रहीं अतिवादी और प्रतिक्रियावादी ताक़तों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे, इसका जवाब ढूंढना काफी मुश्किल है. इसका सबसे बड़ा कारण शायद 9/11 के हमलों में छुपा है. आतंकी मामलों में गिरफ्तारियों की स्थिति में एक संगठन के रूप में अमेरिकी मुस्लिम समुदाय अक्सर 9/11 का हवाला देता है. अपने बचाव में उक्त संगठन यही तर्क देते हैं कि 9/11 में शामिल आतंकी अमेरिकी नहीं थे और अमेरिकी समाज एवं जीवनशैली से उनका दूर तक कोई रिश्ता नहीं था. अमेरिकी मुसलमानों को पाकिस्तानी या फिलीस्तीनियों से अलग समुदाय के रूप में प्रचारित करने और अफ्रीकी–अमेरिकी या श्वेत लोगों के नेतृत्व को बढ़ावा देने के पीछे यही सोच थी कि यह एक रक्षा कवच का काम करेगा और दूर मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों की कारस्तानियों की ज़िम्मेदारी लेने से पूरा समुदाय बचा रहेगा.

लेकिन मुस्लिम अमेरिकी आतंकवादियों की जमात के उभरने से इस रणनीति की विफलता तय है. एक ओर जहां अमेरिका में पैदा हुए मुसलमान फ़ैसल शहजाद जैसे लोगों, जो मुस्लिम देशों में पैदा हुए हैं, की खुलेआम आलोचना करने से नहीं चूकते, वहीं अमेरिकी समाज की मुख्यधारा में यह अंतर कोई मायने नहीं रखता. अमेरिकी समाज हर अमेरिकी मुसलमान, चाहे वह अमेरिका में पैदा हुआ हो या कहीं और, की नीयत को संदेह की नज़रों से देखता है. जैसा कि टाइम्स स्क्वायर मामले में हमने देखा है कि अमेरिकी मुस्लिम समुदाय और उसके संगठनों की भूमिका घटना घटित होने के बाद प्रतिक्रिया व्यक्त करने तक ही सीमित है और यह ख़ुद उसके लिए ठीक नहीं है. यह समुदाय अपनी अलग विचारधारा या नेतृत्व का विकास करने की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिससे अपनी सामाजिक हैसियत की रक्षा करने में कामयाब हो सके. इसकी जगह अमेरिकी मुस्लिम समुदाय जल्दी–जल्दी धनी बनने के अपने सपने को अमलीजामा पहनाने में लगा है. फिर उसकी एक चिंता यह भी है कि अमेरिका की खुली सामाजिक संस्कृति उसकी आने वाली पीढ़ियों को अपने प्रभाव में न ले ले. यही वजह है कि चमकदार गुंबदों वाली बड़ी–बड़ी मस्जिदें अमेरिका के तक़रीबन हर बड़े शहर में देखने को मिल जाती हैं और उनके आगे लगी कार की कतार अमेरिकी मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आर्थिक हैसियत की कहानी बयां करती है.

धनी मुसलमान, जिनकी संतानें अमेरिका में ही पैदा हुई हैं, ख़ुद को समुदाय के अंदर एक विशिष्ट तबका मानते हैं और बाद के दिनों में वहां पहुंचे टैक्सी चलाने वाले नव प्रवासियों को नीची निगाहों से देखते हैं. इसी तरह मध्य पूर्व के देशों से यहां आए मुसलमान पाकिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान मूल के मुस्लिमों से कोई जुड़ाव नहीं दिखाते.

इसी से पैदा हुई लापरवाही का परिणाम यह है कि समुदाय के नेताओं में शायद ही कोई ऐसा हो, जो युवा मुस्लिम अमेरिकियों के लगातार बढ़ते सामाजिक अलगाव जैसे मुद्दों के बारे में कुछ सोचता हो, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जबकि अमेरिकी समाज की मुख्यधारा उन्हें संदेह की नज़रों से देखने लगती है. मुस्लिम अमेरिकी समाज के माता–पिता अपनी संतानों के जीवन में मौजूद दोहरेपन के बारे में भी सोचने को तैयार नहीं हैं. मुस्लिम अमेरिकियों की इस नई पीढ़ी को एक ओर जहां समाज की मुख्यधारा से अलग रहकर अपनी पहचान बनाए रखना है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे बने रहने की चुनौती भी उनके सामने है. हाल के महीनों में एक और चिंताजनक बात देखने को मिली है. मुस्लिम अमेरिकी समुदाय अपनी पहचान के साथ जुड़े नस्लीय और धार्मिक पहलुओं के प्रति सतर्क नहीं हैं. कुछ महीने पहले एरिजोना में प्रवासियों के ख़िलाफ़ ऐसे भेदभावपूर्ण क़ानून को मंजूरी दी गई, जिसे शर्मनाक कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसकी कोई ख़ास प्रतिक्रिया नहीं दिखी. (इस क़ानून से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हिस्पैनिक मूल के लोग हैं) सीएआईआर जैसी राष्ट्रव्यापी संस्थाओं ने बार–बार प्रेस विज्ञप्तियां ज़रूर निकालीं, लेकिन ज़ुबानी जमा ख़र्च के अलावा बहिष्कार या एकता मार्च के आयोजनों की कोई चर्चा भी नहीं हुई. दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकी मुस्लिम समुदाय हिस्पैनिक मूल के लोगों के संगठनों के साथ ख़ुद को जोड़ने में नाकामयाब रहा. अब इसकी वजह चाहे हिस्पैनिक समुदायों के प्रति उसकी ख़ुद की नस्लीय भावना हो या फिर वह छलावे में आकर इस उदासीनता का शिकार हो गया हो (उस समय फ़ैसल शहजाद वाला मामला हुआ भी नहीं था), लेकिन वह यह समझने में असफल रहा कि नस्लीय भेदभाव के मामले में दोनों समुदाय एक ही धरातल पर खड़े हैं. इस क़ानून के अंतर्गत हिस्पैनिक मूल के लोगों को अपने प्रवास को वैध साबित करने के लिए पहचान प्रमाणपत्रों की ज़रूरत होगी. मुस्लिम समुदाय को भी विमान में यात्रा करने से पहले सुरक्षा जांचों की अंतहीन प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है, लेकिन वह दोनों मुद्दों को एक साथ जोड़ने में रणनीतिक रूप से विफल रहा. इसमें कोई संदेह नहीं कि 9/11 की घटना ने मुस्लिम समुदाय को सांगठनिक एकता के प्रति जागरूक बनाया, लेकिन यह समुदाय आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से खुद ही इतनी ज़्यादा विविधताओं वाला है कि यही उसके अंदर नेतृत्व के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गया है. यही वजह है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस विज्ञप्तियां निकाल कर कर्तव्य की इतिश्री समझ ली जाती है.

धनी मुसलमान, जिनकी संतानें अमेरिका में ही पैदा हुई हैं, खुद को समुदाय के अंदर एक विशिष्ट तबका मानते हैं और बाद के दिनों में वहां पहुंचे टैक्सी चलाने वाले नव प्रवासियों को नीची निगाहों से देखते हैं. इसी तरह मध्य पूर्व के देशों से यहां आए मुसलमान पाकिस्तान या अफ़ग़ानिस्तान मूल के मुस्लिमों से कोई जुड़ाव नहीं दिखाते. अमेरिकी मुस्लिम संगठनों और मस्जिदों की अंदरूनी राजनीति इन्हीं विरोधाभासों से संचालित होती है, जो न केवल उनके विकास में बाधक है, बल्कि एक ऐसे समुदाय की परिचायक है, जो खुद अपनी पहचान को लेकर संदेह में है. इतना ही नहीं, इसी के चलते मुश्किल भरे मौजूदा हालात में यह नेतृत्वविहीन होकर जीने को मजबूर है.

राफिया ज़कारिया
feedback@chauthiduniya.com

e देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम–भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार–राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

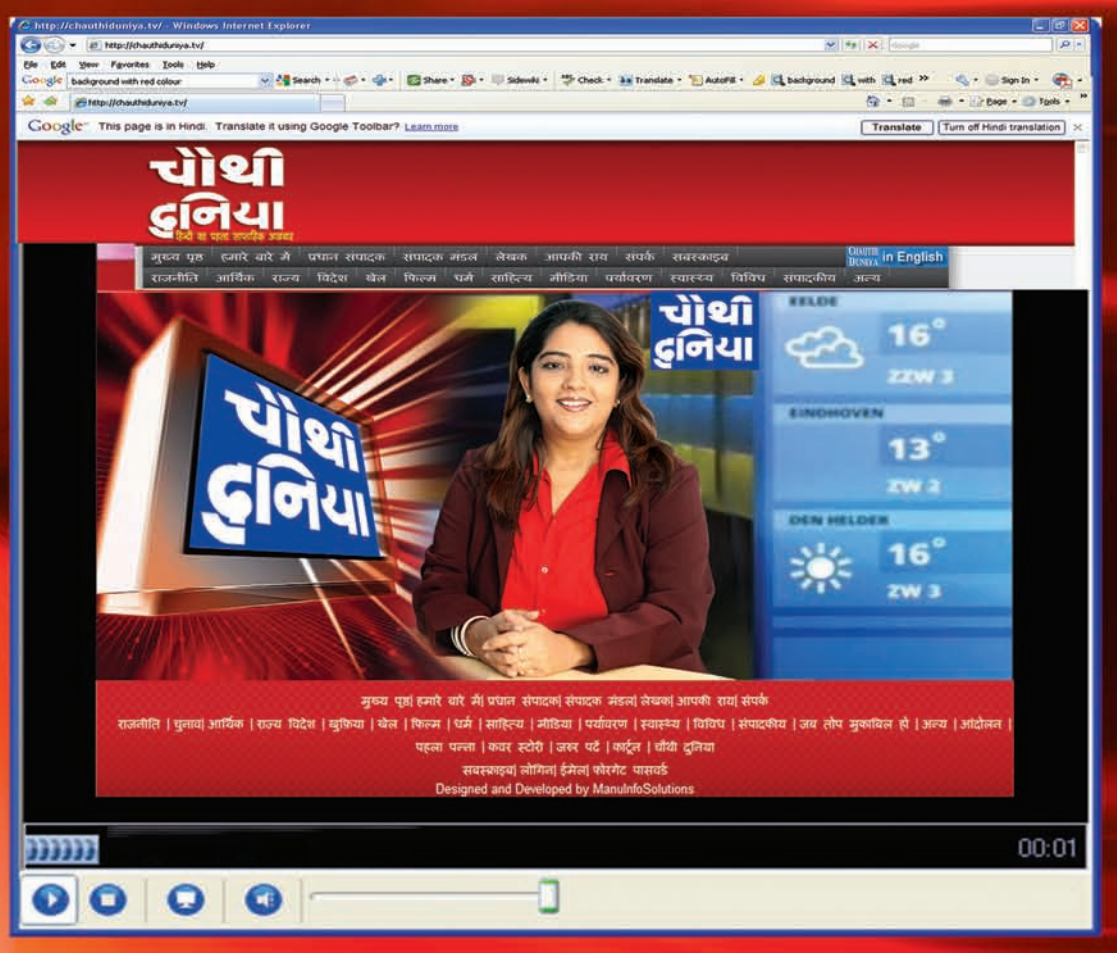

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

आम आदमी जब मंदिर में जाता है तो मंदिर की भव्यता, सुंदरता और पवित्रता को महसूस कर मन मसोस कर रह जाता है कि उसका नाम मंदिर की दीवारों पर कभी नहीं होगा.

ईंट दान क्यों

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन की उत्कृष्ट कृति वृंदावन में साई धाम और साथ ही वहां निर्माण किए जा रहे भव्य साईं मंदिर की चर्चा इन दिनों ज़ोरों पर है. लगभग डेढ़ साल पहले इसके स्थापना की प्रेरणा साई भक्त ऑसिम खेत्रपाल यानी मुझे स्वप्न में मिली. बाबा ने प्रेरणा दी एक ऐसे विशाल मंदिर का निर्माण हो जिसकी हर ईंट भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने से आए. आज तक जितने भी भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ है, लोगों के दान से हुआ है. बड़े-बड़े उद्योगपति लाखों रुपये दान में देते हैं और फिर उनके नाम संगमरमर की दीवारों पर खुदे होते हैं. आम आदमी जब उस मंदिर में जाता है, मंदिर की भव्यता, सुंदरता और पवित्रता को महसूस कर मन मसोस कर रह जाता है कि उसका नाम मंदिर की दीवारों पर कभी नहीं होगा. वह कुछ पैसा दान पेटी में डालकर भगवान को प्रणाम कर आगे बढ़ जाता है. बाबा जो ग़रीब नवाज़ हैं, उन्होंने अपने हर भक्त की पुकार को सुना और ऐसे मंदिर के निर्माण की प्रेरणा मुझे दी जिसकी हर ईंट उनके हर भक्त के नाम से होगी. चाहे वह सड़क पर रिक्शा चलाने वाला मज़दूर हो, मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता सीनियर एक्जिक्यूटिव हो. सिर्फ़ पांच सौ रुपये की एक ईंट के दान से उसे न सिर्फ़ ऐसा महसूस होगा कि ये मंदिर उनका अपना है बल्कि उसकी दीवारों पर अंकित उनका नाम उन्हें अमर कर देगा. इस महान विचार के साथ शुरूआत हुई ईंट दान की मुहिम की. लगभग दो साल पहले जब इसकी शुरूआत हुई तब मुझे लोगों की बहुत सी बातों का सामना करना पड़ा था, लोगों ने इल्जाम लगाया कि ईंटें बेची जाएंगी. कुछ ने कहा बाबा को बेचा जा रहा है तो किसी का मानना था आध्यात्म के नाम पर पैसा बटोरा जा रहा है. लेकिन बाबा के भक्त जानते थे कि उन्हें प्रेरणा कहां से मिली है. उनका असल विश्वास बाबा पर और उनके संकेतों पर है. मैंने ईंट दान का प्रचार सभी माध्यमों टेलीविजन, पोस्टर, एसएमएस, अख़बार से लोगों तक पहुंचाया. चूंकि भावना भक्ति से प्रेरित थी, इसलिए सब कुछ होता चला गया. कहा जाता है अगर बीज होगा तो फल भी मीठा होगा. इन दो सालों में जन-जन ने ईंट दान की. उनके साथ चमत्कार होने लगे. लोगों के घर बन गए. नौकरियां लग गईं, शादी तय हो गईं. ऐसी ही छोटी मोटी मुश्किलें जिनसे लोग परेशान थे, ईंट दान के बाद ही ठीक होने लगीं. यह बाबा का संकेत था या अपनी ही शक्ति की का परिणाम कि सभी काम पूर होते गए. ईंट दान करते-करते लोग धीरे-धीरे फाउंडेशन से जुड़ते गए और एक परिवार का हिस्सा बनते गए. आज धीरे धीरे साई भक्त परिवार एक अलग मुकाम पर पहुंच गया है.

साई भक्त परिवार का हिस्सा बनने के लिए कृपया पर **09999313918** एसएमएस करें.

ॐ साई राम.

ऑसिम खेत्रपाल
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

बाबा के जीवन से

शिरडी के साई बाबा ने अपना पूरा जीवन एक फकीर के भेष में गुज़ार दिया. अपने भक्तों के लिए जहां उनका चरित्र बहुत सहज, सरल, निर्मल और प्रेमपूर्ण था, वहीं घमंडी और लोभी व्यक्तियों को सबक सिखाकर उन्हें सही रास्ते पर लाना भी बाबा को ख़ूब आता था. बाबा ने हर व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने के लिए कभी प्रेम का, कभी गुस्से का और कभी चमत्कारों का सहारा लिया. इसलिए बहुतों के लिए बाबा का चरित्र रहस्यमयी था. सबके बारे में सब कुछ जानने वाले बाबा के किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है. लेकिन एक बार बाबा ने स्वयं अपने जीवन की एक घटना अपने भक्तों को सुनाई थी. उन्होंने बताया कि उन पर गुरूकृपा कैसे हुई. एक बार बाबा और उनके तीन भक्त ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग के बारे में बात कर रहे थे. एक भक्त ने कहा कि हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनना चाहिए और दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है. दूसरे ने कहा कि हमें अपनी संकीर्ण भावनाओं और विचारों से मुक्त होना चाहिए. इस पर तीसरे ने कहा कि यह संसार तो सदैव परिवर्तनशील है. सिर्फ़ निराकार ही शाश्वत है, इसलिए हमें सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए. तब चौथे यानी बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करना चाहिए, दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा से हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राणादी गुरू को समर्पित कर देने चाहिए क्योंकि वही हमें ईश्वर तक पहुंचाएगा. इस प्रकार तर्क-वितर्क के बाद चारों लोग ईश्वर की खोज में वन की ओर चले. रास्ते में उन्हें एक बंजारा मिला, उसने पूछा, हे सज्जनों इतनी तपती धूप में आप लोग किधर जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग वन की ओर जा रहे हैं. तब बंजारे ने पूछा कि किस उद्देश्य से वन की ओर जा रहे हैं. उन्होंने टाल मटोल करना चाहा पर दी बंजारा फिर बोला हे सज्जनों बिना पथ प्रदर्शक के इस भयानक वन में भटकने से कोई लाभ नहीं है. अगर आपकी इच्छा इस वन में घूमने की है तो किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें. उन चारों ने उस बंजारे की बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गए. उन्होंने सोचा कि वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है, तब किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है.

लेकिन वन में दिन भर इधर उधर भटकते थके-हारे भूखे प्यासे चारों वहीं पहुंच गए जहां वह बंजारा था. उनकी हालत देख वह बहुत प्रेम से बोला, हर कार्य में चाहे वो छोटा हो या बड़ा, मार्ग दर्शक आवश्यक होता है, ईश्वर के प्रेरणा के अभाव में सत्पुरूषों से भेट होना संभव नहीं है. भूखे रह कर तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता, यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करें बल्कि ईश्वर का प्रसाद समझ कर ग्रहण करना चाहिए. यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानना चाहिए. बंजारे के इस प्रेमपूर्ण आग्रह को, स्वयं को महाज्ञानी समझने वाले तीन मित्रों ने अस्वीकार किया और आगे बढ़ गए. लेकिन बाबा को उस अनपढ़ की बातों में सच्चाई दिखी. उस बंजारे का निर्मल और प्रेमपूर्ण स्वभाव देखकर बाबा ने उसका रूखा सूखा भोजन खाया. भोजन समाप्त होते ही बाबा ने देखा उनके गुरू वहां प्रकट हुए. गुरू ने पूछा कि क्या बात है, बाबा ने पूरी घटना उन्हें सुना दी, उन्होंने मुझे आश्वास्त किया और कहा कि तुम्हारे मन की इच्छा मैं पूर्ण करूंगा पर इसके लिए मुझ पर संपूर्ण विश्वास रखना होगा. बाबा के हां में सिर हिलाने पर गुरूजी उन्हें कुअें के पास ले गए और रस्सी उनके पैर में बांध कर उन्हें कुए में लटका दिया, बाबा का सिर पानी को छू नहीं सकता था और न ही हाथ, उन्हें यूं लटका गुरूजी कहीं चले गए और चार पांच घंटे बाद लौटे, बाबा को बाहर निकाल उनसे पूछा तुम्हारा कैसा अनुभव रहा. बाबा बोले गुरूदेव मुझे परमानंद की अनुभूति हुई. बाबा का जवाब सुन गुरूजी ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने साथ अपनी शाला में ले लिया. बाबा ने कहा कि यही वह जगह थी जहां वह सारी इंद्रियों के मोहजाल से बाहर निकलकर खुद को पहचान पाए. दिन रात ध्यान में मग्न होने के बाद बाबा का मन और बुद्धि स्थिर हुई. उन्होंने बताया कि गुरूकृपा से उन्हें किसी भी वस्तु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी. बल्कि हर वस्तु दिन में प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी. केवल गुरू ही जानते हैं कि कुअें में उलटा लटके हुए जब पूरा संसार घूमता हुआ नज़र आए, पैरों तले ज़मीन खिसक जाए, ज़िंदगी इधर से उधर हो जाए, अगर गुरू पर अटूट विश्वास और निष्ठा है तो मन कभी विचलित नहीं होगा, हर पल परमानंद की अनुभूति होगी.

इस हफ्ते फाउंडेशन में

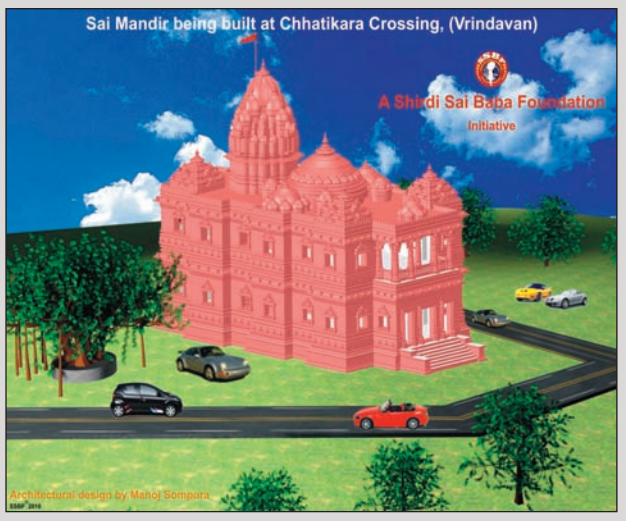

लगातार बढ़ता साई परिवार हर हफ्ते नए-नए आयाम कायम रचता जा रहा है. हफ्ते में तीन दिन शाम 6 से 8 स्वयं को पहचानने और जानने की ज्ञान चर्चाएं और साई योग के माध्यम से लोग अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लगे हैं. इन कक्षाओं में सिखाया जाता है कि बाबा के साथ रिश्ता कैसे जोड़ें.

हर रात सोने से पहले बाबा की डायरी या चिट्ठी लिखें. उन्हें बताए दिन भर में क्या हुआ, किस बात ने आपको दर्द दिया, क्या अच्छा हुआ. अच्छा लगता है. धीरे धीरे आप पाएंगे आप शिकायतों के परे पहुंच गए हैं. तब न सिर्फ़ आप शांति से सोएंगे बल्कि अगली सुबह एक नई ताज़गी के साथ शुरू होगी. डायरी लिखने के इस प्रयोग ने सेशंस में आने वाले बहुत से लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है. भारत के कोने कोने से आए लोगों के ईंट दान से बनने जा रहा फाउंडेशन द्वारा निर्मित भव्य साई मंदिर का डिजाइन आ गया है. हम सभी साई भक्तों के लिए यह डिजाइन दिखा रहें है. अक्षरधाम मंदिर का निर्माण करने वाले प्रसिद्ध आर्किटेक्ट मनोज संपूरा ही इस मंदिर का निर्माण करेंगे.

शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन (रजि.)

अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म शिरडीपुरीश्वर साई नाथ महाराज के सिद्धांतों, शिक्षाओं, जनचेतना और जनजागरण के कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शिरडी साई फाउंडेशन कृत संकल्प है. यदि आप भी इस महायज्ञ में अपने सत्कर्मों की आहुति डालना चाहते हैं तो साई भक्त परिवार में आपका सहर्ष स्वागत है.

नाम.....

पता.....

टेलीफोन.....मोबाईल.....

ई-मेल.....

हस्ताक्षर

सदस्य बनने के लिए अपना पूरा विवरण निम्न पते पर अपने ड्राफ्ट के साथ भेजें

हमारा पता है:-

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन पोस्ट बॉक्स नंबर-17517, मोती लाल नगर नंबर-1, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई-58

आप अपना नाम, पता और फोन नंबर 09999989427 पर एसएमएस भी कर सकते हैं

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना (कार्यक्रम, प्रबंधक, तिथि, स्थान और समय सहित) www.ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

लेह में सांप्रदायिक अलगाव का मूल कारण बेशक़ राजनीतिक है, लेकिन इसके साथ धार्मिक पहलू भी जुड़े हैं.

अदम्य जिजीविषा की दास्तां

अनंत विजय

आत्मकथा और जीवनियों में मेरी शुरू से ही रुचि रही है. देशी–विदेशी लेखकों, साहित्यकारों, फ़िल्म कलाकारों और राजनेताओं की दर्जनों आत्मकथाएं मैंने पढ़ी हैं. पिछले दिनों कूरियर से मुझे डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना की आत्मकथा– मेरी आत्मकथा, कालजयी संघर्ष गाथा मिली. आत्मकथा देखकर मैंने इस किताब को अलग रख दिया कि जब भी मौक़ा मिलेगा, इसे ज़रूर पढ़ूंगा. लेकिन दो–तीन महीने बीत गए, नौकरी की व्यस्तता के बीच ऐसा फंसा कि कुछ भी पढ़ना–लिखना संभव नहीं हो पाया, किसी भी किताब को हाथ नहीं लगा पाया. इस बीच मेरे श्वसुर दिल्ली आए और बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गए. तीन दिन नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रहे. इस तरह के अस्पतालों में करने को तो कुछ होता नहीं है, मरीज़ की सेवा–सुश्रुषा तो हॉस्पिटल के ज़िम्मे होती है, लेकिन किसी भी आपातकालीन स्थिति से निबटने और हर तरह के टेस्ट के पहले सहमति पत्र पर दस्तखत करने के लिए आपको वहां रुकना पड़ता है. ख़ैर यह एक अवांतर प्रसंग है.

अस्पताल में मैं दो–तीन किताबें ले आया था. पत्रकार गीताश्री की नागपाश में स्त्री और द्वारिका प्रसाद सक्सेना की आत्मकथा, लेकिन आत्मकथाओं में रुचि की वजह से मैंने पहले द्वारिका जी की किताब को पढ़ना शुरू किया. पहले उसकी भाषा को लेकर मेरे मन में सवाल खड़े होने लगे. सक्सेना जी की भाषा पचास के दशक की हिंदी है, जहां पानी को जल, नदी को सरिता कहने का प्रचलन था, लेकिन उनकी भाषा में एक लालित्य था, जो मुझे बांधे रहा. जैसे–जैसे आगे बढ़ता गया, भाषा गौण होती चली गई और लेखक का संघर्ष हावी होता चला गया. लेखकीय संघर्ष ने भाषा, कथ्य एवं प्रवाह सबको पीछे छोड़ दिया. एक ग़रीब परिवार का 12–15 साल का बच्चा किस तरह से दिल्ली आता है, वहां कई प्रेसों में कंपोजिटर की नौकरी करते हुए अपनी निष्ठा और लगन से प्रेस मालिकों का दिल जीतते हुए फोरमैन के पद तक जा पहुंचता है, लेकिन उसकी क़िस्मत में विधाता ने कुछ और ही लिख रखा था. कई नौकरियां छूटीं, कई मिलीं, लेकिन अंतिम पड़ाव आना शेष था. इस बीच द्वारिका जी ने जीविकोपार्जन के लिए क्या–क्या नहीं किया. चाय बेची, साइकिल की दुकान में काम किया, लेकिन कहीं भी पढ़ाई के प्रति मोह और लगन में कमी नहीं आई. दिल्ली में प्रेस में हिंदी कंपोजिटर की नौकरी करते हुए स्वाध्याय से अंग्रेजी सीखना और फिर अंग्रेजी में कंपोजिंग में दक्षता हासिल कर लेने का जो प्रसंग है, वह इस बात को एक बार फिर से साबित करता है, *करत–करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान.* बग़ैर किसी औपचारिक ज्ञान के, किसी गुरु के, किसी संसाधन के, किसी सपोर्ट के द्वारिका जी ने सड़क किनारे लैंपपोस्ट के नीचे बैठकर अंग्रेजी का ज्ञानार्जन किया. उस समय हिंदी कंपोजिटर द्वारका जी को यह महसूस हुआ था कि हिंदी की अपेक्षा अंग्रेजी कंपोजिटर को अधिक वेतन मिलता है और उसकी प्रतिष्ठा भी अधिक थी. उस समय तो यह बात समझ में आती थी कि देश गुलाम था और अंग्रेजों एवं अंग्रेजी का ही बोलबाला था, लेकिन अब भी स्थिति कुछ बदली नहीं है.

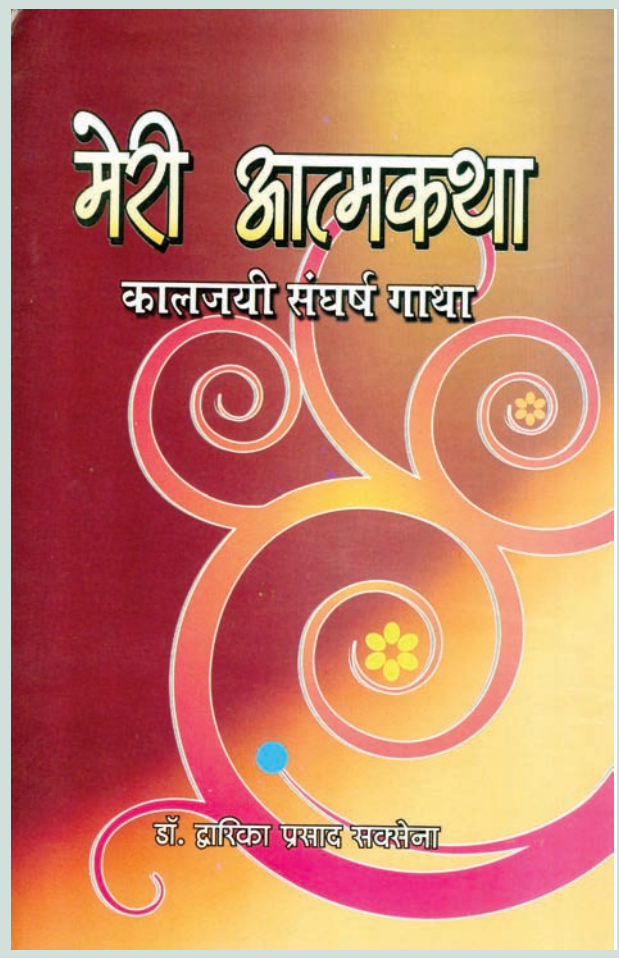

जहां भी एक तरह का पेशा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होता है, वहां अंग्रेजी वालों की प्रतिष्ठा भी अधिक है और उन्हें पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं. आज़ादी के साठ साल भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. लेकिन पारिवारिक वजहों से लेखक को दिल्ली रास नहीं आई और वह फिर से अपने गांव लौट आया. गांव लौटते ही एक बार फिर शुरू होता है लेखक का संघर्ष. अच्छी–भली नौकरी छोड़कर गांव लौटना और फिर से पढ़ाई की इच्छा ज़ाहिर करना दोनों परिवारों के विरोध का कारण बना, लेकिन कहते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर कुछ करने की सोच ली है. उनके साथ भी यही हुआ और तमाम कठिनाइयों के बावजूद लेखक इंटरमीडिएट, बीए, एमए पास करता चला गया. अंतत: उसे बलवंत राजपूत कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी मिल गई. नौकरी मिलने के प्रसंग में भी लेखक ने उस वक़्त समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था की गहरी जड़ों की ओर इशारा किया है. इस बीच उनके जीवन में संघर्ष के कई पड़ाव आए, जिसे इस छोटे से लेख में समेटना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा है. इसके लिए पाठकों को अग्रवाल पब्लिकेशंस, आगरा से यह आत्मकथा मंगवा कर पढ़नी होगी. द्वारिका प्रसाद सक्सेना की इस किताब को पढ़ते हुए मुझे इस बात का अफ़सोस रहा कि मैं इनके साहित्य लेखन से परिचित क्यों नहीं रहा. इस आत्मकथा के अलावा द्वारिका जी की लगभग दो दर्जन किताबें प्रकाशित हैं, जो जयशंकर प्रसाद से लेकर दिनकर तक, पद्मावत से लेकर कामायनी तक के विषयों को समेटती हैं.

द्वारिका जी की आत्मकथा को पढ़ने के बाद मेरी दो धारणाएं और पुष्ट हुईं. पहली यह कि हिंदी के लेखकों का मूल्यांकन उनके जीवनकाल में नहीं हो पाता है. उन्हें उनके लेखन के हिसाब से प्रसिद्धि भी नहीं मिल पाती. निराला और मुक्तिबोध इसके दो बेहतरीन उदाहरण हैं. दोनों का मूल्यांकन उनकी मृत्यु के बाद ही हो पाया. उसी तरह सुदीप बनर्जी की कविताओं के मूल्यांकनपरक लेख उनके मरणोपरांत ही छपे. ये तो चंद उदाहरण हैं, जबकि हिंदी की विशाल दुनिया में कई ऐसे लेखक और कवि हैं, जो देश के सुदूर इलाक़ों में रहकर बेहतरीन रचनाएं लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंदी के पाठकों और आलोचकों की नज़रों से ओझल हैं.

मेरी जो दूसरी धारणा है, वह यह है कि अगर कोई हिंदी का लेखक वामपंथी या फिर तथाकथित प्रगतिशील विचारधारा में यक़ीन नहीं रखता है तो हिंदी के प्रगतिवादी आलोचक उसे साज़िशन हिंदी के हाशिए पर रखते हैं. द्वारिका जी की आत्मकथा में इस बात के संकेत तो नहीं हैं, लेकिन इस बात के संकेत ज़रूर हैं कि वह वामपंथी विचारधारा के नहीं थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ़ उनका झुकाव था. उसकी वजह से वह जेल भी गए. हो सकता है कि हिंदी के प्रगतिशील आलोचकों ने इस वजह से उन पर और उनके लेखन पर कोई ध्यान नहीं दिया. कुल मिलाकर अगर हम एक कृति के रूप में विचार करें तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना की आत्मकथा को हिंदी में आई कुछ श्रेष्ठ आत्मकथाओं में शुमार किया जा सकता है. यह आत्मकथा चार भागों में है, लेकिन जो शुरुआत के दो खंड हैं, वे अद्भुत हैं. मराठी और दलित लेखकों की आत्मकथाओं से जिस संघर्ष की तस्वीर सामने आती है, वह कमोबेश एक ही किस्म की होती है, लेकिन यहां लेखक का संघर्ष दलित लेखकों से इतर ज़मीनी और यथार्थवादी है. इस लिहाज़ से भी यह आत्मकथा पठनीय है. आलोचक उनकी भाषा को लेकर एतराज जता सकते हैं, उनकी आत्मकथा में उनकी आत्म–श्लाघा को लेकर भी सवाल खड़े कर सकते हैं. अपनी आत्मकथा में एक–दो जगह पर द्वारिका जी ने अपने आपको विश्व प्रसिद्ध लेखक लिख दिया है, लेकिन अगर हम इस कृति के कथ्य पर विचार करें और लेखक की अदम्य जिजीविषा के बरक्श उसे रखकर देखें तो उनको इतना लिखने की छूट दी जा सकती है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

प्रदीप सौरभ

रेखा काफी चटकीली थी. पाउडर, बिंदी, लिपस्टिक उसे बहुत पसंद थे. काम के बाद बाल संवारना वह नहीं भूलती थी. मुन्नी से ज़्यादा साफ–सुथरी रहती थी. उसकी नज़र भी पूरे काम पर थी, लेकिन उसकी अकड़ ने उसे व्यक्त नहीं होने दिया. आनंद भारती ने उसका हिसाब करते वक़्त पंद्रह दिन के अलग से पैसे दे दिए, ताकि इस बीच वह काम तलाश ले.

मुन्नी ने घर का मोर्चा संभाल लिया था. आनंद भारती अपने को हलका महसूस कर रहे थे. खाने की समस्या अभी उनके सामने बनी हुई थी. मुन्नी से वह खाना नहीं बनवाना चाहते थे. साफ़– सुथरी वह नहीं दिखती थी. वैसे सुंदर थी. लेकिन पैसे आने के साथ–साथ उसमें भी बदलाव आ रहा था. कभी–कभी उसके माथे पर बिंदी चमकती. लिपस्टिक भी लगाने लगी थी. टूटी स्लीपर भी बदल कर उसने प्लास्टिक की नई चप्पलें ख़रीद ली थीं. सलवार– कमीज़ भी साफ़–सुथरी हो गई थी.

आनंद भारती अब उसे चाबी सौंपना चाहते थे. चाबी देने का मतलब साफ़–सफ़ाई से लेकर खाने तक का पूरा इंतज़ाम.

एक दिन उन्होंने उससे कहा, मुझे जल्दी जाना है. क्या तुम आटा सान दोगी? वह मुन्नी को परखना चाहते थे.

इस पर वह कुछ नहीं बोली. सीधे किचन में गई और आटा निकाल कर उसने उसे सान दिया. आनंद भारती को लगा कि उनका चलाया तीर सही निशाने पर लग गया है.

इसी दौरान उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जाना था. घर में बड़ी संख्या में पेड़–पौधे थे. जून की दहला देने वाली गरमी थी. आदमी तो तप कर जी सकता था, लेकिन पानी के बिना पौधों का ज़िंदा रहना मुश्किल था. पूरे तीन दिन की बात थी. उन्हें लगा कि मुन्नी को चाबी देने का यही सही वक़्त है. वह बोले, मैं तीन दिन के लिए बाहर जा रहा हूं. चाबी तुम्हें दे दूंगा. तुम पेड़–पौधों का ध्यान रखना. पानी नहीं मिलेगा तो सारे मर जाएंगे.

इस पर वह तपाक से बोली, न साहब न! घर की ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकती. मेरे पीछे चोरी–चकारी हो जाए तो मैं आपको क्या जवाब दूंगी.

कुछ नहीं होगा. कुछ होगा भी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आनंद भारती ने उसे आश्वस्त किया.

काफी समझाने–बुझाने के बाद वह मान गई. उसने चाबी पकड़ ली.

आनंद भारती इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए. इलाहाबाद हमेशा उन्हें भावुक करता है. गंगा–यमुना–सरस्वती की उस रेती

गतांक से आगे

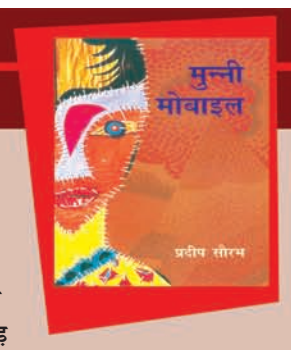

में आनंद की कई यादें हैं, जो गाहे–बगाहे आनंद के दिल पर दस्तक देती रहती हैं. आनंद कभी उस दस्तक पर अपने जीवन के उस पड़ाव के किवाड़ खोल देते हैं और कभी उस थाप को अनसुना कर अपने दिमाग़ की चाबी से दूसरा दरवाज़ा खोल आगे निकल जाते हैं. कमबख्त इलाहाबाद से उनका रिश्ता आंख मिचौनी का सा रहा है. इलाहाबाद में उनकी विश्वविद्यालय की शिक्षा हुई. उनके युवाकाल के कई वर्ष यहीं बीते. अपने संघर्ष का एक लंबा समय उन्होंने यहीं बिताया. रूमानी एहसासों से भरा मुहब्बत का संगम भी यहीं हुआ, जिसे वह अपनी पहली मुहब्बत कह सकते हैं. वह प्यार, जिसका अर्थ वह सही समय पर परिभाषित नहीं कर पाए या उसकी परिभाषा आज भी हर सीमा से परे है उनके लिए.

अगले अंक में जारी...

परस्पर अविश्वास से गहराया लेह का सांप्रदायिक विवाद

योगी सिकंद

वर्ष 1989 के आसपास कश्मीर में आतंकवाद के उदय के बाद लेह की बौद्ध जनता को यह अंदेशा होने लगा कि जम्मू एवं कश्मीर में उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है. अधिकांश बौद्धों को यह डर सताने लगा कि मुस्लिम समुदाय पूरे इलाक़े पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है. इस डर के पीछे दो वजहों की अहम भूमिका थी. पहली, लद्दाख सहित पूरे जम्मू–कश्मीर राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता अथवा पाकिस्तान के साथ उसके विलय की मांग. दूसरी वजह यह थी कि लेह के मुक़ाबले कारगिल क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि की दर काफी ज़्यादा थी. इसका स्पष्ट मतलब यही था कि अगले कुछ दशकों में बौद्ध समुदाय लद्दाख में अल्पमत में आ जाता. इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा विकास योजनाओं एवं सरकारी नौकरियों में बौद्धों के साथ भेदभावपूर्ण नीति ने इस डर में और इज़ाफ़ा किया. लेह के लिए प्रांतीय स्वायत्तता की मांग अब तेज़ी से सांप्रदायिक रंग लेती जा रही थी और इसे बौद्धों एवं मुस्लिमों के बीच आपसी संघर्ष के नज़रिए से देखा जाने लगा था. जुलाई 1989 में लेह में एक बौद्ध और चार मुस्लिम युवकों के बीच एक साधारण झड़प ने इतना विषाक्त रूप धारण कर लिया कि पूरे लेह में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया. जम्मू–कश्मीर पुलिस बल पर यह आरोप लगा कि उसने बौद्ध प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई. ऐसे आरोप भी लगे कि पुलिस बल के जवान ज़बरदस्ती बौद्धों के घर में घुस आए, उनके धार्मिक स्थलों पर तोड़फोड़ की और संपत्तियां लूट लीं. पुलिस की इन ज़्यादतियों के चलते एलबीए (लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन) एक बार फिर लद्दाख के लिए अलग संवैधानिक व्यवस्था और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने की मांग करने लगा. इसके ठीक बाद एलबीए ने मुस्लिम समुदाय के पूर्ण सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की घोषणा कर दी.

बहिष्कार की यह घोषणा शुरू में कश्मीरी मुस्लिमों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जो स्थानीय प्रशासन में प्रभावशाली भूमिका में थे. इसके अलावा सुन्नी मुसलमान भी एलबीए के निशाने पर थे, जो लेह शहर की अर्थव्यवस्था में गहरी दख़ल रखते थे. सुन्नी मुसलमानों को कश्मीरी एजेंट के रूप में देखा जाता था, क्योंकि वे बौद्धों की स्वायत्तता

की मांग का विरोध करते थे. बाद में बाल्टियों को भी बहिष्कार के दायरे में शामिल कर लिया गया, क्योंकि वे सुन्नियों के समर्थन में आ गए थे और इस संघर्ष को सांप्रदायिक पुट देने में सबसे आगे थे. बहिष्कार की इस घोषणा को 1992 में वापस ले लिया गया, क्योंकि भारत सरकार ने एलबीए को स्पष्ट रूप से बता दिया कि ऐसा न होने पर वह उसकी मांगों पर विचार नहीं करेगी. इसके बाद एलबीए और लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन (एलएमए) के बीच एक समझौता हुआ. एलएमए शिया और सुन्नी, दोनों ही समुदायों का प्रतिनिधित्व करती थी. काफी जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने लेह ऑटोनोमस हिल काउंसिल का गठन किया, जिसके अंतर्गत लेह को व्यापक स्वायत्तता हासिल हुई. इसके साथ ही एलबीए की अधिकांश मांगें पूरी हो गईं.

1995 में जब लेह ऑटोनोमस हिल काउंसिल का गठन किया गया तो उसी समय कारगिल के लिए भी ऐसे ही एक निकाय के गठन का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन कारगिल के लोगों ने इसे मानने से इंकार कर दिया. उनका मानना था कि इससे कश्मीर सरकार के अधिकारों का हनन होता है, जिसे वे अपना दोस्त समझते थे. बाद के दिनों में लेह में विकास की तेज़ गति को देखते हुए वे इसके लिए राजी हो गए और 2003 में कारगिल ऑटोनोमस हिल काउंसिल का गठन किया गया, लेकिन कारगिल के जांस्कर क्षेत्र में रहने वाले बौद्धों का एक छोटा तबका इसके विरोध में खड़ा हो गया. बौद्धों को लगा कि यह उनके हितों के ख़िलाफ़ है और वे अपने लिए अलग स्वायत्तशासी क्षेत्र की मांग करने लगे. लेह ऑटोनोमस हिल काउंसिल के गठन के बाद शुरुआत में लगा कि अधिकतर समस्याएं सुलझ गई हैं, लेकिन 2000 में जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव रखकर यह मांग की कि जम्मू– कश्मीर को 1953 के पहले की व्यवस्था की तरह भारतीय संघ के अंतर्गत स्वायत्तशासी क्षेत्र का दर्जा दिया जाए. इस प्रस्ताव के साथ ही एलबीए फिर विरोध में खड़ी हो गई और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की मांग करने लगी. एलबीए की यह मांग इस डर पर आधारित थी कि 1953 के पूर्व की व्यवस्था फिर से बहाल होने पर लद्दाख कश्मीर के एक उपनिवेश के रूप में तब्दील होकर रह जाएगा.

जून 2000 में एक सप्ताह तक चले आंदोलन के बाद एलबीए के अध्यक्ष शेरिंग सांफेल ने ज़ोर देकर कहा कि समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए. उन्होंने यह घोषणा भी की कि मांग न माने जाने पर लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए एलबीए संयुक्त राष्ट्र की शरण में जाएगी. एलबीए की युवा शाखा के नेता लोबजांग न्यांटक ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि भगवान में गहरी आस्था रखने वाले बौद्धों की मांगों को अगर नहीं माना गया तो वे हथियार उठाने को मजबूर हो जाएंगे और इसके लिए प्रशासन ज़िम्मेदार होगा. इस हिंसा का स्वरूप बेशक धर्म विरोधी लगे, लेकिन इसका असल उद्देश्य अपनी पहचान बनाए रखना है. कोई आश्चर्य नहीं कि राज्य को धर्म के आधार पर तीन हिस्सों में बांटने की एलबीए की मांग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुस्लिमों के ख़िलाफ़ अपने अभियान में वे एलबीए को सहयोगी के रूप में देखते थे. लेह की बहुसंख्यक बौद्ध जनता केंद्र शासित प्रदेश की मांग का समर्थन करती है, जबकि लेह में रहने वाले मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा भी इसके समर्थन में है. संभव है कि ज़्यादा विकसित बौद्धों के डर से कुछ स्थानीय मुस्लिम समुदाय इसका विरोध कर रहे हों, लेकिन वे भी इसे खुलेआम प्रदर्शित नहीं करना चाहते. इसी तरह कारगिल की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे का विरोध करती है. उसे डर है कि लेह के मुक़ाबले कम विकसित कारगिल इस केंद्र शासित प्रदेश में शामिल होने से बौद्धों के प्रभुत्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था में उपेक्षा का शिकार हो जाएगा. फिर वे मुस्लिम बहुल कश्मीर से भी अलग नहीं होना चाहते. हालांकि वे घाटी में चल रहे अलगाववादी आंदोलन के ख़िलाफ़ हैं. धार्मिक रंग में रंगी यह राजनीतिक समस्या ज़्यादा गंभीर इसलिए भी है, क्योंकि पूरा लद्दाख क्षेत्र, जिसमें कारगिल और लेह भी शामिल है, एक ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है. चुनावों के दौरान बौद्ध और शिया नेता वोटों के लिए मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं को भड़काने से बाज नहीं आते. कई लोगों का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ाने से, जिसके अंतर्गत शिया बहुल कारगिल और बौद्ध बहुल लेह के लिए अलग–अलग संसदीय क्षेत्र हों, समस्या का समाधान निकल सकता है. या फिर सीटों की रोटेशन प्रणाली से भी समस्या का हल निकाला जा सकता है.

लेह में सांप्रदायिक अलगाव का मूल कारण बेशक़ राजनीतिक है, लेकिन इसके साथ धार्मिक पहलू भी जुड़े हैं. देश के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में भी राजनीतिक दल धर्म का इस्तेमाल लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं, जिसके चलते दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की भावना और बढ़ जाती है. इसके अलावा अधिकांश धार्मिक नेता अन्य धर्मों और उनके अनुयायियों को ग़लत निगाहों से देखते हैं. हालांकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो इसका विरोध करते हैं और विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच बेहतर संबंधों के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मोरारका आर्गेनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड एक बेहतरीन, चिर परिचित, जांचा-परखा और भरोसेमंद नाम है.

ऑर्गेनिक फूड
स्वस्थ जीवन का राज

आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों के पास समय की कमी है. इसकी वजह से लोग अपने खाने-पीने का भी ठीक तरीक़े से ध्यान नहीं रख पाते हैं. प्रतिस्पर्धा और विकासपरक जीवन में व्यस्त होने के कारण लोग बिना पौष्टिकता की परवाह किए कुछ भी खा-पी लेते है. इसके साथ ही खाने पीने का कोई निर्धारित समय ही नहीं रहता है. लोग स्वस्थ और हाईजीनिक खाना के बजाए पेट भरने के उद्देश्य से खाना खाते हैं. भोजन के प्रति अनदेखी से लोगों के स्वास्थ में लगातार गिरावट दर्ज़ किया जा रहा है. ऐसे में अच्छी सेहत के लिए ऑर्गेनिक फूड एक अच्छा विकल्प है. और इस क्षेत्र में मोरारका ऑर्गेनिक फूड प्राईवेट लिमिटेड एक बेहतरीन, चिर परिचित, जांचा परखा और भरोसेमंद नाम है. यह संस्थान ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थो को उचित पैकिंग में नियत व उचित दामों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है. नोएडा के उपभोक्ताओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए नोएडा के इंदिरा मार्केट एफ-51 के सामने सेक्टर 27 में इस संस्थान ने एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुरेका स्टोर खोला है. यहां सभी प्रकार के ऑर्गेनिक फूड जैसे दाल, चावल, गेहूं, आटा, मसाले, घी व कुकीज आसानी से उपलब्ध हैं. इस स्टोर के मालिक हरीश कुमार सुरेका के अनुसार इस तरह के खाद्य पदार्थ की अधिक मांग व कम उपलब्धता ने आकर्षित किया है. वह कहते हैं कि वे पूरी ईमानदारी से इस सेवा के माध्यम से मानवमात्र की सेवा को तत्पर है तथा श्री कमल मोरारका ऑर्गेनिक फूड प्राइवेट लिमिटेड के सूत्रधार है जिनके दिशा निर्देशों व स्वप्नों को वह साकार करेंगे.

तकनीक से हो दोस्ती

तकनीक के जितने लाभकारी प्रभाव देखे जाते हैं उतने ही नुक़सानदायक प्रभाव भी देखने को मिलता है. लेकिन हमारे जीवन में सुबह आंख खोलने से लेकर रात को आंख बंद करने तक तकनीकी उपकरणों से जुड़ाव देखा जा सकता है. चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या वाशिंग मशीन ऐसी अनेक इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है. इनका नुक़सान भी कम नही है इस नुक़सान को कम करने के लिए निर्माता कंपनियां आए दिन नए नए प्रयोग करती ही रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए एलजी ने नए प्रयोग किए हैं. एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने बेहतर स्वास्थ के लिए हेल्थ प्लस अभियान की घोषणा की है और इसके लिए नारा दिया है-अपग्रेड योर लाइफ इन एवरी वे यानी अपने जीवन को हर तरह से अपग्रेड कीजिए. एलजी हेल्थप्लस उपकरण हर तरह से स्वस्थ जीवनशैली के लिए है. इनमें खाना बनाना, कपड़े धुलना, घर को साफ़ करना शामिल है. एलजी का टॉप माउंट रेफ्रीजरेटर ग्रीन आयन डोर कूलिंग और विटामिन प्लस जैसी ख़ासियतों से लैस है. इसका थ्री वे कूलिंग सिस्टम तीन दिशाओं से हवा फेंकता है जिससे फ्रीज में रखा सामान कम समय में ठंडा होता है और ग्रीन आयन सिस्टम खाद्य पदार्थो को बिलकुल ताज़ा रखता है. दुर्गंध मुक्त करने के लिए वेंटीलेशन कोटेड ग्रीन केटचिंस का उपयोग किया गया है. ग्रीन आयन सिस्टम खाद्य पदार्थों को ख़राब करने वाले बैक्टीरिया और फुंगी को मार देता है. इसका विटामिन प्लस टेक्नोलॉजी फलों और सब्जियों पर विटामिन छिड़कता है ताकि वे लंबे वक़्त तक ताज़ा बने रहें. इसके अलावा, मॉयस्ट बैलेंस क्रिस्पर नमी बनाए रखता है.

कपड़े धुलने वाली ख़ास फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन की स्टीम टेक्नोलॉजी एलर्जी से होने वाली बीमारियों का कारण बनने वाले सभी एलर्जेन को ख़त्म करता है और रोगाणुओं को मार डालता है. अस्थमा एंड एलर्जी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका से प्रमाणपत्र पाने वाला यह पहला वाशिंग मशीन है.

इसमें 20 मिनट का एक स्टीम स्प्रे चक्र होता है जिससे कपड़ों के रिंकल और दुर्गंध ख़त्म हो जाते हैं. टब क्लिनिंग के फंक्शन से एक बटन दबाकर टब के अंदर और बाहर के हिस्से को आसानी से साफ़ करता है और फफुंदी के विकास और टब के अंदर से आने वाले दुर्गंध को रोकता है. खाना बनाने वाले उपकरण में एलजी माइक्रोवेव ओवन में स्टीमिंग की पूरी प्रक्रिया के दौरान स्टीमशेफ से नमी और पोषक तत्व दोनों की रक्षा होती है. इससे तैयार होने वाला भोजन स्वास्थकर और स्वादिष्ट होता है.

ई-वेस्ट का ख़तरा

यूरोप और अमेरिका की तरह अब भारत भी ई-वेस्ट की गंभीर समस्या से जूझ रहा है. एक ओर यूरोपीय एवं अमेरिकी देशों ने अपने ई-वेस्ट को भारत में डंप करने का अड्डा बना लिया है, वहीं दूसरी ओर भारत में ई-वेस्ट की समस्या से निपटने का कोई सशक्त प्रबंधन नहीं है. सरकार ने अनियोजित और अव्यवस्थित तरीक़े से होने वाली रीसाइकलिंग को ग़लत ठहरा दिया है, लेकिन इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं. विज्ञापनों, लेखों और दूसरे माध्यमों से आम जनता तक ई-वेस्ट की ग़लत रीसाइकलिंग से होने वाले नुक़सान के बारे में बताया तो जा रहा है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है. हमारे देश में ई-वेस्ट को ठिकाना लगाने के लिए कोई मजबूत तंत्र मौजूद नहीं है. हाल यह है कि सरकार द्वारा लाया गया क़ानून असरदार साबित नहीं हो रहा है.

अनियोजित-अव्यवस्थित तरीक़े से होने वाली रीसाइकलिंग पर रोक नहीं लग पाई है. हर साल भारत में 3,50,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा हो जाता है और 50,000 टन इंपोर्ट होता है. ई-वेस्ट का आयात ग़ैरक़ानूनी है, इसलिए यह स्क्रैप, सेकंड हैंड इलेक्ट्रिकल एपलायंसेज एवं अन्य चीजों के रूप में भारत में आता है. यह सारा ई-वेस्ट हमारे देश में एकत्र हो जाता है. देश के अनियोजित क्षेत्र द्वारा इस ई-वेस्ट का 90 प्रतिशत हिस्सा रीसाइकल कर दिया जाता है, लेकिन अनियोजित तरीक़े से रीसाइकल करना काफ़ी नुक़सानदायक है. भारत में वर्ष 2007 में लगभग 3,30,000 टन ई-वेस्ट एकत्र हुआ था. यह लगभग 110 मिलियन लैपटॉप के बराबर है.

ई-वेस्ट का लगभग दस प्रतिशत हिस्सा हर साल सही तरह से रीसाइकल हो जाता है, जबकि बाकी बचा 90 प्रतिशत ग़लत तरीक़े से रीसाइकल होकर हमारे लिए नुक़सानदायक हो जाता है. आम आदमी की भाषा में ई-वेस्ट का मतलब है ख़राब हो चुका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामग्री, जिसे मरम्मत करके दोबारा काम के लायक नहीं बनाया जा सकता. इस श्रेणी में बेकार इलेक्ट्रिक वायर, पुराना रेडियो एवं फ्रिज जैसी चीजें आती हैं. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अपनी सामान्य अवस्था में हानिकारक नहीं होता, जबकि इसे रीसाइकल करने की प्रक्रिया में कई नुक़सान झेलने पड़ सकते हैं. किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के अंदर कई तरह के तार, सर्किट, मेटल्स, प्लास्टिक और दूसरे तत्व होते हैं. अगर ई-वेस्ट का ग़लत तरीक़े से निपटारा किया जाए तो यह लोगों के स्वास्थ्य और वातावरण पर काफ़ी ग़लत असर करता है. देश के लिए चुनौती यह है कि ई-वेस्ट को सही तरीक़े से रीसाइकल किया जाए, लेकिन ई-वेस्ट से निपटने का काम कबाड़ वालों के हाथ में है. मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफारमेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक विनी मेहता कहते हैं कि ई-वेस्ट को रीसाइकल करने का काम कर रहे अविकसित क्षेत्र का दायरा इतना सीमित है कि सही प्रोसेसिंग यहां संभव नहीं है. ई-वेस्ट की सही तरीक़े से रीसाइकलिंग करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, जो ज़ाहिर तौर पर इस क्षेत्र के पास नहीं होती.

सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र के लोगों को ई-वेस्ट एकत्र करने और उसे डिसमेंटल करने के काम में लगाया जाए. उसके आगे की प्रक्रिया इंडस्ट्री में पूरी कराई जाए. लोगों के जीवन से खेलने से बेहतर है कि कोई मजबूत तकनीक लाई जाए, जिससे छोटे स्तर पर भी रीसाइकलिंग की जा सके. ज़रूरत यह है कि रीसाइकलिंग का ऐसा तरीक़ा अपनाया जाए, जिससे वातावरण को नुक़सान न पहुंचे. निर्माता कंपनियों पर भी ई-वेस्ट के प्रबंधन में भागीदार बनाया जाए और वे अपने प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग का जिम्मा ख़ुद उठाएं. सेंटर फॉर साइंस एंड एजूकेशन रिसर्च के अनुसार, भारत में ई-वेस्ट रीसाइकलिंग के सबसे बड़े अड्डे सीलमपुर दिल्ली और मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हैं. सरकार द्वारा प्रस्तावित नियमों के तहत भारत में पहली बार उपभोक्ताओं से ई-वेस्ट वापस लेने की जिम्मेदारी निर्माता कंपनियों को दी जाएगी. हालांकि इस बारे में कोई व्यवस्थित मॉडल नहीं उतारा गया है, लेकिन निर्माताओं को दी जाने वाली यह जिम्मेदारी सराहनीय होगी. अभी तक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने सिर्फ़ नोएडा स्थित एटेरो रीसाइकलिंग कंपनी को ही ई-वेस्ट प्रोसेस करने का लाइसेंस दिया है, लेकिन देश में उत्पन्न होने वाले ई-वेस्ट की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उसे रीसाइकल करने के लिए एक कंपनी काफ़ी नहीं है.

मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन फॉर इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी के निदेशक विनी मेहता कहते हैं कि ई-वेस्ट को रीसाइकल करने का काम कर रहे अविकसित क्षेत्र का दायरा इतना सीमित है कि सही प्रोसेसिंग यहां संभव नहीं है. ई-वेस्ट की सही तरीक़े से रीसाइकलिंग करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है, जो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र के पास नहीं होती.

रीतिका सोनाली
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

विश्वकप फुटबॉल का सफर 1930 से शुरू हुआ और तब से लेकर अब तक 18 बार इसका आयोजन हो चुका है.

फुटबॉल का महाकुंभ

फुटबॉल विश्वकप में जोश, जुनून और रोमांच का ऐसा संगम देखने को मिलता है कि खिलाड़ी तो खिलाड़ी, दर्शक भी इसमें गोते लगाते रहते हैं. शायद पूरे विश्व में फुटबॉल प्रेमियों की संख्या अन्य खेलों की तुलना में सबसे अधिक है. इसलिए विश्वकप की घोषणा होते ही उसके दीवानों में ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है. मैच देखने के लिए मैदान में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है. वे जोश से इतना लबरेज हो जाते हैं कि कभी-कभी मैदान में ही उलझ पड़ते हैं. विश्वकप फुटबॉल 2010 का भी आग़ाज़ हो चुका है. धीरे-धीरे इसका रंग दर्शकों पर चढ़ता जा रहा है. हर टीम पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर रही है, ताकि जीत उसी की हो.

विश्वकप फुटबॉल का सफर 1930 से शुरू हुआ और तबसे लेकर अब तक इसका 18 बार आयोजन हो चुका है. 19वीं बार इस विश्वकप का आयोजन दक्षिण अफ़्रीका में शुरू हो चुका है. यह 11 जून से 11 जुलाई 2010 तक चलेगा. विश्वकप के लिए दक्षिण अफ़्रीका को दुल्हन की तरह सजाया गया है और फुटबॉल प्रेमी भी उसी रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं. हालांकि दक्षिण अफ़्रीका के लिए मेज़बानी की राह आसान नहीं थी. यदि छह साल पहले उसने अंतिम समय में चार वोट से बाज़ी न मारी होती तो विश्वकप की मेज़बानी करने का उसका सपना पूरा न हो पाता. फीफा की महाद्वीपीय रोटेशन प्रक्रिया के तहत फुटबॉल विश्वकप 2010 का आयोजन अफ़्रीका महाद्वीप में होना था, बावजूद इसके उसकी राह आसान नहीं थी. मेज़बानी को लेकर उसे मोरक्को से कड़ी टक्कर मिली थी. इन दोनों के अलावा नाइज़ीरिया एवं मिस्र और लीबिया एवं ट्यूनीशिया ने संयुक्त रूप से दावेदारी पेश की थी, मगर फीफा की ओर से अनुमति न मिलने के कारण लीबिया और ट्यूनीशिया दौड़ से बाहर हो गए. उसके बाद विश्वकप के आयोजन को लेकर मुक़ाबला त्रिकोणीय हो गया. आयोजन का स्थान सुनिश्चित करने के लिए ज्यूरिख में 15 मई 2004 को फीफा ने वोटिंग कराई, जिसमें दक्षिण अफ़्रीका को 14, मोरक्को को 10 मत मिले, जबकि मिस्र को एक भी वोट नहीं मिला. इस तरह अफ़्रीका महाद्वीप में पहली बार हो रहे फुटबॉल विश्वकप की मेज़बानी दक्षिण अफ़्रीका को सौंप दी गई. हालांकि इससे पहले 2006 के टूर्नामेंट के लिए भी उसने दावेदारी पेश की थी, लेकिन जर्मनी से वह एक मत से हार गया था. ये तो हुईं मेज़बानी की बातें. अब जरा सशक्त टीमों पर नज़रें दौड़ाएं तो पता चलता है कि विश्वकप में खेलने का सम्मान अब तक 76 देशों को मिल चुका है, लेकिन केवल सात देश ऐसे हैं, जो फाइनल की बाधा पार कर चैंपियन बनने में सफल रहे.

ब्राजील का विश्व फुटबॉल पर ज़बरदस्त दबदबा रहा है, लेकिन इटली और जर्मनी जैसी टीमें उसके वर्चस्व को समय-समय पर चुनौती देती रही हैं. अगर पिछले टूर्नामेंटों पर ग़ौर करें तो ब्राजील एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने सभी विश्वकप में शिरकत की और वह रिकॉर्ड पांच बार चैंपियन बना. इसके अलावा दो बार उपविजेता और दो बार तीसरे स्थान पर रहा. यानी 18 में से नौ बार टीम को पोडियम पर जगह मिली. ब्राजील से अधिक केवल जर्मनी दस बार पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रहा. वह तीन बार चैंपियन, चार बार उप विजेता और तीन बार तीसरे स्थान पर रहा. इस तरह दोनों देशों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली. चार विश्व खिताब के साथ मौजूदा चैंपियन इटली दूसरी सबसे सफल टीम है, जो दो बार उपविजेता और एक बार तीसरे स्थान पर रही. इटली ने 2006 विश्वकप में फ्रांस को फाइनल में हराकर अपना चौथा विश्व खिताब जीता था.

जर्मनी ने अपने शानदार फुटबॉल इतिहास में 1954, 1974 और 1990 में विश्वकप जीता. उसने 2006 में विश्वकप की मेज़बानी की थी और उसे तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था. जर्मनी को सेमी फाइनल में इटली से 0-2 से पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन तीसरे स्थान के मैच में उसने पुर्तगाल को 3-0 से हराया था. पिछले टूर्नामेंटों की तरह उसे इस बार खिताब के प्रबल दावेदारों में शामिल नहीं किया जा रहा है. फिर भी उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. हालांकि क्वालीफाइंग दौर में जर्मनी का प्रदर्शन लाजवाब रहा था. उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों पर 26 गोल दागे थे और सिर्फ़ पांच गोल खाए थे. जर्मनी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात मिरोस्लाव क्लोस और लुकास पोदोलस्की जैसे स्टार स्ट्राइकरों का फॉर्म में न होना है. कप्तान माइकल बलाक के चोटिल होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाने से भी उसकी परेशानियां बढ़ गई हैं. जर्मनी को अपनी टीम की तरफ़ से ऐसी प्रतिभाएं मैदान में उतारनी होंगी, जो उसे नाकआउट चरण में ले जा सके. वैसे स्ट्राइकर स्टीफन कीसलिंग टीम की फारवर्ड पंक्ति को मज़बूती दे सकते हैं, लेकिन जर्मनी को क्लोस और पोदोलस्की के फॉर्म में लौटने की पूरी उम्मीद रहेगी. पिछले विश्वकपों के आधार पर जर्मनी को पूरी तरह ख़ारिज़ करना ग़लत होगा और इस टीम में ग्रुप चरण से नाकआउट चरण में पहुंचने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए टीम को चुनौतियों का एवरेस्ट लांघना होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ग्रुप-A
- साउथ अफ़्रीका
- मेक्सिको
- उरुग्वे
- फ्रांस

ग्रुप-B
- अर्जेंटीना
- नाइजीरिया
- कोरिया रिपब्लिक
- ग्रीक

ग्रुप-C
- इंग्लैंड
- यूएसए
- अल्जीरिया
- स्लोवेनीया

ग्रुप-D
- जर्मनी
- आस्ट्रेलिया
- सर्बिया
- घाना

ग्रुप-E
- नीदरलैंड
- डेनमार्क
- जापान
- कैमरून

ग्रुप-F
- इटली
- पराग्वे
- न्यूज़ीलैंड
- स्लोवाकिया

ग्रुप-G
- ब्राजील
- नॉर्थ कोरिया
- आइवरी कोस्ट
- पुर्तगाल

ग्रुप-H
- स्पेन
- स्विट्ज़रलैंड
- होंडुरस
- चिली

बीसीसीआई के लिए टैलेंट हंट है जिम्बाब्वे दौरा

जिम्बाब्वे अपने देश में क्रिकेट को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है. पिछले कुछ समय से इस अफ़्रीकी देश ने महज़ कीनिया, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान जैसे देशों के साथ ही क्रिकेट खेला है. ऐसे में अगर जिम्बाब्वे की मेज़बानी में भारत और श्रीलंका जैसे देश खेलने आते हैं तो निश्चित तौर पर यह उसके लिए ख़ुशी की बात थी. लेकिन, जिम्बाब्वे की ख़ुशी तब अचानक काफ़ूर हो जाती है, जब उसे पता चलता है कि टीम इंडिया यहां खेलने तो आ रही है, पर टीम इंडिया के सितारे नहीं आ रहे हैं. कुछ यही हाल श्रीलंकाई टीम का भी है, जिसके अनुभवी खिलाड़ी कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने को आराम दिया गया है. पहले के कार्यक्रम के अनुसार इस त्रिकोणीय मुक़ाबले की तीसरी टीम न्यूजीलैंड थी, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के जिम्बाब्वे में खेलने से इंकार किए जाने के बाद इसमें भारत को शामिल किया गया है. चयनकर्ताओं ने तो मानों जिम्बाब्वे दौरे को टीम इंडिया के लिए क्रिकेट प्रतिभा खोज की प्रयोगशाला ही बना डाला है. टीम इंडिया के ज़्यादातर अनुभवी और स्टार खिलाड़ियों को आराम दे दिया गया है. सुरेश रैना की कप्तानी में कई नए चेहरों को जिम्बाब्वे दौरे के लिए भेज दिया गया है. मतलब यह कि टीम इंडिया के लिए यह त्रिकोणीय सीरीज टैलेंट हंट का मंच बनने जा रही है, जहां अशोक डिंडा, विनय कुमार, पंकज सिंह और उमेश यादव जैसे नए तेज गेंदबाज़ों के पास ख़ुद को ज़हीर ख़ान, इरफान पठान और श्रीसंत का विकल्प साबित करने का मौक़ा होगा. ज़ाहिर है, इन युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौक़ा मिला है. विश्व कप के लिए महज़ नौ महीने का वक़्त बचा है. सुरेश रैना के लिए भी यह मौक़ा काफी अहम माना जा सकता है. एक भरोसेमंद बल्लेबाज़ को यह साबित करना होगा कि वह एक भरोसेमंद कप्तान बनने की भी काबिलियत रखता है. जिम्बाब्वे दौरे के लिए महेंद्र सिंह धोनी समेत आठ वरिष्ठ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. शायद ऐसा टी-20 में मिली हार और थकान की वजह से किया गया है.

काउंट डाउन शुरू हो चुका है. 28 मई से 9 जून के बीच होने वाले इस त्रिकोणीय मुक़ाबले में युवा और फिट भारतीय खिलाड़ी क्या चमत्कार दिखाते हैं, यह हर कोई देखना चाहेगा. क्रिकेटप्रेमियों एवं चयनकर्ताओं से लेकर ऐसे दर्शक भी, जिनकी क्रिकेट से ज़्यादा उसकी राजनीति में दिलचस्पी रहती है.

ऐसे में सुरेश रैना के लिए कप्तानी का यह ताज कांटों भरा भी हो सकता है. रैना को फिट और युवा खिलाड़ियों की टीम तो दी गई है, लेकिन इनमें से ज़्यादातर के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव नहीं है. हालांकि ये ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अपना प्रदर्शन इसलिए भी बेहतर करेंगे, ताकि किसी भी क़ीमत पर भारतीय टीम में अपनी जगह बना पाएं. विराट कोहली इस टीम के उपकप्तान हैं, जिन्हें टी-20 में जगह नहीं मिली थी. इसलिए कोहली भी इस श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे, ताकि वह आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बना सकें. गेंदबाज़ प्रज्ञान ओझा और लेग स्पिनर अमित मिश्रा भी अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को यह बताने की कोशिश करेंगे कि टी-20 में उन्हें न लेना चयनकर्ताओं की भूल थी. बल्लेबाज़ी की कमान तो यूसुफ पठान, रोहित शर्मा, रैना और दिनेश कार्तिक ही संभालेंगे. लेकिन तेज़ गेंदबाज़ी का क्या होगा? क्योंकि अशोक डिंडा, विनय कुमार, पंकज सिंह और उमेश यादव जैसे तेज़ गेंदबाज़ों के पास अनुभव नहीं है. हालांकि पंकज, प्रज्ञान और रोहित को जिम्बाब्वे में खेलने का अनुभव ज़रूर है. बहरहाल काउंट डाउन शुरू हो चुका है. 28 मई से 9 जून के बीच होने वाले इस त्रिकोणीय मुक़ाबले में युवा और फिट भारतीय खिलाड़ी क्या चमत्कार दिखाते हैं, यह हर कोई देखना चाहेगा. क्रिकेटप्रेमियों एवं चयनकर्ताओं से लेकर ऐसे दर्शक भी, जिनकी क्रिकेट से ज़्यादा उसकी राजनीति में दिलचस्पी रहती है.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 7 जून–13 जून 2010

काजोल वक़्त पर थायराइड टेस्ट कराती हैं और दूसरी होने वाली मांओं को भी यही सलाह देती हैं. वह काफ़ी वक़्त से समाजसेवा से जुड़ी रही हैं.

इफ्फी की ऑस्कर को टक्कर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को कान और ऑस्कर जैसे समारोहों के स्तर पर आयोजित करने का मन बना रहा है. ऐसा हुआ तो सिर्फ़ बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड और दुनिया के दूसरे देशों के कलाकार एवं फ़िल्में भी इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल पुरस्कारों के लिए जद्दोज़हद करते दिखेंगे. अब तक इफ्फी में दक्षिण अफ़्रीकी, लैटिन अमेरिकी, खाड़ी और एशियाई देशों की फ़िल्में ही नामांकित होती रही हैं. लिहाज़ा बॉलीवुड समेत भारत की सभी फ़िल्मों का मुक़ाबला इन देशों के साथ ही होता रहा है. यानी अब बॉलीवुड फ़िल्मों का मुक़ाबला हॉलीवुड फ़िल्मों से होगा. मंत्रालय की कोशिश यह होगी कि हॉलीवुड की प्रख्यात फ़िल्में, फ़िल्मकार और कलाकार भी इसमें शिरकत करने में गौरव महसूस करें. अंतरराष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव और पुरस्कारों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में गठित जाने-माने फ़िल्मकारों की समिति ने बीती पंद्रह मई को सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी को सौंपी गई रिपोर्ट में कई अहम सिफ़ारिशें की हैं. इसके तहत पुरस्कारों की रक़म बढ़ाने से लेकर पूरी दुनिया के लिए इफ्फी के द्वार खोल दिए जाएंगे. सूचना प्रसारण मंत्री बनने के बाद अंबिका सोनी ने भारतीय फ़िल्मों का स्तर ऊपर उठाने और पुरस्कारों की गरिमा बढ़ाने के लिए श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी. इसमें मोहन अगासे, सईं पराजपे, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान एवं नागेश कुपनूर जैसे फ़िल्मकार शामिल हैं. समिति ने छह माह में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी. रिपोर्ट में पुरस्कारों के चयन के लिए डबल ज्यूरी और कई कड़े मापदंड अपनाने सहित कई अहम सिफ़ारिशें की गई हैं, जिससे मंत्रालय भी लगभग सहमत है. अभी इफ्फी में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म को 40 लाख रुपये मिलते हैं, जिसमें 20-20 लाख रुपये निर्माता-निर्देशक के बीच बंट जाते हैं. इसी तरह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को 15 लाख, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता-अभिनेत्री को 10-10 लाख रुपये दिए जाते हैं. सूत्रों के मुताबिक़, इन पुरस्कार राशियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के लिहाज़ से कम बताते हुए इनमें भारी-भरकम बढ़ोत्तरी की सिफ़ारिश की गई है. फीचर फ़िल्म की ज्यूरी के लिए सोलह सदस्य रखने की सिफ़ारिश की गई है और गैर फीचर फ़िल्म की ज्यूरी में छह सदस्य. उद्देश्य यह है कि विदेशी फ़िल्मकार न सिर्फ़ यहां आएं, बल्कि पुरस्कारों को प्रतिष्ठित भी मानें. इसलिए पुरस्कार राशि बढ़ाने से लेकर फ़िल्मों के चयन के पैमाने और आयोजन की भव्यता तक पर ध्यान दिया जाएगा.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इस पहल से क्या बॉलीवुड में अच्छी फ़िल्में बनने लगेंगी? वैसे भी ज़्यादातर बॉलीवुड फ़िल्मों में नाच-गाने के अलावा कुछ नहीं होता है. हर दूसरी फ़िल्म हॉलीवुड फ़िल्मों की नकल होती है तो फिर किस तरह की प्रतियोगिता की उम्मीद की जा सकती है. नकल करने की आदत आज की नहीं है. यह 1969 में फ़िल्म आराधना से शुरू हुई थी. यह फ़िल्म 1946 में हॉलीवुड में बनी फ़िल्म टू ईच हीज ओन की नक़ल थी. उसके बाद हॉलीवुड की फ़िल्मों की नक़ल का जो सिलसिला बॉलीवुड में शुरू हुआ, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है. सवाल यह है कि क्या विदेशी फ़िल्मों की नक़ल करके बनाई गईं बालीवुड की फ़िल्में इस तरह के अवार्ड समारोह में शिरकत कर पाएंगी. हो सकता है कि मंत्रालय की इस पहल के बाद भारतीय फ़िल्मों का स्तर सुधर जाए. उम्मीद तो यही करनी चाहिए.

रीतिका सोनाली
ritika@chauthiduniya.com

बटरफ्लाई बनी शर्लिन

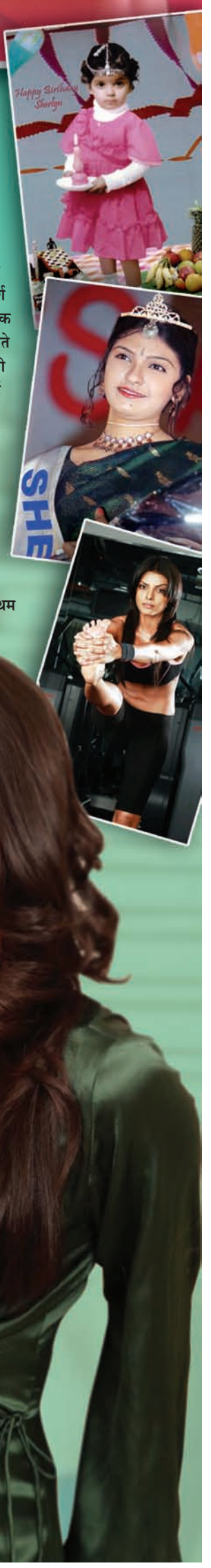

हॉट एंड सेक्सी शर्लिन चोपड़ा आए दिन नए कारनामों की वजह से मीडिया में छाई रहती हैं. वह अभी तक फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी कोई ख़ास जगह तो नहीं बना पाईं, पर सुर्खियों में छाए रहने का गुण बख़ूबी सीख गई हैं. शो बिग बॉस से शर्लिन को काफ़ी लोकप्रियता मिली. शर्लिन चोपड़ा भारत की जेनिफर लोपेज मानी जाती हैं. उन्होंने बॉलीवुड की दूसरी साइज जीरो अभिनेत्रियों को अपना आदर्श मानते हुए अपने फिगर को आकर्षक बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी भी करा ली है. वह अपनी आकर्षक फिगर और सेक्सी अदाओं को भुनाने में माहिर हैं. शिल्पा शेट्टी एवं बिपाशा बसु के रास्ते पर चलते हुए अब वह भी अपनी फिटनेस डीवीडी निकालने वाली हैं. इस पर उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया है. इसके लिए वह हफ्ते में छह दिनों का योगा सेशन ले रही हैं, जिसके लिए उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है. इससे वह परेशान नहीं हैं, बल्कि सुबह जल्दी उठने में उन्हें काफ़ी मजा आ रहा है. हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली शर्लिन बचपन से ही पढ़ाई में तेज थीं और स्वभाव से अंतर्मुखी भी. उनका साथ दोस्तों को काफ़ी बोर करता था. बचपन के उस हिस्से को शर्लिन कैटरपिलर कहती हैं. उन दिनों वह मोटी भी थीं. बड़े होने पर जब उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ अलग-ख़ास करने के लिए इस दुनिया में आई हैं, तब वह कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की कोशिश में जुट गईं और उसके बाद उनका नया अवतार सबके सामने है. वह अपने रूप परिवर्तन को मेटामॉरफोसिस नाम देती हैं. इसके अलावा वह आजकल सामाजिक कार्यों में भी ख़ूब रुचि ले रही हैं. अभी हाल में वह प्रथम नामक संस्था से जुड़ी हैं. यह संस्था ग़रीब बच्चों के शिक्षण के लिए काम करती है. इसके लिए शर्लिन न सिर्फ़ अपने बिजी शेड्यूल से वक़्त निकालती हैं, बल्कि आर्थिक मदद भी करती हैं. यह सब तो ठीक है शर्लिन, पर अगर फ़िल्म इंडस्ट्री में टिके रहना है तो आपको अदाओं के साथ अभिनय में भी परिपक्वता लानी चाहिए.

काजोल का अभियान

बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां हैं, जो अभिनय से लोगों का दिल बहलाने के अलावा समाजसेवा से भी जुड़ी हैं. इस फ़ेहरिस्त में एवरग्रीन ऑल टाइम फेवरेट एक्ट्रेस काजोल का नाम भी जुड़ गया है. काजोल इस वर्ष एबोट इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर थायराइड डिसऑर्डर को लेकर महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान में हिस्सा ले रही हैं. वह कहती हैं कि हमारे देश में ज़्यादातर महिलाएं थायराइड डिसऑर्डर और उसके प्रभाव से बेख़बर रहती हैं. इसलिए हम देश की सभी महिलाओं से थायराइड टेस्ट कराते रहने की अपील करते हैं, क्योंकि परिवार तभी ठीक तरीक़े से चल सकता है, जब घर की महिला स्वस्थ हो. दूसरी बार गर्भवती हुईं काजोल ने कहा कि यह टेस्ट ख़ासकर गर्भवती महिलाओं को ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि थायराइड की कमी होने वाले बच्चे के मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालती है. मां के शरीर में थायराइड की कमी से बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाता है. वह ख़ुद भी वक़्त पर थायराइड टेस्ट कराती हैं और दूसरी होने वाली मांओं को भी यही सलाह देती हैं. काजोल काफ़ी वक़्त से समाजसेवा से जुड़ी रही हैं. वह ब्रिटेन आधारित लुंगा ट्रस्ट के लिए काम करती रही हैं. यह संस्था भारत में विधवाओं के बच्चों को शिक्षित करने का काम करती है. काजोल इसकी गुडविल एंबेसडर हैं, साथ ही पालक भी. इसके अलावा काजोल शिक्षा नामक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ी हैं. एनजीओ शिक्षा भी बच्चों के शिक्षण सुधार पर काम करती है. काजोल को उनके सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन कांफेडरेशन ऑफ एनजीओ एवं खेमका फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2008 में कर्मवीर पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है. यह अवार्ड उन्हें अपने कार्यक्षेत्र से बाहर आकर सामाजिक कार्यों में भाग लेने की वजह से प्रदान किया गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
बिहार झारखंड

दिल्ली, 7 जून –13 जून 2010
www.chauthiduniya.com

संकट में मोदी की कुर्सी

बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की कुर्सी ख़तरे में है. अब तक पिछड़ावाद के हावी होने के कारण धीरे-धीरे अगड़ी जातियों का एक बड़ा तबका पार्टी से दूर होता जा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रदेश भाजपा की कमान डॉ. सी पी ठाकुर के हाथों आई, एक बार फिर से पार्टी की गाड़ी अगड़ों की पटरी पर दौड़ने लगी है.

सरोज सिंह

बिहार भाजपा का चाल, चरित्र व चेहरा एक बार फिर बदल रहा है. अब तक उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में पिछड़ों एवं अगड़ों की रस्साकसी के खेल में अगड़ों के हाथ तंग होते रहे थे, लेकिन प्रदेश भाजपा का नेतृत्व डॉ. सी.पी. ठाकुर के हाथों आते ही पार्टी की गाड़ी अगड़ों की पटरी पर सरपट दौड़ने लगी है. इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में ही सही, पर भाजपा का एक खेमा यह मानता रहा है कि दल के भीतर पिछड़ों को वर्चस्व बढ़ता जा रहा है. महज़ खानापूर्ति के तहत अगड़ों के नेताओं को जगह दी जा रही है. संघ के मापदंड टूट रहे थे. इन बातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा शुरू होते ही इस बात को लेकर प्रयास तेज़ हो गए थे कि इस बार जिसके हाथ में नेतृत्व जाए वह भाजपा को पिछड़ावाद के पेंच और अपने सहयोगी दल के प्रभाव से मुक्त करा सके. यही वजह थी कि डॉ. सी.पी. ठाकुर के अध्यक्ष बनते ही पार्टी का चेहरा बदला-बदला नज़र आने लगा. जहां न केवल मोदी का समीकरण ध्वस्त हुआ बल्कि लगभग किनारा होते अगड़ी जाति के नेताओं को त्राण भी मिला. पदाधिकारियों की टीम के साथ भाजपा की प्रदेश कार्य समिति तक में अगड़ी जाति का प्रतिनिधत्व बढ़ा. इसे मोदी की पार्टी पर कमज़ोर होती पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है. बदलाव की हवा उपमुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई है. बताया जा रहा है कि बिहार में अगर दोबारा राजग की सरकार बनती है तो इस बार मोदी के लिए उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना आसान नहीं होगा. सीपी ठाकुर की नई टीम पर गौर करें तो स्थायी समिति, विशेष आमंत्रित, स्थायी आमंत्रित और पदेन सदस्यों के कुल 284 पद में 184 सदस्य अगड़ी जाति के हैं. इस अगड़ी जातियों में भी 87 पदों पर भूमिहार, 46 पर ब्राह्मण, 42 पर राजपूत और 9 पद कायस्थ के खाते में गए. वहीं वैश्य, यादव, कुर्मी, कोयरी, महादलित, दलित अतिपिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के हिस्से में क्रमश: 38, 20, 08, 08, 11, 05, 07 एवं 04 पद ही आए हैं. इसको आधार मानते हुए पार्टी के भीतर वैश्य, कुर्मी एवं कुशवाहा की हुई उपेक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं.

अगड़ों व पिछड़ों के वर्चस्व की लड़ाई को यही विराम नहीं मिला. भाजपा की मूल कमेटियों में अगड़ों की भागीदारी की विशिष्ठता मंच व मोर्चा में भी बनी रही मंच-मोर्चा के फलसफे पर भी पिछड़ों को उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा. हाल यह है कि मंच मोर्चा के लिए जिन 41 पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हुई, उनमें 28 पदाधिकारी अगड़ी जाति के हैं. आलम यह है कि शिक्षा, बुद्धिजीवि व कला मंच की कमान अगड़ी जाति को थमा दी गई है. इन तीनों मंचों के संयोजक व सह संयोजक अगड़ी जाति के ही बनाए गए हैं. झुग्गी-झोपड़ी, व्यवसाय, आजीवन सहयोग निधि व उद्योग मंच व विधि प्रकोष्ठ में भी सह संयोजक का पद अगड़ी जाति को सौंप दी गई है. कुल मिलाकर मंच मोर्चा का हाल यह है कि भूमिहार से 10 ब्राह्मण से 09 राजपूत से 05, कायस्थ से 04, वैश्य से 06 महादलित से 03, कोयरी कुर्मी मल्लाह व अतिपिछड़ा से एक-एक को पदाधिकारी बनाया गया है.

अगर राजग फिर सत्ता में आया तो उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी किसी अगड़े को बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है. इस खेमे का तर्क है कि अगड़ी जातियों के वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए यह ज़रूरी है कि इस कुर्सी पर कोई सवर्ण चेहरा बैठे. उनका तर्क है कि राज्य में मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों ही पदों पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधत्व नई राजनीतिक परिस्थियों में किसी भी सूरत में ठीक नहीं है.

यह वजह कम नहीं थी भाजपा के भीतर विस्फोट की स्थिति. जहां तक चर्चा है नाराज़ खेमे में आक्रमकता सबसे ज़्यादा राज्य के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के भीतर थी. चर्चा तो इस बात कि है कि विरोध के मुहाने पर पटना-दिल्ली की दौड़ के बाद भाजपा के अंतर्कलह का जो चेहरा सामने आया, वहां पार्टी का संविधान ही बौना पड़ गया. अपने को आचरण वाली पार्टी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास पार्टी के भीतर उपजे संघर्ष को पाटने के लिए तत्काल अपने संविधान का उल्लंघन करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा. यह दीगर है कि इन कोशिशों के बाद भी क्षेत्रीय संतुलन बनाने में भाजपा कामयाब नहीं हो सकी. येन-केन-प्रकारेण ही सही पार्टी के भीतर यह चर्चा चल पड़ी है कि संगठन में किसके हाथ कितना पद गया. इस चर्चा में उपमुख्यमंत्री मोदी के खाते में प्रदेश महामंत्री-मंगल पाण्डेय व राजेंद्र गुप्ता, मंत्री-सूरजनंदन मेहता, उपाध्यक्ष-रमादेवी, चंद्रमुखी देवी, संजय झा, प्रवक्ता-सुरेश रूंगटा, आर.के.सिन्हा के नाम की चर्चा है. प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ठाकुर के खाते में महामंत्री-रजनीश सिंह, मंत्री किरण कुमारी, उपाध्यक्ष-हरिशंकर शर्मा, संजय मयूख, श्यामा सिंह, रवींद्र सिंह को डाला गया है. इसी तरह से अन्य लोगों ने अपने लोगों को संगठन में शामिल कराने में सफलता हासिल की तो उनमें शत्रुघ्न सिन्हा, अश्विनी चौबे, राधामोहन सिंह, हृदयनाथ सिंह व नंद किशोर यादव के नामों की चर्चा है. मगर, इन सबों के बीच कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने प्रभाव सीमा को बढ़ाया भी है. वर्तमान सूची जारी होने के बाद भाजपा के भीतर इस चर्चा को फिर आयाम मिलने लगा है कि कार्यकर्ताओं के उपेक्षित होने का क्रम लगातार जारी है.

चर्चा यह भी है कि भाजपा के संविधान में यह तय है कि प्रदेश भाजपा बिहार के सांगठिनक ढांचा में प्रदेश अध्यक्ष के अलावा दस उपाध्यक्ष व दस मंत्री के साथ एक कोषाध्यक्ष की टीम बनेगी. इसकी संख्या में फेर बदल करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् की सहमति लेना ज़रूरी है, लेकिन विरोध के त्वरित स्वर देखते इस औपचारिकता का ध्यान नहीं रखा गया और संविधान का उल्लंघन कर दस उपाध्यक्ष के बदले 12 और दस मंत्री के बदले 11 मंत्री बनाए गए हैं. इसके बावजूद पार्टी के भीतर क्षेत्रीय व जातीय समीकरण के तुष्टिकरण को लेकर विरोध गहराता ही जा रहा है. भाजपा के भीतरखाने की मानें तो सांगठनिक पद को लेकर मुंगेर, नालंदा, जमुई, नवादा, बांका, शेखपुरा, औरंगाबाद व बाढ़ की उपेक्षा का असर गहराने लगा है. इस क्षेत्र को सांगठनिक महत्वपूर्ण पदों से वंचित रखा गया. यह बात दीगर है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का विद्रोही स्वर केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में कम हो गया है, लेकिन राज्य के सहकारिता मंत्री गिरिराज सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क़रीबी माने जा रहे सूर्यगढ़ा विधायक प्रेमरंजन पटेल सहित पिछड़ों व अति पिछड़ों के कई नेताओं का विरोध अंदर-ही-अंदर सुलग रहा है. सीपी ठाकुर ने जो नई टीम बनाई उससे साफ़ है कि संगठन में अगड़ी जातियों का दबदबा बढ़ा है, लेकिन यह सिलसिला यहीं रुक जाएगा ऐसा भी नहीं है. सूत्रों पर भरोसा करें तो बताया जा रहा है कि अगर राजग फिर सत्ता में आया तो उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी किसी अगड़े को बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है. इस खेमे का तर्क है कि अगड़ी जातियों के वोटरों को अपनी तरफ करने के लिए यह ज़रूरी है कि इस कुर्सी पर कोई सवर्ण चेहरा बैठे. उनका तर्क है कि राज्य में मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोनों ही पदों पर पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधत्व नई राजनीतिक परिस्थियों में किसी भी सूरत में ठीक नहीं है. इसलिए अगर पार्टी से नाराज हो रहे सवर्ण मतदाताओं का साथ चाहिए तो उपमुख्यमंत्री के लिए अगड़ी जाति के किसी नेता को प्रोजेक्ट करना ज्यादा ठीक होगा. इसके अलावा भाजपा पिछले साढ़े चार सालों में पिछलग्गू की बनी अपनी छवि से भी निजात पाना चाहती है. खासकर बटाईदारी क़ानून व एएमयू की शाखा किशनगंज में खोलने को लेकर हुई छीछालेदर की क्षतिपूर्ति को पार्टी ज़रूरी मान रही है. इसलिए पार्टी का एक खेमा सुशील मोदी की जगह अगड़ी जाति के किसी वरिष्ठ नेता को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहता है. जाहिर है आने वाली घड़ी सुशील मोदी के लिए चुनौती भरी है. पार्टी फिर सत्ता में आई और उनकी कुर्सी बरक़रार रहे इसके लिए उन्हें नहले पर दहला मारना ही होगा.

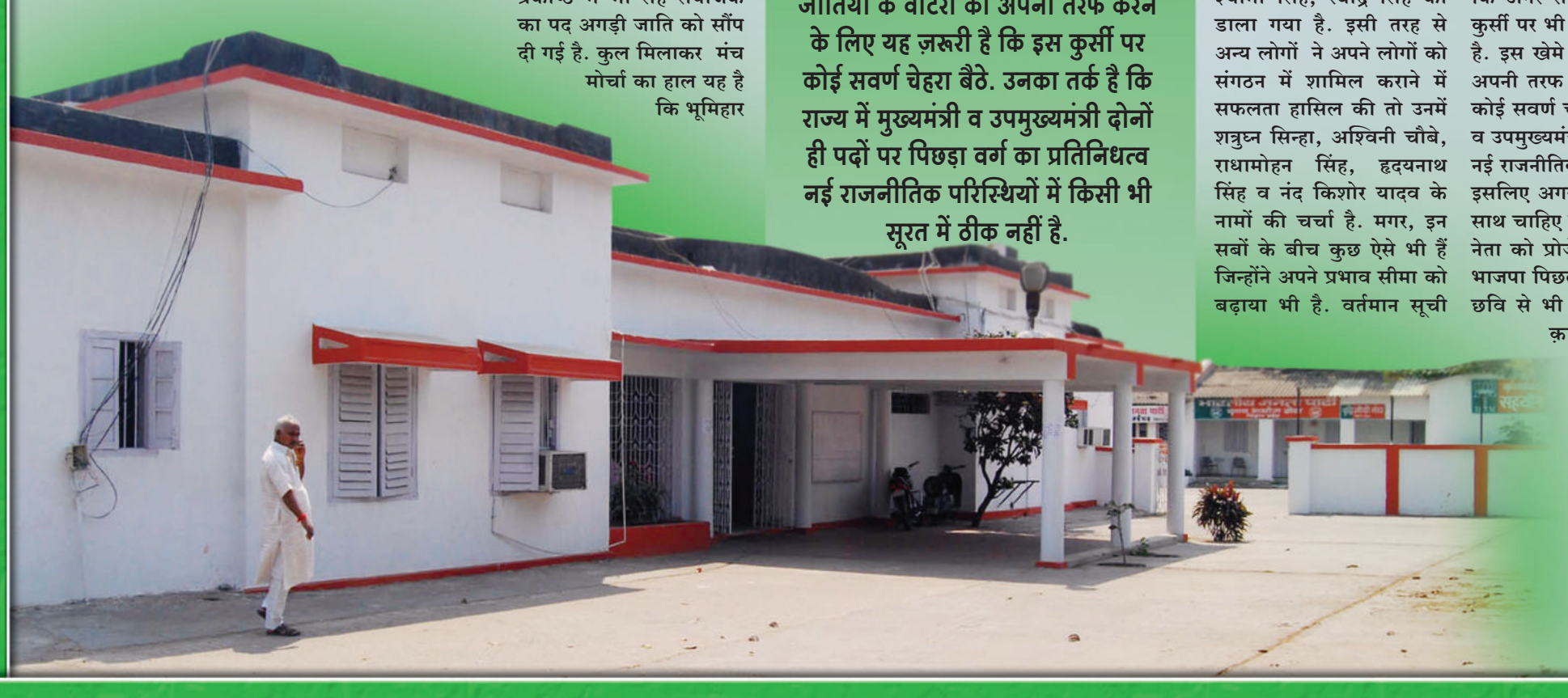

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति के बियावान में प्रवेश कर चुके विजय कृष्ण के भविष्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं. लोगों की मानें तो राजनीति का यह चतुर खिलाड़ी कोई गुल अवश्य खिलाएगा.

ज़िले में तेज़-तर्रार युवा नेता के रूप में उभरे प्रदेश युवा जदयू के महासचिव व प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं.

राजनीतिक नौटंकी से विकास पर ब्रेक

नवल किशोर सिंह

झारखंड में एक माह से जारी एक राजनैतिक नौटंकी का पटाक्षेप होते ही नए नाटक का मंचन शुरू हो जा रहा है. कौन बनेगा मुख्यमंत्री की तर्ज पर राजनेता म्यूजिकल चेयर के खेल में मस्त हैं और विकास का पहिया थमा हुआ है. जनता आश्चर्यचकित होकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का तमाशा देख रही है. सच्चाई यह है कि झारखंड के लोगों का अब संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से ही मोहभंग होने लगा है. हाल में किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि 70 फीसदी लोग मौजूदा हालात में राष्ट्रपति शासन को ही बेहतर विकल्प मान रहे हैं. जोड़-तोड़कर सरकार बनाए जाने के पक्ष में मात्र आठ प्रतिशत लोग हैं, जबकि 22 प्रतिशत लोग पुनर्मतदान के पक्ष में हैं. अब यदि राजनेताओं से पूछा जाए कि बहुमत का फ़ैसला ही लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है तो बहुमत राष्ट्रपति शासन के पक्ष में है, तो उनके पास क्या जवाब होगा.

बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू यह है कि यह नौटंकी वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में ही परवान चढ़ने लगी. इसके कारण वार्षिक बजट के तहत पारित विकास योजनाओं की फाइलें आलमारियों में ही पड़ी रह गईं और उनके मद में आवंटित राशि कोषागारों तक भी नहीं पहुंच सकी. चालू वित्तीय वर्ष को दो माह बीत चुके हैं. विभिन्न विभागों के अधिकारी इस इंतज़ार में हैं कि कोई सरकार बने तो काम शुरू हो. नौकरशाही भी इस माहौल में हतप्रभ है. जनता समझ नहीं पा रही है कि इस राज्य का शासन किस मुहूर्त में हुआ कि शैशवावस्था में ही इसके पांव लड़खड़ाने लगे सिर चकराने लगा. झारखंड के अलावा देश में शायद कोई ऐसा राज्य होगा, जहां मात्र 10 वर्ष के अंदर 7 मुख्यमंत्री और 8 मुख्यसचिव बदल चुके हैं. अब राज्य एक और बदलाव की ओर बढ़ रहा है. राजनैतिक बेशर्मी का आलम है यह कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और तीन पूर्व मंत्री घोटाले के आरोप में क़रीब छह माह से जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं तो एक मुख्यमंत्री अल्पमत में आने के बावजूद कुर्सी से चिपके रहे. यहीं नहीं लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइलों पर दस्तख़त भी करते रहे. राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद भी बैंक डेट में तबादला पदस्थापन करते रहे. विधान सभा चुनाव लड़ने की अब कोई गुंजाइश नहीं है. 29 जून को छह माह पूरे हो रहे हैं. इसके बाद उन्हें भगवान भी मुख्यमंत्री नहीं बनाए रख सकते. इसके बावजूद वह मीडिया के समक्ष धड़ल्ले से कहते फिर रहे हैं कि वह सीएम हैं और बने रहेंगे. अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. झारखंड के नेताओं के बयानों को सुनने के बाद समझ में आता है कि प्रजातंत्र को मूर्खों का शासन क्यों कहा जाता है.

झारखंड राज्य का गठन इसके विकास की गति तेज़ करने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन बीते दस वर्षों में इसकी हालत संयुक्त बिहार के समय से भी बदतर हो गई. राज्य के विकास की जगह राजनेताओं का विकास होता गया. जनप्रतिनिधि बेशर्मी से चमचमाती कारों के काफिले के साथ चलने लगे. कभी फांकाकशी में दिन गुजारने वाले छुटभैये नेता मौक़ा मिलते ही करोड़ों में खेलने लगे. हर वित्तीय वर्ष में केंद्र द्वारा आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा वापस होता रहा. नेता-ठेकेदार-नौकरशाह और दलालों की चौकड़ी आर्थिक लूट में लगी रही. अपराध बेलगाम होते गए. अपहरण और रंगदारी का धंधा इतनी तेज़ी से पुष्पित-पल्लवित हुआ कि दूसरे राज्यों के अपराधी गिरोहों का यह तीर्थस्थल सा बन गया. उग्रवाद भी सुरसा की तरह मुंह फैलाता चला गया. यह सिलसिला बदस्तूर जारी है. इस अवधि में भूख से दर्जन से ज़्यादा मौतें हुई और सरकारी गोदामों में अनाज सड़ता रहा. ग़रीबों का निवाला कालाबाज़ारियों की हवस का शिकार बनता रहा. साक्षरता अभियान एक बिंदु पर आकर ठहर सा गया. ग्रामीण विद्युतीकरण एक सपना बनकर रह गया. पेयजल, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, रोज़गार के क्षेत्र में यह सूबा अपने साथ सृजित राज्यों की तुलना में फिसड्डी रहा. शहरी विकास के मद में केंद्र से 136.92 करोड़ रुपये मिले. इसमें एक पैसा भी ख़र्च नहीं किया जा सका. यह राशि शहरी विकास के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने हेतु स्वीकृत सात योजनाओं के लिए दी गई थी. दरअसल जहां राजनेताओं की पूरी ताक़त सरकार बनाने और गिराने में लगी हो. जहां आर्थिक लूट को जन्मसिद्ध अधिकार समझा जाता हो, जहां नौकरशाही बेलगाम, भ्रष्ट और नाकारा हो वहां विकास की कल्पना तो की जा सकती है लेकिन हक़ीक़त में नहीं बदला जा सकता है. झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि जन्म लेते ही लुटेरों के चक्रव्यूह में फंस गया. अब कोई चमत्कार ही इसे उबार सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

ज़िला बनाने वाले ही विधानसभा जाएंगे

विकास कुमार

रोसड़ा विधानसभा (सु.) क्षेत्र में चुनावी हवा इन दिनों तेज़ हो गई है. नए परिसीमन के अंतर्गत रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र को सामान्य से सुरक्षित कर दिए जाने के बाद से मौजूदा राजद विधायक गजेंद्र प्रसाद सिंह नए क्षेत्र की तलाश में जुट गए हैं. गजेंद्र की जगह लेने के लिए यहां दिग्गज नेताओं ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. अनुमान है कि सभी पक्ष चाहा नेता यहां चुनावी अखाड़े में कूदने की पूरी तैयारी में लगे हैं.

रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 1986 में पहली बार विधायक बनने के बाद गजेंद्र सिंह पांच बार चुनाव जीत चुके हैं. तत्कालीन विधायक भोला मांडर के निधन के बाद वर्ष 1986 में हुए उपचुनाव में गजेंद्र प्रसाद सिंह ने सत्ताधारी कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र नारायण चौधरी को पराजित कर ज़िले और राज्य में तहलका मचा दिया था. गजेंद्र प्रसाद सिंह 1990 में कांग्रेस के रमाकांत झा, 1995 में समता पार्टी के अशोक कुमार मुन्ना एवं वर्ष 2005 के फरवरी एवं नवंबर में हुए चुनाव में दोनों बार जदयू के मौजूदा ज़िलाध्यक्ष व पूर्व विधायक अशोक कुमार मुन्ना को मात देकर विधानसभाई राजनीति में अपना सिक्का जमाया था. लेकिन सिर्फ़ विधानसभा क्षेत्र का स्वरूप बदल जाने के चलते वारिसनगर में ताबड़तोड़ बैठकें कर यहां से लड़ने का संकेत वह दे रहे हैं, क्योंकि नए परिसीमन में वारिसनगर विधानसभा में शिवाजीनगर प्रखंड की छह पंचायत जो पूर्व में रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत थी, को शामिल कर लिया गया है. शिवाजीनगर प्रखंड गजेंद्र प्रसाद सिंह का गृह क्षेत्र है इसलिए वारिसनगर की राह उन्हें ज़्यादा आसान लग रही है.

नए सिरे से गठित रोसड़ा विधानसभा में रोसड़ा प्रखंड के 16 पंचायत ढाहर बसढिया, मोतीपुर, जहांगीरपुर उत्तर, जहांगीरपुर दक्षिण, रहुआ, सोनुपुर उत्तर, हरिपुर, भिरहा पूरब, भिरहा पश्चिम, भरवाही, भिरहा दक्षिण, मो. नगर उर्फ रोसड़ा पूरब, मो. नगर उर्फ रोसड़ा पश्चिम, चकथात पूरब, शिवाजीनगर प्रखंड के 11 पंचायत शंकरपुर, जाखड़ धर्मपुर, पिपराही, दसौत, रहियार उत्तर, रहियार दक्षिण, बल्लीपुर बंधार, करियन दक्षिण, रानीपरती और रजौर रामभद्रपुर समेत सिंघिया प्रखंड के 12 पंचायत फुलहारा, लिलहौल, सिंघिया पूरब, सिंघिया पश्चिम, माहें, वारी, निपुर भरसिया, बंगरहटटा, हरदिया, महरा और बसठटा को शामिल किया गया है. महर्षि उदयनाचार्य एवं कविवर आरसी प्रसाद सिंह की जन्म-कर्म भूमि के लोग आज भी रोसड़ा के समुचित विकास चाहते हैं. विदित हो कि राज्य में पटना के बाद रोसड़ा ही में नगरपालिका का गठन 1 अप्रैल 1869 में किया गया था. आज़ादी मिलने और समस्तीपुर को ज़िला का दर्जा मिलने के बाद भी रोसड़ा का समुचित विकास क्षेत्र के पूर्व जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैए के चलते नहीं हो सका. लालू

सरिता कुमारी

गजेंद्र सिंह

पितम्बर पासवान

प्रसाद एवं राबड़ी देवी के शासनकाल में छोटे-छोटे अनुमंडल को ज़िला का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन सभी अहर्ताओं को पूरा करने के बाद भी रोसड़ा अनुमंडलवासी रोसड़ा को ज़िला बनाने की रट आज भी लगा रहे हैं. नीतीश सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री एवं भाजपा सांसद भोला सिंह ने समस्तीपुर दौरे के दौरान रोसड़ा नगर पंचायत को नगर परिषद् बनाने एवं ज़िला का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया था, जो मौजूदा शासन के बीते साढ़े चार वर्षों में नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा सत्ता एवं विपक्षी पार्टी राजद एवं जदयू को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा ऐसी चर्चा है.

रामदत्त पासवान

रामदेव महतो

विधानसभा क्षेत्र रोसड़ा

पिछले चुनाव में राजद प्रत्याशी गजेंद्र प्रसाद सिंह ने जदयू के मौजूदा ज़िलाध्यक्ष व पूर्व विधायक अशोक कुमार मुन्ना को 3132 मतों से पराजित किया था. इस बार यहां प्राय: सभी दलों में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है. वर्ष 2005 के चुनाव में यह सीट जदयू के खाते में थी, जबकि बगल के विभूतिपुर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे. 2005 के चुनाव में विभूतिपुर में भाजपा का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, वहीं भाजपा प्रत्याशी रहे पूर्व कांग्रेसी विधायक चंद्रबली ठाकुर फिर से अपने पुराने घर कांग्रेस में लौट चुके हैं. ऐसे में भाजपा के पास कोई ऐसा दमदार चेहरा नहीं है, जो सीपीएम के अभेय दुर्ग में मौजूदा विधायक रामदेव वर्मा के विजय अभियान पर विराम लगा सके. ऐसी स्थिति में चर्चा है कि विभूतिपुर सीट भाजपा से जदयू ले लेगी और जदयू द्वारा रोसड़ा विधानसभा भाजपा के लिए छोड़ दिया जाएगा. किसी कारणवश अगर ऐसा नहीं होता है तो रोसड़ा विधानसभा सु. क्षेत्र से जदयू की ओर से प्रखंड बीस सूत्री सदस्य रामदत्त पासवान के चुनाव लड़ने की चर्चा गर्म है. रामदत्त पासवान रोसड़ा की राजनीति में अपनी पहचान बनाने हेतु लंबे समय से प्रयासरत हैं. उनके समर्थक पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि रोसड़ा विधानसभा से जदयू ही चुनाव लड़ेगी और रामदत्त पासवान की उम्मीदवारी सबों पर भारी पड़ेगी. रामदत्त पासवान की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर उनके यहां समर्थकों की भारी भीड़ जुटी रहती है, जो आगामी चुनाव में पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूती देने के एक सूत्री अभियान में लगे हैं. पासवान के समर्थन में कार्यकर्ताओं की वही टीम आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तय कर रही है, जो कभी मौजूदा ज़िलाध्यक्ष व पूर्व विधायक अशोक कुमार के लिए काम करती थी. यदि भाजपा इस सीट से अपना प्रत्याशी देती है तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. संजय पासवान का चुनाव लड़ना भी तय माना जा रहा है. राजग गठबंधन के कार्यकर्त्ताओं की निगाहें इस बात पर जा टिकी है कि रोसड़ा (सु.) सीट जदयू या भाजपा के हिस्से में आती है? कांग्रेस की ओर से यदि किसी महिला को उम्मीदवार बनाने की चर्चा पर यकीन करें तो ई. सरिता कुमारी का नाम सामने आ रहा है. हाल के दिनों में सरिता कुमारी क्षेत्रीय समस्याओं एवं अगलगी की घटनाओं के बाद पीड़ितों की सुधि लेने में दिलचस्पी दिखाई है, जिससे वह चर्चा में बनी हुई है.

कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव रामदेव महतो भी टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं, जो महादलित की श्रेणी में आते हैं. उन्हें और उनके समर्थकों को कांग्रेस का टिकट मिलने का पूर्ण भरोसा है. महतो आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी एवं राहुल-सोनिया के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने हेतु पूरी सजगता से तत्पर हैं. लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दलित सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यविंद पासवान भी पूरे दमखम के साथ चुनावी तैयारी में जुटे हैं. उनके नेतृत्व में रोसड़ा विधानसभा में लोजपा को बूथ लेबल पर मजबूत किया जा रहा हैं. सत्यविंद पासवान वर्तमान में समस्तीपुर ज़िला परिषद क्षेत्र सं.-48 से ज़िला पार्षद भी हैं.

रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट हो जाने के कारण अब यहां से राजद के पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं दरभंगा ग्रामीण के मौजूदा विधायक पीतांबर पासवान की उम्मीदवारी भी लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि वह भी पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से रोसड़ा विधानसभा की राजनीति में पूरी तत्परता से डटे हैं और घूम-घूम कर कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं. नए सिरे से गठित रोसड़ा (सु.) विधानसभा में मतदाताओं की कुल संख्या 244117 है, जिसमें पुरुष 129210 और महिला मतदाताओं की संख्या 114907 है. पिछली बार के चुनाव में मतदाताओं की संख्या 194651 थी. जिसमें इजाफा होकर इस बार मतदाताओं की संख्या 244117 हो गई है. पिछली बार 50.2 प्रतिशत मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था और आगामी विधानसभा चुनाव में न्याय के साथ विकास की धारा में दलित-महादलित ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, तो मतदान के प्रतिशत बढ़ने की भी पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

नेताओं की किस्मत सवर्ण वोटर लिखेंगे

देवघर नगर निगम चुनाव की तारीख़ जैसे-जैसे नजदीक आ रही है वैसे-वैसे चुनावी माहौल परवान चढ़ रहा है. उम्मीदवारों का रोड शो, नुक्कड़ सभा, रैली के अलावा घर-घर जाकर संपर्क अभियान चरम पर है. 17 वर्षों बाद हो रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता में काफी उत्साह है. उम्मीदवारों के समर्थन में जनता भी सहयोग दे रही है. हर जगह सिर्फ़ मेयर एवं डिप्टी मेयर की चर्चा है. वार्ड आयुक्त के लिए भी उत्साह कम नहीं है. कहीं भैया उम्मीदवार हैं तो कहीं भाभी, कहीं चाचा तो कहीं चाची, कहीं पति तो कहीं पत्नी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं. सभी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. उम्मीदवारों के बीच सेटिंग-गेटिंग और दावपेंच का खेल शुरू है. जातीय समीकरण अपने पक्ष में करने के लिए होड़ मची है. नगर निगम चुनाव के सर्वोच्च पद मेयर हेतु सर्वाधिक दिलचस्प एवं कड़ा मुकाबला है. इस चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिज्ञों की परछाई अवश्य ही दिख रही है. लगभग सभी दलों के समर्थक मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं. पर्दे के पीछे, राजनीतिज्ञों की ओर से हर तरह के सहयोग किए जा रहे हैं. देवघर के नगर निगम चुनाव में सवर्णों की भूमिका निर्णायक होने की संभावना है. शहर की आधी से अधिक आबादी सवर्णों की है और वह हर तरह से संपन्न होने के कारण शहर के चुनावी माहौल को मोड़ने की ताक़त रखते हैं. मेयर एवं डिप्टी मेयर का पद अनारक्षित होने के कारण अधिकांश उम्मीदवार सवर्ण वर्ग से हैं, जो सभी हथकंडे अपनाने में सक्षम हैं. पिछड़ों की आबादी 65 हज़ार 869 है, लेकिन उनकी ओर से कोई सशक्त उम्मीदवार नहीं है. पिछड़ों को गोलबंद करना भी मुश्किल है. इस कारण सभी उम्मीदवारों की नज़रें पिछड़ों के वोट पर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़ों का वोट अपने पक्ष में करने में सक्षम होगा वही देवघर के पहले मेयर का ताज पहनेगा तथा उसका ही इतिहास में नाम दर्ज होगा.

दिलीप कुमार सिंह

राज नारायण खवाड़े

> नगर निगम चुनाव के सर्वोच्च पद मेयर हेतु सर्वाधिक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है. क्योंकि शहर के हर क्षेत्र के दिग्गज एक दूसरे को चुनौती देने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं. इस चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है,लेकिन अप्रत्यक्ष रुप से राजनीतिज्ञों की परछाई अवश्य ही दिख रही है.

संजयानंद झा

सुनील कुमार खवाड़े

युद्धिष्ठिर राय

मेयर के प्रबल दावेदारों में प्रसिद्ध समाजसेवी सुनील खवाड़े, शिक्षाविद् युद्धिष्ठिर राय, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े एवं वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सिंह हैं. समाजसेवी सुनील खवाड़े को ज़िला पासी समाज की बैठक में सर्वसम्मति से समर्थन देने की घोषणा की गई है. इसके अलावा कई सामाजिक संस्थाओं ने भी सुनील खवाड़े को समर्थन देने की घोषणा की है. अपार जनसमर्थन से संतुष्ट सुनील खवाड़े का कहना है कि उनके पूर्वजों के अलावा अपने द्वारा किए गए समाज सेवा का पुरस्कार मिलने का समय आ गया है. सुनील के समर्थन में लगभग सभी जाति, वर्ग एवं संप्रदाय के लोगों के साथ ग्रामीण इलाक़ों के लोग भी दिख रहे हैं. उनके रोड शो, रैली व जनसंपर्क अभियान में भारी भीड़ को देखकर मतदाताओं के अनुसार अब तक सुनील खवाड़े काफी आगे चल रहे हैं. शिक्षाविद् युद्धिष्ठिर राय को भी अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है. राय की भी शहर में काफी लोकप्रियता है. रेड रोज स्कूल के सचिव होने के नाते खेलकूद प्रेमियों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान हैं. सबसे चर्चित दबंग उम्मीदवारों में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजनारायण खवाड़े उर्फ बबलू खवाड़े पर सबकी नजर है, जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 40 हज़ार वोट लाकर सशक्त दावेदारी दर्ज कर चुके हैं. बबलू खवाड़े को भी मतदाताओं की ओर से अच्छा समर्थन मिल रहा है. वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप सिंह की भी मतदाताओं में पहचान है. चुनाव प्रचार अभियान पूरे चरम पर है, देखना है कि देवघर की जनता पहले मेयर का ताज किसके सिर रखती है. डिप्टी मेयर पद के लिए प्रबल दावेदारों में संजयानंद झा, रवनी कांत ठाकुर, एस एन सिंह, सुरेश साह, बबलूधारी प्रमुख हैं. रवनी कांत ठाकुर युवा, शिक्षित एवं कर्मठ हैं. शिक्षाजगत से जुड़े होने के कारण शहर में उनकी अच्छी छवि है. उन्हें पूर्व कांग्रेस ज़िलाध्यक्ष राजेंद्र दास का आशीर्वाद प्राप्त है.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

शह-मात का खेल शुरू

नए परिसीमन से अस्तित्व में आए वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में संभावित प्रत्याशियों की आवाजाही और कार्यक्रमों की धूम मचनी शुरू हो गई है. गया मुफ्फसिल विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर वजीरगंज, मानपुर, और गया नगर निगम के छह वार्डो को मिलाकर बने इस विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न दलों के संभावित प्रत्याशियों विशेषकर सवर्ण जाति के लोग इसे अपना विशेष क्षेत्र मानकर विधानसभा की देहरी तक पहुंचने के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं. आज़ादी के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से उपेक्षित रहे वजीरगंज की विकास की चिंता आज सभी दलों के संभावित प्रत्याशियों को सताने लगी है. कभी दो-दो विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वजीरगंज आज राजनीतिक रूप से सर्वाधिक गर्म नज़र आ रहा है. गर्मी की इस मौसम में यहां के बढ़ते राजनीतिक तापमान में हर संभावित प्रत्याशी मतदाताओं की नब्ज टटोलने में लगे हैं. मुफ्फसिल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक अवधेश कुमार सिंह अपनी पार्टी से दावेदारी जताकर नए परिसीमन में आए क्षेत्र के मतदाताओं के बीच जाकर अपनी उपलिब्धयों को बता रहे हैं. कांग्रेस में कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो यहां से उनका कांग्रेस प्रत्याशी होना तय है. राजपूत बहुल इस विधानसभा क्षेत्र पर अपनी मज़बूत पकड़ का दावा करने वाले अवधेश सिंह को चुनौती देना किसी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन दूसरे दलों से ताल ठोक रहे संभावित प्रत्याशियों को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा. अपने-अपने तर्क, चुनावी गणित, वजीरगंज की उपेक्षा ओर विकास के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों में सबसे अधिक दावेदारी जदयू से ही है. पूर्व विधायक विनोद कुमार यादवेंदु जदयू से यहां की दावेदारी करे रहे हैं. वे दो बार मुफसिल विधानसभा क्षेत्र से राजद के टिकट पर विधायक रह चुके हैं. फिलहाल जदयू में रहकर पार्टी के वोट बैंक और अपने जातीय मत के आधार पर दावेदारी जता रहे हैं. हाल के वर्षों में ज़िले और प्रदेश में अपने तेज़-तर्रार युवा नेता के रूप में उभरे प्रदेश युवा जदयू के महासचिव व प्रवक्ता धीरेंद्र कुमार मुन्ना की भी जबर्दस्त दावेदारी है. युवा होने और उपेक्षित वजीरगंज को विकास का नया स्वरूप देने की बात करने वाले धीरेंद्र मुन्ना को उम्मीद है कि पार्टी उनके जैसे समर्पित युवा कार्यकर्ता को तरजीह देकर वजीरगंज से प्रत्याशी बनाएगी. उनका कहना है कि हम विकास पुरुष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास की सोच को वजीरगंज में और आगे ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे. यहां का सभी राजनीति समीकरण और दलीय मत मेरे अनुकूल है. आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी के बाद ज़िले के विकास में अहम भुमिका निभाने वाले बड़ा बच्चा बाबू- छोटा बच्चा बाबू परिवार से आने वाले और वर्षो तक वजीरगंज समेत पूरे ज़िले में किसानों और महादलितों की समस्याओं के लिए लड़ने वाले समाजसेवी रविंद्र प्रताप भी जदयू से अपनी मज़बूत दावेदारी कर रहे हैं. विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के ख़ास माने जाने वाले रविंद्र प्रताप को मलाल है कि आज़ादी के बाद वजीरगंज में कोई विकास नहीं हुआ. इस बार वह वजीरगंज के विकास के लिए समर्पित संकल्प के साथ वजीरगंज के ही किसी व्यक्ति को यहां का प्रतिनिधि बनाने के प्रयास में हैं. यदि जदयू ने उन्हें मौक़ा दिया तो वह जीतकर वजीरगंज पुलिस अनुमंडल को प्रशासनिक अनुमंडल का दर्जा दिलाने के साथ ही अनुमंडल स्तर पर सभी सरकारी विभागीय कार्यालय को यहां लाएंगे और विकास के नए आयाम खोलेंगे. मगध विश्वविद्यालय सिंडिकेट और बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य डॉ. अरविंद कुमार सिंह जदयू से अपनी संभवित उम्मीदवारी को लेकर क्षेत्र में सक्रिय हैं. समता पार्टी के स्थापना काल से लेकर अबतक नीतीश कुमार के साथ रहने वाले अरविंद सिंह को उम्मीद है कि पार्टी उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाएगी. समता पार्टी से लेकर जदयू तक संगठन में विभिन्न पदों पर रहने वाले कमलेश वर्मा भी यहां से संभावित प्रत्याशी हैं. उन्हें दल का समर्पित सिपाही रहने और वजीरगंज में अपने काम को लेकर यहां से टिकट मिलने का भरोसा है. गया कॉलेज के व्याख्याता डॉ. कृष्णनंदन यादव, विनोद कुमार, अक्षय सिंह, मुनेश्वर सिंह, अशोक कुमार अंज समेत दर्जनों लोग यहां से जदयू के संभावित दावेदारों में हैं. वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य क्षितिज मोहन सिंह जदयू-भाजपा गठबंधन के अंतर्गत वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र भाजपा कोटे में आने की उम्मीद पर यहां से भाजपा के एक प्रमुख दावेदार के रूप में हैं. इस विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय होने और विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा के विभिन्न पदों पर रहते हुए मानपुर-वजीरगंज में लोगों की सेवा करने वाले क्षितिज मोहन अपनी दावेदारी भाजपा से जता रहे हैं. उनकी दावेदारी को चुनौती देने वाला भाजपा से स्थानीय स्तर पर कोई नहीं है. जाति और पार्टी स्तर पर चुनावी समीकरण को वह अपने अनुकूल बताते हैं. वहीं दूसरी ओर राजद लोजपा गठबंधन में इस सीट को लोजपा के अंतर्गत आने का दावा करते हुए लोजपा नेता और अधिवक्ता ठाकुर मुरारी सिंह अपनी दावेदारी कर रहे हैं. उनका कहना है कि वजीरगंज पर अपनी नज़र रखते हुए ही लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान ने इस विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सेल का स्टील प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास किया था. उनका दावा है कि उन्हें मौक़ा मिला तो वजीरगंज को विकास की राह पर ले जाएंगे. इन सबसे इतर राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले युवा बिल्डर और शिक्षण संस्थान संचालक के रूप में चर्चित अनिल सिंह वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन किस दल से चुनाव लड़ेंगे इसका ख़ुलासा वह अभी करना उचित नहीं समझते हैं. अनिल सिंह वजीरगंज के विकास को लेकर चिंतित हैं और यहां के लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क सुविधा समेत अन्य समस्याओं के निदान के लिए प्रयासरत हैं. किसी दल ने टिकट दिया तो ठीक अन्यथा वजीरगंज के लोगों के अनुरोध पर स्वतंत्र रूप से भी मज़बूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे. नए परिसिमन में वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद तमाम संभावित प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने का दावा करने वाले चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू ने यहां के चुनावी गणित को अपने पक्ष में कर लिया है. यह बात यहां के अधिकांश युवा और उनके समर्थक कहते हैं. 9 मई को पटना में आयोजित किसान महापंचायत में 152 गाड़ियों के साथ हज़ारों लोगों को लेकर शामिल होने वाले चितरंजन कुमार वजीरगंज के विकास के लिए कुछ भी कर गुज़रने की तमन्ना रखते हैं. उनका कहना है कि वजीरगंज की जनता ने मौक़ा दिया तो यह क्षेत्र विकास के मामले में बिहार का मॉडल बनेगा. वजीरगंज के लिए तन-मन-धन समर्पित करने वाले चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू यहां विकास की गंगा बहाने का दावा करते हैं. 278 बूथ के 2,29,584 मतदाता वाले राजपूत बहुल वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र नए परिसीमन की वजह से सभी प्रत्याशियों के लिए एक तरह से नया है, लेकिन सवर्ण जाति के संभावित प्रत्याशियों की बहुलता को देखते हुए हर कोई पहले अपने दल से टिकट सुनिश्चित कराने की फिराक में हैं. कुल मिलाकर इतना तय है कि विधानसभा चुनाव में पूरे गया ज़िले में वजीरगंज का राजनीतिक तापमान सबसे अधिक गर्म रहेगा. अपने ही जाति के सर्वाधिक संभावित प्रत्याशी से कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक अवधेश कुमार सिंह किस तरह निपटेंगे, इस पर लोगों की नज़र है. इतना तो तय है कि अवधेश सिंह को चुनौती देना कोई आसान काम नहीं है. इस बार उनकी राह भी आसान नहीं है. उन्हें शिकस्त देने के लिए वजीरगंज में अभी से ही राजनीति की बिसात पर शह-मात देने का खेल शुरू हो चुका है.

अजीत सिंह

अवधेश सिंह

चितरंजन कुमार

धीरेंद्र मुन्ना

रविंद्र प्रताप

ठाकुर मुरारी सिंह

विधानसभा क्षेत्र वजीरगंज

विनोद यादवेंदु

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

विजय कृष्ण राजनीतिक खिचड़ी पकाने में जुटे

दिव्या कुमारी

जयप्रकाश आंदोलन की उपज और महान दिवंगत समाजवादी नेता स्व. चंद्रशेखर के शिष्यों में शुमार विजय कृष्ण की गिनती बिहार के कद्दावर राजनेता में होती थी. पटना से जब वह बाढ़ के लिए निकलते थे, तो उनके समर्थक बिना बुलाए गाड़ियों के काफिले के साथ उनके पीछे-पीछे चलते थे, लेकिन आज उनके साथ न वो काफिला है और न वो गाड़ी. स्थिति बिल्कुल उलट है. राजनीति के बियावान में प्रवेश कर चुके विजय कृष्ण के भविष्य पर सबकी निगाहें टिकी हैं. लोगों की मानें तो राजनीति का यह चतुर खिलाड़ी कोई गुल अवश्य खिलाएगा, क्योंकि धुन के पक्के, स्वभाव से स्वाभिमानी, मन से संतोषी विजय कृष्ण उन लोगों में से नहीं जो आसानी से हार मान लें और चुपचाप राजनीतिक आत्महत्या कर लें. जेपी आंदोलन की उपज और बिहारी राजनीति में तुर्क का दमखम रखने वाले पूर्व सांसद विजय कृष्ण की ख़ामोशी सूबे की सियासत में नए हलचल के संकेत दे रही है. उनकी ख़ामोशी आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई नया समीकरण तैयार कर सकता है. अपने क़रीबी सत्येंद्र सिंह की हत्या के आरोप में जेल से बाहर निकले पूर्व सांसद विजय कृष्ण इन दिनों अज्ञातवास जीवन जी रहे हैं. जेल से निकलने के बाद न तो वह किसी मंच पर दिखे और न ही अब तक उनका कोई बयान सामने आ सका है, लेकिन सूत्रों की मानें तो राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले विजय कृष्ण विधानसभा चुनाव की तैयारी में अपनी खिचड़ी तैयार करने में जुट गए हैं. उनके गृह क्षेत्र बाढ़ से उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं. पुराने घर यानी राजद में वापसी की संभावना भी है. वर्तमान में नीतीश सरकार से जिस तरह राजपूतों की नाराजगी बढ़ रही है, ऐसे में हो सकता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद विजय कृष्ण की घर वापसी को हरी झंडी देकर यह संदेश देने का प्रयास करेंगे कि देखो किस तरह सरकार ने विजय कृष्ण का शोषण किया. राजद की राजनीतिक गलियारे में चहलकदमी करने वाले लोग बताते हैं कि लालू प्रसाद को विजय कृष्ण से सहानुभूति है. संभावना बन रही है कि विजय कृष्ण लालटेन जलाने के लिए बाढ़ में क़दमताल कर सकते हैं. क्योंकि नीतीश कुमार के क़रीबी बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को पराजित करने के लिए राजद को सशक्त उम्मीदवार चाहिए. ज़ाहिर है विजय कृष्ण के पास बाढ़ के बहुसंख्यक मतदाताओं का समर्थन भी है और सहानुभूति भी. उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने अत्यंत विनम्रतापूर्वक राजनीतिक टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. हालांकि विजय कृष्ण यह कहना नहीं भूले कि इंतजार कीजिए परिणाम ज़रूर सामने आएगा. अभी वह ख़ामोश रहकर ही अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं. कहा तो यहां तक जा रहा है बटाईदारी बिल से उपजे विवाद के बाद जदयू में हुए दो फाड़ के बाद विजय कृष्ण का किसी भी पक्ष में खुलकर सामने नहीं आना इस बात की पुष्टि करता है कि पूर्व सांसद की तैयारी किसी नए घर की तलाश में है. पिछले लोकसभा चुनाव के दरम्यान विजय कृष्ण ने राजद में हो रही उपेक्षा को कारण बताते हुए कभी अपने प्रतिद्वंद्वी रहे नीतीश कुमार के घर आसरा ले लिया. लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तुरुप के पत्ते की तरह इस्तेमाल किया. राजपूत बहुल इलाक़ों में विजय कृष्ण ने ज़ोरदार चुनाव अभियान चलाया. अगवानपुर गांव में ललन सिंह के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे विजय कृष्ण ने घोषणा की थी कि इस इलाक़े में लालू प्रसाद को कार्यकर्ताओं के दर्शन नहीं होंगे. इधर जदयू में प्रवेश करते हुए विजय कृष्ण पर बड़ी ज़िम्मेदारी डालने की तैयारी चल रही थी. बाढ़ के सकसोहरा में ख़ुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि लोग यही चाहते थे कि विजय कृष्ण और नीतीश आपस में मिल जाएं. लोगों की इच्छा अब पूरी हो गई है तथा विजय कृष्ण को शीघ्र ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी. राजनीतिक गलियारे में इस बड़ी जिम्मेदारी को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के मनोनयन की ओर इशारा माना जा रहा था. कहा तो यहां तक गया कि सत्येंद्र की हत्या में अगर विजय कृष्ण का नाम नहीं आता तो उन्हें जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन नई पार्टी की नई छौंक विजय कृष्ण को रास नहीं आई. अपने रिश्तेदार सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में वह जेल चले गए. शासन सत्ता से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बचाने की कोशिश होगी, लेकिन उल्टे शासन ने विजय कृष्ण को जेल भेजने के लिए पूरी ताकत लगा दी. विजय के करीबियों की मानें तो उन्हें साजिशन इस हत्याकांड से जोड़ा गया. करीबी सूत्रों की मानें तो विजय कृष्ण राजधानी में रहकर ही विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं. बटाईदारी बिल को लेकर सूबे का सवर्ण तबका काफी हद तक लामबंद हो चुका है. बांका के सांसद दिग्विजय सिंह और महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार के विरुद्ध अभियान चलाया है. उस पर भी विजय कृष्ण की नजर हैं. उन्हें उम्मीद है कि राजपूत नेता की कमी को पूरा करने के लिए नीतीश इनको अभयदान देंगे. दूसरी तरफ सियासत की गलियों से यह खबर भी छनकर आ रही है कि विजय कृष्ण आने वाले चुनाव में जदयू और बागी खेमे के समानांतर ताकत तैयार कर कड़ी चुनौती दे सकते हैं. वह फिलहाल खामोश हैं, लेकिन सियासत के इस महारथी की खामोशी जदयू के साथ ही विपक्षी राजद को भी बेचैनी में डाल रखी है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा. संभावना है कि सूबे में आचार संहिता लगने की तारीखों के साथ ही विजय कृष्ण अपनी रणनीतियों का ख़ुलासा करेंगे. बाढ़ के लोगों को इंतजार है उनके उद्घोष का क्योंकि सामने महाभारत की बिसात बिछी हुई है और लड़ाके भी दो-दो हाथ करने को बेताब हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि सेनापति युद्ध का बिगुल फूंके.

feedback@chauthiduniya.com

भाजपाइयों ने खींचा चुनावी खाका

जैसे-जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है प्राय: सभी पार्टियों ने चुनावी समर में उतरने के लिए अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है. भाजपा ने भी चुनावी रणनीति बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में एकजुटता लाने एवं उनमें जोश भरने का काम शुरू कर दिया है. पूर्णियां प्रमंडल समेत कोसी के सात ज़िलों में के पार्टी से जुड़े विभिन्न पदों ज़िलाध्यक्षों, विधायकों, विधान पार्षदों एवं सांसदों की बैठक कर चुनावी लड़ाई का शंखनाद किया. बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव एवं उससे जुड़े रणनीति का मुद्दा छाया रहा. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे को सहयोग करने एवं एकजुटता का पाठ पढ़या गया. जदयू के साथ संभावित सीटों के तालमेल व उसकी अदला-बदली पर भी गहन विचार किया गया. इस अवसर पर आगामी 13 जून को पटना के गांधी मैदान में होने वाली चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक से अधिक लोगों को पटना लाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया गया. बैठक में यह राय बनी की कोसी क्षेत्र से पिछले चुनाव से भी बेहतर परिणाम लाया जाए. वरिष्ठ नेताओं ने इसके लिए आम लोगों के साथ सीधा संवाद करने व उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए हर संभव प्रयास करने की ज़रूरत पर बल दिया. नेताओं ने साफ़ कर दिया कि अगर बेहतर परिणाम देना है तो आपसी मतभेद को भुलाकर पार्टी के सभी लोगों को एकजुट होकर चुनावी लड़ाई में कूदना होगा. यह भी तय हुआ कि बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को पूरी तरह सक्रिय रहना होगा. कुल मिलाकर भाजपा की इस महापंचायत में यह संदेश देने की कोशिश की गई की हर हाल में 2005 का इतिहास दोहराना है. पटना में होने वाली रैली की सफलता के लिए भी भाजपाइयों को कमर कसने को कहा गया.

नीरज कुमार सिंह
feedback@chauthiduniya.com

केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल-अनंत भारती

अनंत भारती

पूर्णियां के भाजपा ज़िला मंत्री व युवा भापजा नेता अनंत भारती ने दावा किया है कि आगामी 13 जून को पटना के गांधी मैदान में होने वाली भाजपा की रैली में पूर्णियां एवं कोसी प्रमंडल के युवा भाजपा कार्यकर्ता काफी संख्या में जुटेंगे. उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण आज मंहगाई चरम पर है. नक्सली हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है. केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नक्सलियों के ख़िलाफ़ उठाए जा रहे क़दम में उनके ही पार्टी के सांसद अड़ंगा लगा रहे हैं और पूरे राष्ट्र के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं. दोषी अफजल गुरु को फांसी देने में देरी की जा रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति एवं महंगाई रोक पाने में विफलता एवं अन्य कई मुद्दों पर विरोध जताने पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल समेत सात जिलों से भारी संख्या में युवा भाजपा कार्यकर्ता पटना के गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 7 जून–13 जून 2010

फिल्मों से कावेरी झा लाइम लाइट में आ गईं और इसी वजह से तेलगू फिल्मों में इनकी मादक अदाओं के चर्चे ज़ोरों पर हैं.

भारत की ज़मीन नेपाल के क़ब्ज़े में

आख़िर कब तक भारत अपनी ज़मीन पर पड़ोसी देशों का अतिक्रमण का शिकार बनता रहेगा? कब तक प्रत्येक भारतीय यह समाचार सुनता रहेगा, कि पड़ोसी मुल्क ने उसकी ज़मीन क़ब्ज़ा कर लिया है. कब तक यह सुनते रहेंगे कि सरकार उच्चाधिकारी स्तर की वार्ता कर रही है. यह सुनते-सुनते तो पचास वर्ष का समय गुजर गया. जी हां, यहां बात हो रही है भारत-नेपाल से जुड़े सुस्ता विवाद की. 1831 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के पदाधिकारी कर्नल एल एच जैक्शन ने नेपाल को भारत की शक्ति का अहसास कराते हुए दोनों देशों का सीमांकन किया था. ठीक उसी समय गंडक नदी की धारा का भी सीमांकन किया गया था. तत्कालीन दस्तावेज पर ब्रिटीश सरकार और नेपाल के राजा जंग बहादुर ने हस्ताक्षर किया, लेकिन कालान्तर में गंडक नदी की शैतानी धारा ने भारत के हिस्से की तरफ कटाव करना शुरू कर दिया. जिस कारण नरसहिया जंगल, सुस्ता, ठारी गांव तथा खेती की ज़मीन नदी के उस पार चली गई. कटाव होने और भारतीय ज़मीन नेपाल की तरफ खिसकने को लेकर 1846 में अंग्रेजों ने सर्वेक्षण करके भिखनाठोरी आदि जगहों पर पीलर आदि लगवाएं, लेकिन सुस्ता का समाधान नहीं हो सका. दोबारा विवाद को समाप्त करने के लिए 1883-85 में एससीबी टेनर्स ने सर्वेक्षण किया. तीसरी बार 1894-95 में फिर सर्वे कैड स्ट्रल द्वारा सर्वे किया गया. मगर, हर बार नेपाल सर्वे की स्थिति को मानने से इंकार करता रहा. पुन: चौथी बार 1902 में ईजे सियेल्स सर्वे हुआ, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नेपाल ने इसे मानने से इंकार कर दिया. एक बार फिर 1929 में दोनों देशों ने संयुक्त सीमा आयोग का गठन किया. 1930 में आयोग ने भारत की तरफ नदी की सीमा खिसकने की बात स्वीकार की. गंगबरार ज़मीन को भारत का हिस्सा माना, लेकिन नेपाल सरकार ने इसे भी ख़ारिज़ कर दिया. 1957 में भारत सरकार ने टोपोग्राफिकल सर्वे के द्वारा भारतीय सीमा का विवाद नेपाल के साथ समाप्त करनी चाही पर नेपाल ने हर बार की तरह इस बार भी ठेंगा दिखाते हुए शाही सैनिक और सीमा सुरक्षा गार्ड के जवानों को अतिक्रमण करने के लिए खुली छूट दे दी. अतिक्रमण करके पुलिस चौकी कायम कर लिया. 1961 में पुलिस चौकी बनने की सूचना पर तत्कालीन सांसद पं. कमल नाथ तिवारी के अगुवाई में हज़ारों राष्ट्रवादियों ने सुस्ता पहुंचकर विरोध जताया. फिर भी अतिक्रमण जारी रहा है. उसके बाद भारत में रह रहे लोगों ने 1964 में सुस्ता पहुंचकर इसका कड़ा विरोध किया. विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नेपाली पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें दो लोगों की जान चली गई. भारत ने वाल्मीकिनगर बराज के निर्माण का हवाला देते हुए उच्चस्तरीय वार्ता की शुरुआत की, लेकिन नेपाल ने समस्या को ठंढा बस्ते में डाल दिया. भारत की कमजोरी से नेपाल का मनोबल बढ़ता गया. नेपाल का अतिक्रमण और भारतीय लागों की उदासीनता को देखकर चंपारण के तत्कालीन ज़िला अधिकारी ने 28 जनवरी 1969 को बिहार सरकार के पास सीमा विवाद समाप्त करने के लिए एक पत्र लिखा. इस पर बिहार सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा. जिस पर केंद्र सरकार ने पत्र के आलोक में विदेश सचिव एन मेनन और नेपाल के अपर सचिव केपी कोईराला के संग त्रिदिवसीय बैठक दिल्ली में कराई, लेकिन नेपाल के सचिव ने 1815 के सुगौली संधि और 1817 में निर्धारित नदी के मध्य सीमा का हवाला देते हुए भारत द्वारा 1931 में दिए गए प्रस्ताव को ख़ारिज़ कर दिया. यही वह समय था भारत को कड़ा रुख अपनाने का, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका खामियाजा भारत आज भी भोग रहा है. इतना ही नहीं 1922 में 21 एकड़ ज़मीन रक्सौल में रेल गाड़ी चलाने के लिए नेपाल को दी गई, लेकिन यहां पर भी यही हाल रहा. पहले नेपालियों ने झोपड़ी बनाई बाद में वहां वे पक्का मकान बना लिए. भीखनाठोरी में भी यही हाल रहा. सुस्ता में पहले पुलिस चौकी बाद में नेपाली लोगों ने यहां रहना शुरू कर दिया. फिर देखते ही देखते उन्होंने यहां बाज़ार खड़ा कर लिया. उसके बाद नेपालियों ने यहां कार्यालय भी बना लिया. इस प्रकार नेपाल अपना दावा मजबूत करता गया और भारत मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो किलोमीटर तक नो मैन्स लैन्ड रहता है. 1983 में भारतीय भगोड़ा मुन्ना खां अपने साथियों के साथ भारतीय भूमि पर जब सुस्ता की ओर से अतिक्रमण कर रहा था. तब इसकी सूचना मिलते ही वाल्मीकिनगर के थाना प्रभारी ईस्माईल खां जब कार्रवाई करने पहुंचे तो मुन्ना खां ने थाना प्रभारी समेत दो जवानों को गोली मारकर हत्या कर दी. अतिक्रमण इतना बढ़ता चला गया कि सुस्ता स्थित राजस्व ग्राम ठाढी थाना नं.3 क्षेत्रफल 7332 एकड़, रमपुरवा थाना नं.6 क्षेत्रफल 934 एकड़, परसौनी थाना नं. 11 क्षेत्रफल 2351, बलगंगवा थाना नं. 12 क्षेत्रफल 3481 एकड़ ज़मीन अतिक्रमण का शिकार होता चला गया. भारतीय किसानों को वहां खदेड़ा जा रहा था. नरकटियागंज की ओर भीखनाठोरी में ओरिया नदी के कटाव में भारतीय भू भाग नेपाल की तरफ चला गया है. जब-जब भारतीय किसानों ने अपनी ज़मीन को जोतना और आबाद करना चाहा तो नेपाली पुलिस ने उन्हें मार भगाया. अब तो नेपाली पुलिस भारतीय भगोड़ों को सामने लाकर एसएसबी के जवानों पर यह आरोप लगाती रही है कि भारतीय किसानों को एसएसबी के जवान उकसाते हैं. 21 सितंबर 2007 को वाल्मीकिनगर बराज पर भारतीय भगोड़ों के साथ नेपाली लोगों ने प्रदर्शन करके भारत विरोधी नारे लगाए. उसके बाद 10 अक्टूबर 2007 को नेपाल के नवलपरासी स्थित त्रिवेणी सेना कैंप में भारत नेपाल के पदाधिकारी एक संग बैठकर एक संयुक्त कमेटी का निर्माण किया. कमेटी के सदस्य अस्थाई सीमा का निर्धारण करेंग. इस कमेटी में दोनों देशों के पांच-पांच सदस्य होंगे, जिसमें भारत की तरफ से रमपुरवा के उप मुखिया राकेश कुमार, जलील अंसारी, रहीम मियां, सकलदेव साह, शिवपूजन तिवारी को शामिल किया गया, जबकि नेपाल की ओर से मणि कुमार श्रेष्ठ, टेकराज उपाध्याय, दिलबर थापा, बुद्धिसागर उपाध्याय, अकल थापा शामिल किए गए. दोनों देशों के पदाधिकारियों में भारत की ओर से बगहा अनुमण्डल पदाधिकारी अभय कुमार सिंह, एसएसबी के सेनानायक एचआर बारोट, प्रभारी आरक्षी अधीक्षक सुभाष शर्मा, बगहा दो के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप कुमार गुप्ता, वाल्मीकिनगर थाना प्रभारी शमशेर सिंह, वहीं नेपाल की तरफ से नवलपरासी के ज़िला अधिकारी एसपी शरदचन्द्र आदि मौजूद रहे. ये सभी लोगों ने विवादित क्षेत्रों का दौरा किया. उसके बाद तय किया गया कि दोनों देशों के ज़िला पदाधिकारी बैठक करके सरकारों को यथा स्थिति से अवगत कराएंगे. अनुमण्डल पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह से सुस्ता विवाद के संबंध में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब कुछ पूर्ववत स्थिति में है.

राजा जंग बहादुर

अरविन्द नाथ तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

भोजपुरी ही है मंजिल

जहां एक तरफ भोजपुरी सिने नगरी में गैर भोजपुरी क्षेत्रों के बाहर की तारिकाओं के जलवे बरक़रार हैं, तो वहीं बिहारी बाला कावेरी झा हिंदी और तेलगू फ़िल्मों में अपनी किस्मत आजमा रही हैं. हिंदी फ़िल्मों की बात करें तो, अभी तक उनकी कुछ ही फ़िल्में रिलीज हुई हैं. जिनमें शाहनी आहूजा और ईशा देओल के साथ हाईजैक और हाल ही में रिलीज प्रियर्दशन और दर्शील सफारी की बम बम बोले का नाम लिया जा सकता है. ग़ौरतलब है कि इन दोनों फ़िल्मों से कावेरी को कोई खास फायदा नहीं मिला है. हां, इतना ज़रूर है कि इन फ़िल्मों से वो लाइम लाइट में आ गईं और इसी वजह से तेलगू फ़िल्मों में इनकी मादक अदाओं के चर्चे ज़ोरों पर हैं. इनकी ज़्यादातर तेलगू फ़िल्में म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर रही हैं. इसके अलावा स्टेज कार्यक्रमों में भी इनकी अच्छी-ख़ासी डिमांड है. बहुत कम लोगों को पता होगा कि कावेरी कई सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं, इसके अलावा उन्होंने बाकायदा एयर होस्टेस का प्रशिक्षण भी लिया है. कावेरी से जब पूछा गया है कि वह बिहारी होने के बावजूद भोजपुरी फिल्मों में काम क्यों नही करतीख तो उनका जवाब था कि जब मैने ग्लैम वर्ल्ड में कदम रखा था तब से ही सोच रखा था कि एक बार जमने के बाद भोजपुरी सिनेमा में ही काम करूंगी. अब समय आ गया है. इतने कम समय में कावेरी ने जितनी कामयाबी हासिल की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वह दिन दूर नहीं, जब भोजपुरी की दूसरी अभिनेत्रियां इनसे कोसों दूर होंगी.

feedback@chauthiduniya.com

ISO 9001:2000 Certified
World Standard Quality Now Available in India
Italian International Paints

Long Life for Paints & Walls
ITALIAN
Wall Putty

* Made from DPMC
* Marvelous White
* Super Smoothness
* 100% Damp proof
* 100% Crack proof
* World Class Packing

World Standard
ITALIAN
Decorative Premium
WHITE CEMENT

welcome

ITALIAN International Paints.
Plot No.8, 2nd Floor, Nitin Palace,
CHANDKHEDA, Near-O.N.G.C.IRS,
Ahmedabad,Pin-382424(Gujarat)

Slight Costly but Superior

Fax No.079-23972402 / 033-25224090

चौथी दुनिया

दिल्ली, 7 जून–13 जून 2010

www.chauthiduniya.com

प्रजातंत्र जीतेगा या कमलनाथ

यह अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति केंद्रीय मंत्री कमलनाथ का लगाव है या कुछ और, पर वह व्यास नदी की धारा की तरह उत्तर–दक्षिण गलियारे को भी छिंदवाड़ा की ओर मोड़ना चाहते हैं. उनकी जिद के कारण राष्ट्रीय महत्व के इस गलियारे का भविष्य ख़तरे में पड़ गया है.

आरती पटेल

उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाले उत्तर–दक्षिण गलियारे का भविष्य केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की जिद के कारण ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है. व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यास नदी की धारा को मोड़ने वाले कमलनाथ अब विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत उत्तर–दक्षिण गलियारे को अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा की ओर मोड़ना चाहते हैं. कमलनाथ की जिद के कारण राष्ट्रीय महत्व का यह गलियारा सिवनी ज़िले तक बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की पेशी के लिए लटक गया है. इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने में भी कमलनाथ की ही भूमिका है.

वर्ष 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वीकृत स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को राष्ट्रीय हित की योजना मानते हुए वर्तमान प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने व्यक्तिगत रुचि लेकर पूरा करने के निर्देश दिए थे. इस परियोजना में उत्तर भारत के श्रीनगर को दक्षिण भारत के अंतिम छोर कन्या कुमारी तक फोर लाईन सड़क से जोड़ा जाना है, जिसे नॉर्थ साउथ कॉरीडोर का नाम दिया गया था. वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद टी.आर. बालू के स्थान पर कमलनाथ सड़क परिवहन मंत्री बनाए गए. उत्तर–दक्षिण गलियारा उनके संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा से मात्र 70 किलोमीटर दूर सिवनी ज़िले से होकर नागपुर जा रहा था. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मित्र रहे कमलनाथ को लगा कि व्यास नदी की धारा को व्यक्तिगत हितों के लिए मोड़ लेने के बाद वे इस नार्थ–साउथ कॉरीडोर की दिशा भी बदल सकते हैं. कमलनाथ स्वयं सड़क परिवहन मंत्री के पद पर जब से आसीन हुए हैं तभी से नार्थ–साउथ कॉरीडोर को छिंदवाड़ा ले जाने का षडयंत्र प्रारंभ हुआ. सबसे पहले वर्ष 2007 के अंतिम महीनों में एक काल्पनिक ख़बर में बताया गया कि कान्हा नेशनल पार्क से एक बाघ 180 किलोमीटर पैदल चलकर पेंच नेशनल पार्क पहुंच गया. इससे लगभग 15 किलोमीटर दूर फोर लाईन की सड़क को बनाया जाना है. कमलनाथ के चचेरे भाई अशोक कुमार वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का एक संगठन वन्य प्राणियों के संरक्षण के नाम से चलाते हैं. अशोक ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर निवेदन किया कि सिवनी से नागपुर के मध्य कॉरीडोर की फोन लाइन सड़क पेंच नैशनल पार्क के वन्य प्राणियों पर दुष्प्रभाव डालेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने वन्य प्राणी विशेष तौर पर बाघों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय साधिकार समिति से जांचकर रिपोर्ट सौंपने को कहा. केंद्रीय साधिकार समिति (सी.ई.सी.) की टीम ने कमलनाथ के प्रभाव वाले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉर्टी के सदस्य डॉ. राजेश गोपाल को वन्य जीव विशेषज्ञ के तौर पर शामिल किया. उम्मीद के मुताबिक़ डॉ. राजेश गोपाल ने सिवनी ज़िले के जंगलों की ऐसी रिपोर्ट कुछ ऐसे तैयार की जैसे कि देश के सारे बाघ इसी क्षेत्र में रहते हैं. डॉ. गोपाल ने पेंच और कान्हा नेशनल पार्क के बीच की दूरी 200 किलोमीटर बताते हुए कॉरीडोर के मार्ग को ही बाघों का प्राकृतिक रास्ता बता दिया. जबकि वास्तविकता यह है कि पेंच और कान्हा किसी भी तरह से जंगल से जुड़े नहीं है, दोनों के बीच किसी भी मार्ग से 200 किलोमीटर की दूरी पार कर जुड़ पाना संभव नहीं है.

डॉ. गोपाल की रिपोर्ट काल्पनिक होने के बावजूद पर्यावरण एवं वन्य प्राणियों के लिए सहानुभूति का कारण बन गई और महानगरों में बंटे हुए पर्यावरणविदों और मीडिया ने सिवनी से गुज़रने वाले नार्थ साउथ कॉरीडोर की फोर लाईन सड़क को जंगली जानवरों के लिए नुकसानदेह बता दिया. स्वयं कमलनाथ के भाई और वन्य प्राणियों के कथित संरक्षक अशोक कुमार को छिंदवाड़ा के जंगलों की वास्तविकता पता नहीं है. पेंच नेशनल पार्क छिंदवाड़ा के घने जंगलों से जुड़ा हुआ है. छिंदवाड़ा के ये घने जंगल प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र पंचमढ़ी तक सतपुड़ा की पर्वत माला की जैव–विविधताओं के साथ जुड़े हुए हैं. इन क्षेत्रों में वन विभाग और ग्रामीणों ने अक्सर बाघ के पद चिन्ह भी देखे हैं.

पिछले पांच वर्षों के दौरान नेशनल पार्कों के अंदर मारे जा रहे बाघों की चिंता डॉ. राजेश गोपाल और अशोक कुमार को नहीं है. वह मीडिया को गुमराह करते हुए फोर लाइन सड़क को नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर ले जाने के पक्ष में हैं. ऐसा कर उन्होंने इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ जैव–विविधता, लाखों पेड़ों और देश में लुप्त होते हुए बाघों के अस्तित्व को ख़तरे में डाल दिया है.

केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की वजह से भविष्य में फोर लाइन का छिंदवाड़ा होते हुए नागपुर जाना, देश के लोगों को 70 किलोमीटर का अतिरिक्त मार्ग तय करने के लिए बाध्य करेगा. 70 किलोमीटर यात्रा के दौरान 900 टन कार्बन का उत्सर्जन प्रतिवर्ष होगा, जिसकी परवाह कमलनाथ या उनके सहयोगियों को नहीं है. यदि छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच होता हुआ फोर लाइन गुज़रेगा तो इस क्षेत्र के 81581 वृक्षों की बलि देनी होगी. छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच जलेबी आकार का 22 किलोमीटर लंबा घाट पेंच नेशनल पार्क के क़रीब है. यदि फोर लाइन सड़क बना भी दी जाए तो इस घाटी से बड़े वाहन मुश्किल से निकलेंगे. ऊपर से 22 किलोमीटर लंबी इस घाटी के घाट को कम करने के लिए उसका विस्तार 30 से 32 किलोमीटर तक करना पड़ेगा. इससे होने वाला पर्यावरण का नुकसान कम नहीं आंका जा सकता.

पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना विशेषज्ञों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर टी.आर. बालू के परिवहन मंत्री काल तक सुगमता से चल रही थी. कमलनाथ के सड़क परिवहन मंत्री बनने के बाद छिंदवाड़ा क्षेत्र में ही यह परियोजना क्यों न्यायालय में उलझ गई. इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है. कमलनाथ ने एक ही मंजिल के लिए तीन रास्तों के विकल्प दिए हैं. उद्योगपति कमलनाथ छिंदवाड़ा से नागपुर के बीच के क्षेत्र में आदिवासियों को मिली बेहिसाब छूट का लाभ उठाकर अपने मित्रों के हित में विशेष आर्थिक क्षेत्र छिंदवाड़ा में बनवाकर अपनी राजनीतिक साख को मजबूत करना चाहते हैं. अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कमलनाथ राष्ट्रीय हितों को साख पर रखने में भी परहेज नहीं कर रहे.

एक शक्तिशाली नेता के मंसूबों को पूरा करने के लिए सिवनी–लखनादोन मार्ग में सिवनी के आगे 12 किलोमीटर फोर लाइन सड़क बनाने में ख़र्च हुए 1200 करोड़ रुपयों के साथ–साथ अभी तक काटे गए लाखों वृक्षों की भरपाई कौन करेगा. इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है. अंग्रेजों के शासनकाल में सिवनी के आदिवासियों ने सत्याग्रह कर वृक्षों की कटाई रोकने के लिए अपनी जान तक दे दी थी. अगर वर्तमान में सिवनी से नागपुर जाने वाली फोर लाईन सड़क बन जाती है तो यह आदिवासियों के विकास को अंतर्राष्ट्रीय आयाम देने में महत्वपूर्ण भमिका निभा सकती है. लेकिन कमलनाथ की जिद और कूटनीतिक चालें इस राष्ट्रीय परियोजना को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए तत्पर है. सिवनी में अब तक कमलनाथ के 100 से ज़्यादा पुतले जलाए जा चुके हैं. इतना ही नहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी भी सिवनी–नागपुर फोर लाइन सड़क के पक्ष में है. सिवनी के दस लाख लोग कमलनाथ की राजनीतिक चाल के ख़िलाफ़ पर्यावरण, वन और आदिवासी विकास के मुद्दे पर एकजुट होकर खड़े हुए हैं. दूसरी ओर कमलनाथ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रजातंत्र के 10 लाख पहरियों को अपनी ताक़त का एहसास दिला रहे हैं. निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाथों में हैं. देखतें हैं फ़ैसला किसके पक्ष में होगा.

feedback@chauthiduniya.com

क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पूरे देश को सात मार्ग से जोड़ देने की योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से प्रारंभ की गई थी. इस योजना के तहत देश के बाहरी हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए पूरे राष्ट्र की यात्रा का एक सुगम मार्ग तैयार किया जाना था. यह मार्ग एक्सप्रेस वे के नाम से जाना जाएगा. इस मार्ग से चैन्नई, मुम्बई, दिल्ली और कोलकाता को 5800 किलोमीटर की लंबी सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा, यह मार्ग सिक्स लेन का होगा. इस मार्ग के बन जाने के कारण भारत के सभी प्रांतों को आसानी से एक दूसरे के साथ संलग्न कर सांस्कृतिक एवं आर्थिक तंत्र को मजबूती दी जानी है. इस योजना के पहले चरण में ही देश के सभी प्रमुख शहरों में इसका कार्य प्रारंभ किया गया है. 12 करोड़ यू.एस. डॉलर से अधिक की इस परियोजना को लागू करने के लिए पूरे देश में एक साथ काम प्रारंभ किया गया है. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़क मार्ग के अतिरिक्त रेल मार्ग से भी समूचे देश को मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई से एक साथ जोड़ने की योजना है. इस योजना के तहत परिवहन और 60 प्रतिशत यात्रियों की सुविधा के लिए एक राष्ट्रीय रेल मार्ग का निर्माण हो सकेगा. रेल के इस नए हाईवे सिस्टम के कारण यात्रियों को कई सहूलियतें भी मिलेंगी. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अपने निर्धारित कार्यक्रम से काफी पीछे चल रही है. अधिकारी जानकारी के अनुसार कहीं कहीं इस योजना को 96 प्रतिशत तक पूरा कर लिया गया है. इस योजना के साथ भ्रष्टाचार की कई कहानियां भी साथ में जुड़ी हुई है. वर्ष 2003 में बिहार के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्धारा प्रधानमंत्री को भेजे गए शिकायती पत्र में भ्रष्टाचार की कई शिकायतों का जिक्र था. इन शिकायतों के भेजे जाने के कुछ समय बाद ही उपरोक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हत्या कर दी गई थी. स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इन दिनों छिन्दवाड़ा में कमलनाथ की महत्वाकांक्षा की बली चढ़ रही है. परियोजना के साथ राजनेताओं और ठेकेदारों के निहित स्वार्थों में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के पूरा होते ही विवादास्पद बना दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्धारा अनुमोदित इस योजना को कांग्रेस शासनकाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केवल इसीलिए अनुमति दी की इससे भारत समग्र रूप में विकास कर पाने में सक्षम है. यातायात के बेहतर साधनों के अतिरिक्त रेल एवं सड़क मार्ग से परिवहन के एक नए एक्सप्रेस वे से देश में आर्थिक क्रांति और सामाजिक एकता कायम की जा सकती है. बशर्ते यहां महत्वाकांक्षी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना कमलनाथ जैसे राजनेताओं के निहित स्वार्थों से मुक्त हो सके.

बलरामपुर सरगुजा इलाके में एक पहाड़ी कोरबा दंपति की झोपड़ी में जलकर मृत्यु हो गई थी. रात्रि ठण्ड से बचने के लिए यह दंपति अलाव जलाकर सो रहा था.

सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य था कि आंगनवाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को पका और ताज़ा भोजन मिल सकेगा. साथ ही स्थानीय समूह होने के कारण समय पर खाना दिया जा सकेगा.

सार –संक्षेप

इंदौर में एक और बड़ा भूमि घोटाला

अबदुल मजीद खान

मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अब्दुल मजीद ख़ान ने राज्य की भाजपा सरकार को घपलों, घोटालों की जनक और संरक्षक बताते हुए कहते हैं कि इंदौर में स्वदेशी मिल के ज़मीन घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिकायत सुनने को तैयार नहीं हैं, लगता है कि सरकार भूमि घोटालों में लिप्त है. अब्दुल मजीद ख़ान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इंदौर में बंद पड़ी स्वदेशी मिल की ज़मीन को नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन ने सोफिया रियल इस्टेट इंडिया बुल्स को बेचा है. यह सौदा ही बुनियादी रूप से गलत है, क्योंकि नेशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इस ज़मीन को बेचने का हक़ ही नहीं है. वास्तव में स्वदेशी मिल की ज़मीन का स्वामित्व नगर निगम इंदौर के पास है और उसने स्वदेशी मिल को लीज पर ज़मीन दी थी. बाद में जब स्वदेशी मिल आर्थिक रूप से भारी घाटे की स्थिति में आ गई, तब नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन ने इस मिल का अधिगृहण किया था. इस तरह नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन केवल लीज होल्डर है और क़ानून के अनुसार लीज होल्डर को उसके क़ब्ज़े की भूमि का स्वामित्व नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्वदेशी मिल की ज़मीन बेच दी गई और नगर निगम इंदौर या राज्य सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं लगाई. मजीद ख़ान का कहना है कि सभी तथ्यों को जानते हुए भी राज्य सरकार ने मंत्री मंडल में इस ज़मीन के सौदे की इजाज़त दे दी और इस तरह इस भूमि का भूमि उपयोग भी बदल दिया गया. श्री मजीद ख़ान ने कहा कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर प्रवास के दौरान जब अखबार जगत मैडम नामक संस्था के बैनर तले कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने मुख्यमंत्री से स्वदेशी मिल की ज़मीन के सौदे के बारे में शिकायत करने के लिए उनसे संपर्क साधा तो मुख्यमंत्री ने उनसे भेंट करने से साफ़ इंकार कर दिया. मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से लगता है कि उन्हें इस भूमि घोटाले की पूरी तरह जानकारी है और वे अब मुंह चुराते फिर रहे हैं. कांग्रेस सचिव का कहना है कि इंदौर के कुछ जानकार नेताओं ने उन्हें बताया है कि स्वदेशी मिल की ज़मीन के संदिग्ध सौदे में उद्योगमंत्री कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका भी संदेह के घेरे में है. इससे पहले विजयवर्गीय इंदौर में सुगनी देवी कॉलेज के समीप की भूमि के सौदे में हुए घपले, घोटाले को लेकर काफी बदनाम हो चुके हैं. मजीद ख़ान ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में जांच कराने और ज़मीन बचाने के लिए गंभीर प्रयास करने की अपील की है.

आस्ट्रेलियन बत्तखों ने खींचा पर्यटकों का ध्यान

प्रवासी पक्षी आस्ट्रेलियन बत्तख ने हाल में भोपाल की बड़ी झील में आठ बच्चों को जन्म दिया है. आस्ट्रेलियन बत्तख गर्मी के मौसम में भोपाल आती हैं और वर्षा के बाद यहां से चली जाती हैं. पक्षी प्रेमियों को यह जानकर बेहद खुशी हुई कि मेहमान विदेशी बत्तख ने भोपाल में आठ बच्चों को जन्म दिया है. जानकारों का कहना है कि ऐसा कई वर्षों बाद हुआ है.तपती गर्मी के इस मौसम में बड़ी झील (भोपाल ताल) के वोट क्लब के पास यह मादा बत्तख अपने नवजात शिशुओं को तैरना सिखाते हुए पर्यटकों को दिन भर दिखाई देती है. वोट क्लब के पास ही भोपाल का वन्यप्राणी उद्यान तथा मानव संग्रहालय है, इसलिए यहां रोज हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं. अब भोपाल झील में आस्ट्रेलियन बत्तख और उसके बच्चों की अठखेलियां भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई हैं. भोपाल ताल पर तैनात नगर निगम के कर्मचारी और वन्यप्राणी उद्यान के कर्मचारी इस बत्तख और उसके बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग हैं.

भ्रष्टाचार का विरोध करने वालों को धमकाने का सिलसिला जारी

मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले अब इतने बढ़ चुके हैं कि अपने भ्रष्टाचार के खबरों को दबाने के लिए वे खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. भाजपा शासनकाल में इंदौर के एक स्थानीय अखबार के विरूद्ध भाजपा के एक मंत्री और विधायक द्वारा चलाया जा रहा कथित उत्पीड़न का कार्यक्रम इन दिनों चर्चा में है. नेताओं और अधिकारियों की भ्रष्ट आचरण की खबरों से मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार की साख दांव पर लगी हुई है. मध्यप्रदेश के आदिवासी जिले मंडला में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा स्थानीय पत्रकारों को टेलीफोन करके गालियां देने और जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है. जिले के पत्रकार असफाक खान, मुकेश श्रीवास और संदीप चतुर्वेदी ने 19 अप्रैल को जिले के पुलिस अधीक्षक को सौंपी अपनी शिकायत में लिखा है कि जब वे जिले के कान्हा क्षेत्र में एक रिसोर्ट निर्माण के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करके लौटे थे तो उन्हें मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला जगदीश चंद्र जटिया द्वारा स्वयं के मोबाईल से न सिर्फ अभद्र भाषा में चेतावनी दी गई, अपितु जान से मारने की धमकी भी दी गई. इन पत्रकारों ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिनांक 2 अप्रैल को एक रिसोर्ट पर बाल मजदूरों को काम करते हुए देख उन्होंने रिसोर्ट के मालिक के बारे में कोटवार से जानकारी चाही. मालूम पड़ा कि यह रिसोर्ट मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला जगदीश चंद्र जटिया के परिजन का है. इसी दिन जब इन्होंने खबर की पुष्टि के लिए जटिया को फोन किया तो उन्होंने इन पत्रकारों के साथ अभद्रता की. पुलिस अधीक्षक को लिखी शिकायत में पत्रकारों ने कहा है कि जटिया ने उन्हें कटवाकर फेंक देने और ऐसे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी है जिससे वे जीवन भर बाहर न निकल सकें। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के आदिवासी जिलों को विकास कार्यो के लिए भेजे जाने वाली राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रही है, इन जिलों में आदिवासी विकास के नाम पर काम करने वाले अधिकारी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे पाए गए. श्री जटिया के संदर्भ में यह भी बताया जाता है कि जिला पंचायत द्वारा क्रियान्वित की गई कई योजनाए सिर्फ कागजों में ही प्रशंसा की पात्र बनी हुई है. उपरोक्त दर्ज प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है. मंडला जिले में मुख्यमंत्री की कई घोषणाओं के बावजूद अभी तक प्रशासन अधिकारियों की गैर जिम्मेदारना कार्यवाहियों से मुक्त नहीं हो सका है. उल्लेखनीय है कि इसी जिले में इन्हीं अधिकारियों के भरोसे राज्य सरकार आदिवासी महाकुंभ आयोजित करने की योजना बना रही है. इस कार्यक्रम में राज्य सरकार 20 लाख आदिवासियों को एकत्र करने का दांवा करती है. दूसरी ओर इंदौर क्षेत्र में राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने एक स्थानीय अखबार के विरूद्ध खुलेआम सड़कों पर गुंडागर्दी प्रारंभ कर दी है. इस अखबार द्वारा पिछले एक माह से अधिक अवधि से जिले में इन नेताओं के भ्रष्टाचार की कलई लगातार खोली जा रही है. भाजपा के इन दो महत्वपूर्ण नेताओं के समर्थकों ने अखबार की प्रतियों को वितरित होने के पहले हॉकर से छीनकर जला दिया साथ ही अखबार से संबंधित व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी भी दी है. जिला प्रशासन गुंडागर्दी की इस वारदात के विरूद्ध पूरी तरह मौन है. प्रशासन और राजनेताओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध हथियार लेकर आम व्यक्ति को डराने धमकाने का सिलसिला मध्यप्रदेश में पहली बार इसी सरकार के दौरान जन्म ले रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सिर्फ़ किताबी योजनाएं और खोखले वायदे

स्वर्णिम म.प्र.का रोड मैप

विनय दीक्षित

स्वर्णिम मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र तैयार करने की प्रसव वेदना से प्रदेश की भाजपा सरकार पिछले कई महीनों से जिस प्रकार से चीख– पुकार मचा रही थी, उसे लगता था कि सरकार परिवर्तन का भीमसेन जनने वाली है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में हुए विचार मंथन के बाद जनता को पता चला कि सरकार का बौद्धिक गर्भपात हो गया. मुख्यमंत्री ने सदन में ज़ोर–शोर से घोषणाओं और नए कार्यक्रमों के नाम पर जो कुछ कहा है, उसमें नया कुछ भी नहीं है.

सन 2008 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी सफलता और राजनीतिक चतुराई पर आत्ममुग्ध हैं. वह अपनी छवि निखारने के लिए नए–नए आकर्षक नारे गढ़ते रहते हैं. पिछले दिनों उन्हें दिव्यज्ञान हुआ कि झाड़ झंकार, मिट्टी–पत्थर, नदी–पहाड़ वाले मध्य प्रदेश को स्वर्णिम भूमि बनाना चाहिए. इसके बाद वे स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का राग अलापते हुए पूरे प्रदेश में तांडव करते घूमने लगे. मीडिया को भी उन्होंने मोहित कर लिया. करोड़ों रुपयों के विज्ञापन और प्रायोजित प्रचार से सरकार ने मुख्यमंत्री की छवि विकास पुरुष के रूप में बनाने का अभियान चलाया. लेकिन बहुत दिनों बाद किसी समझदार ने मुख्यमंत्री को समझाया कि भैया, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा तो बुलंद हो गया, लेकिन इसे बनाओगे कैसे? तब उन्हें भी समझ आया कि अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नक्शा तैयार कर लेना चाहिए. इसीलिए मुख्यमंत्री ने मई माह की तपती गर्मी में चार दिनों के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र विचार–मंथन के लिए आहूत किया. चार दिन बाद अफसरों द्वारा तैयार किए गए भाषण को एक आज्ञाकारी छात्र की तरह रटकर विधानसभा में सुना दिया.

प्रदेश की आम जनता भोली और भली है, लेकिन उसकी समझदारी पर शंका नहीं की जा सकती है. इतना ज़रूर है कि कुछ चालाक नेता कुछ समय के लिए जनता को भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जनता ज़्यादा देर तक किसी के झांसे में नहीं आती है. मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता भले ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश और मई 2010 में घोषित संकल्प को लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन सड़क पर खड़ा आम आदमी हंस रहा है.

प्रदेश में दिसंबर 2003 में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी. तब भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में राज्य के बहुमुखी विकास और जनकल्याण के अनेक लुभावने वायदे किए थे, फिर 2008 में भी जनता ने भाजपा के पक्ष में ही जनादेश दिया और तब भी भाजपा ने जनता के बीच कई नए–पुराने वायदों का प्रचार किया था. दो चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के बाद भी सरकार ने राज्य में कृषि, उद्योग, बिजली, पानी, सड़क, विकास, जनकल्याण आदि विषयों पर सरकारी नीतियों की घोषणा की. हर साल बजट सत्र में सरकार राज्य के विकास और जनकल्याण के बारे में नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा करती आई, फिर 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने राज्य के पांच वर्ष की अवधि के लिए विकास योजना तैयार की. इसे केंद्र सरकार की मंजूरी भी मिल गई. इतनी सारी कोशिशों और बौद्धिक कवायदों के बाद भी आख़िर क्या कमी रह गई थी कि मुख्यमंत्री को मई 2010 में अचानक विचार आया कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए उन्हें और भी अच्छे और नए सुझावों की ज़रूरत है.

असल में मुख्यमंत्री और भाजपा की स्थिति उस अनभिज्ञ और दिशा भ्रमित राही की तरह है, जो अपने लुभावने वायदों की भूल–भुलैया में फंसा हुआ है और निकलने के लिए उसे रास्ता नहीं सूझ रहा है. इसीलिए भाजपा सरकार ने अपने शासन के छह वर्ष पूरे कर लेने के बाद अब राज्य के विकास का रोडमैप तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है. लेकिन यह प्रक्रिया हास्यास्पद और फूहड़ सी लगती है.

लोकतंत्र में विपक्ष या प्रतिपक्ष का अपना महत्व होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा सत्र को असंवैधानिक बताने की बहस चलाते हुए इस सत्र का बहिष्कार ही किया. कांग्रेस रचनात्मक विपक्ष की ज़िम्मेदार भूमिका से बचती रही और सड़क पर हल्के–फुल्के ढंग से सरकार के ख़िलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शन करती रही.

दरअसल कांग्रेस अपनी चुनावी पराजय के शोक से आज तक उबर नहीं पाई है. बिजली संकट के लिए आम कांग्रेसी आज भी अपनी पिछली सरकार को ही दोषी मानता है. इसके अलावा जब कभी किसी भी समस्या का ज़िक्र होता है और भाजपा कांग्रेस सरकार की ख़ामिया गिनाने लगती है, तो कांग्रेसी बगले झांकने लगते हैं. अपराध बोध से ग्रस्त कांग्रेस विधायक विधानसभा में स्वस्थ्य और मुखर विरोध करने में सक्षम साबित नहीं हुए है. इसलिए विधानसभा सत्र का बहिष्कार करके उन्होंने कोई नाम कमा लिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता.

अवनि वैश्य

जहां तक स्वर्णिम मध्य प्रदेश के नारे का सवाल है, तो इस गर्मी में जब राज्य में पानी के लिए जनता तरस रही है, बिजली संकट के लिए आंसू बहा रही हैं, तब मुख्यमंत्री जनता को राहत देने से बचते हुए विधानसभा में स्वर्णिम मध्य प्रदेश का नारा बुलंद कर रहे हैं. राज्य में शासन–प्रशासन में भ्रष्टाचार, अनैतिकता और संवेदनहीनता की बुराईयों से समझौता करके शिवराज सिंह राज्य की जनता को सुशासन कैसे दे सकते हैं और सुशासन के बिना यह राज्य विकास कैसे कर सकता हैं, यह समझदारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

मुझे कुछ आला अफसरों ने बताया है कि मुख्यमंत्री मंत्रालय में कभी जमकर नहीं बैठते हैं. अगर कभी बैठते भी हैं तो गंभीर विषयों पर गंभीरता से गहन अध्ययन, मनन और चिंतन नहीं करते. सभी फैसले सतही और टालू तरीके से लिए जाते हैं. इसीलिए मंत्रालय का प्रशासन के निचले स्तर से कोई सतत संवाद नहीं रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर पर इस बारे में किसी को चिंता नहीं है. विकास और जनकल्याण की योजनाएं केवल पैसा ख़र्च करने के लिए सतही तौर पर लागू की जाती हैं. इसीलिए उनके अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं.

प्रदेश का सबसे बड़ा संकट है–पहचान का संकट. मध्य प्रदेश की अपनी कोई पहचान आज तक नहीं बनी है. हिंदी शब्दकोश में पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, हरियाणवी, राजस्थानी, बिहारी, गुजराती जैसे शब्द तो हैं, लेकिन मध्य प्रदेशवासी के लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है. इसका कारण है कि मध्य प्रदेश का अपना कोई निजत्व नहीं है. इसीलिए मध्य प्रदेश के नागरिक या तो पूरी तरह से भारतीय होते हैं या फिर शहर–गांव या बुंदेलखंड, बघेलखंड, मध्य भारत जैसे अंचलों तक सिमटकर रह जाते हैं. समग्र मध्य प्रदेश का बोध न किसी नागरिक को है और न किसी नेता को है. यहां की सभी नदियां अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण दूसरे राज्यों के हितों के लिए समर्पित हैं. हमें वनों की रक्षा करनी होती है, क्योंकि देश में पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है. राज्य की 35.5 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजातियों की हैं.

भौगोलिक रूप से उद्योग और अन्य आर्थिक सेवाओं के लिए यह राज्य अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त नहीं है. ऐसे में केवल कृषि और पशुपालन ही आर्थिक विकास का मुख्य आधार है, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के कारण मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है और अपना महत्व खोता जा रहा है. सरकार के 2009–10 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक़ सन 1999–2000 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का अंशदान 28 प्रतिशत था जो 2008–09 में घटकर 20.53 प्रतिशत रह गया है. सरकार लाख दावे करे, पर कृषि क्षेत्र में विकास दर कम हो रही है. प्रमुख फ़सलों अनाज, दलहन, तिलहन, गन्ना आदि के उत्पादन में कमी आ रही है. इसी तरह पशुपालन के क्षेत्र में भी आर्थिक कारोबार में कमी आई है.

राज्य में गौवंशीय पशुओं की संख्या एक करोड़ 89 लाख और भैंसवंशीय पशुओं की संख्या 75 लाख, बकरे–बकरियों की संख्या 81 लाख है, लेकिन दूध के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं है. यह विचार करने योग्य है कि मध्य प्रदेश से छोटा गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध उद्योग आनंद डेयरी के लिए विश्व विख्यात है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे राज्यों से दूध मंगाते हैं या कृत्रिम दूध तैयार करते हैं. सरकार ने दुग्ध उद्योग के विकास और पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए कोई कारगर योजना तैयार नहीं की.

कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से जर्जर हो रहा है, इसलिए रोज़गार अवसर भी कम हो रहे हैं. यही कारण है कि सरकार को गांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना और अन्य कई केंद्र और राज्य प्रायोजित ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रमों पर हर साल अरबों रुपया ख़र्च करना पड़ता है. इतना ही नहीं, गांव में अनाज की कमी हैं, इसीलिए तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 15 हज़ार से ज़्यादा सस्ते राशन की दुकानें खोल रखी हैं. प्रदेश की ग्रामीण,आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था के अस्त–व्यस्त और बर्बाद हो जाने के कारण ही शहरों की ओर ग्रामीण जनसंख्या का पलायन तेज़ी से हुआ है और इस कारण शहरों में गंदी बस्तियों का जाल फैल रहा है. रोज़गार के अवसर भी सिकुड़ते जा रहे हैं.

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का सपना दिखा रही सरकार को अपने 2008 के चुनावी वायदे को याद कर लेना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि प्रतिवर्ष एक लाख बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाया जाएगा, लेकिन राज्य में रोज़गार अवसर कम हो रहे हैं और बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ रही है. बेरोज़गारी बढ़ने का मुख्य कारण राज्य में विकास और आर्थिक गतिविधियों में कमी आना है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यदि सचमुच प्रदेश के विकास में रुचि है, तो वह ग़ैर ज़िम्मेदार विरोधी दल के नेता की तरह बातें बखानने की आदत छोड़ दें. जनता के बीच अपनी छवि बनाने के लिए शासन–प्रशासन की आलोचना करके मुख्यमंत्री प्रशासन का मनोबल कमजोर करते है. कई बार तो मुख्यमंत्री स्वयं को व्यवस्था के कीचड़ में खिले कमल के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए अपनी सरकार और अपने अफसरों की आलोचना भी करते हैं, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि उन्होंने इस व्यवस्था से न केवल समझौता कर रखा है, बल्कि वे स्वयं इस व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं.

प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरत है एक कारगर और व्यवहारिक रोडमैप की. यह रोडमैप मंत्रालय के अफसरों या भाजपा के कुछ किताबी नेताओं के ज़रिए तैयार नहीं किया जा सकता है. मुख्यमंत्री को उदारतापूर्वक राज्य के सभी राजनैतिक दलों और राज्य की जानकारी रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ मन लगाकर बैठना होगा और राज्य के प्रत्येक विषय पर गंभीरता से चर्चा कर राज्य की बेहतरी के लिए कार्ययोजना बनानी होगी. मध्य प्रदेश में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उनका दोहन अभी तक नहीं हुआ है.

स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है तो ईमानदारी से कड़ी मेहनत करनी होगी और निजी स्वार्थ तथा विकास में बाधक शक्तियों से निर्णायक संघर्ष करना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए कि विकास की यह लंबी और कठोर यात्रा सिर्फ़ किताबी योजनाओं और खोखली घोषणाओं के दम पर नहीं की जा सकती है.

feedback@chauthiduniya.com

पोषण आहार कार्यक्रम माफ़ियाओं के क़ब्ज़े में

संध्या पाण्डे

बच्चों, गर्भवती तथा नवप्रसूता माताओं में कुपोषण की गंभीर समस्या भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति सबसे भयावह और मारक बनी हुई है. सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भी वर्तमान में राज्य में नवजात शिशुओं से लेकर पांच वर्ष तक की आयु के 60 प्रतिशत बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रस्त होने के कारण कमज़ोर और बीमार हैं. इनमें से कई बच्चों की असमय मौत हो जाती है. इसी प्रकार 50 प्रतिशत गर्भवती और प्रसूता माताएं भी अल्परक्तता तथा आयरन कैल्शियम की कमी से पीड़ित हैं.

भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने कुपोषण निवारण के लिए कई कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन राज्य में पोषण आहार सप्लाई करने और उसका वितरण करने तक की पूरी प्रक्रिया माफ़ियाओं के क़ब्ज़े में होने के कारण वास्तविक हितग्राहियों को पोषण आहार कार्यक्रम का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है. सरकार ने इस योजना में अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए बड़े–छोटे माफ़िया तंत्र को प्रोत्साहित किया है, लेकिन अब यह माफ़िया तंत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होकर अपना हित साधन में लगा हुआ है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इन माफ़ियाओं की उपस्थिति और करतूतों की भली प्रकार जानकारी है, इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को शहरी क्षेत्रों में सक्रिय माफ़ियाओं से मुक्त रखने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे कि भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में एक समूह या प्रतिष्ठान को 15 से 20 आंगनवाड़ियों में ही पोषण आहार आपूर्ति के लिए नियुक्त किया जाए. बाक़ायदा सरकारी फ़ाइल चली और मुख्यमंत्री के इन निर्देशों पर महिला एवं बाल कल्याण विभाग की मंत्री और प्रमुख सचिव ने भी स्वीकृति की मोहर लगाई, लेकिन फाइलों में दबा यह आदेश शहरों तक नहीं पहुंचा हैं और इसलिए बड़े शहरों में सक्रिय पोषण आहार आपूर्ति करने वाले माफ़िया अभी भी खुलकर अपना खेल खेल रहे हैं और कुपोषित बच्चों तथा ग़रीब माताओं के हिस्से को डकार रहे हैं. पूरे प्रदेश में 69238 आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरण की व्यवस्था है, इनमें लगभग 50 लाख बच्चों और 10 लाख गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है. इन्हें 300 से 600 कैलोरी तक का प्रोटीन पोषण आहार के रूप में दाल–दलिया या अन्य खाद्य पदार्थ के रूप में दिया जाता है, लेकिन इस कार्यक्रम में कई ख़ामियां, गड़बड़िया और घपले–घोटले होते रहे हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रदेश भर की आंगनवाड़ियों में बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं को ताज़ा पका खाना देने के उद्देश्य से साझा चूल्हा योजना बनाई गई. मुख्यमंत्री ने योजना 15 जुलाई 2009 से शुरू करने के निर्देश दिए थे, पर योजना 1 नवम्बर से अस्तित्व में आ पाई इसके देर से शुरू होने का कारण भी दलिया माफ़िया और विभाग के कुछ अधिकारियों को माना जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक़ महिला बाल विकास के निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी इस योजना को शुरू करने के ख़िलाफ़ थे, इसका कारण दलिया माफिया साझा चूल्हा योजना को बंद करवाने का षड़यंत्र कर रहे थे. इस षड़यंत्र में कथित रूप से लाभान्वित विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों का भी पर्दे के पीछे से सहयोग रहा. उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कटिबद्धता के चलते अंततः विभाग को एक नवंबर से योजना शुरू करनी पड़ी.

> महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस योजना में ऐसे पेंच डाल दिए कि यह योजना अब दलालों के क़ब्ज़े में हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में यह योजना स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जानी थी.

महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने इस योजना में ऐसे पेंच डाल दिए कि यह योजना अब दलालों के क़ब्ज़े में है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में यह योजना स्थानीय स्वसहायता समूहों के माध्यम से संचालित की जानी थी. इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य था कि आंगनवाड़ियों में आने वाले बच्चों और महिलाओं को पका और ताज़ा भोजन मिल सकेगा. साथ ही स्थानीय समूह होने के कारण समय पर खाना दिया जा सकेगा. इस कारण हर गांव में रोज़गार में भी बढ़ोतरी होती और गांव की स्थानीय महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध होता.

अधिकारियों ने यह योजना एमपी एग्रो के माध्यम से संचालित करने का नियम बना डाला. जिसके चलते योजना का लगभग 60 फ़ीसदी हिस्सा एमपी एग्रो के माध्यम से दलिया माफ़ियाओं के क़ब्ज़े में हैं. शेष 40 फ़ीसदी योजना में से क़रीब 25 फ़ीसदी हिस्सा भी इन दलिया माफ़ियाओं के क़ब्ज़े में है. इस 25 फ़ीसदी में ग्रामीण क्षेत्र में मध्यान्ह भोजन योजना के साथ साझा चूल्हा योजना चलाई जा रही है. बचा हुआ 15 प्रतिशत काम स्वसहायता समूहों के नाम पर दलिया माफ़ियाओं के कथित ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है. इस प्रकार पोषण आहार का लगभग 80 फ़ीसदी काम वास्तविक रूप में एमपी एग्रो और स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है. ग्रामीण क्षेत्र में कुल काम का 25 प्रतिशत ही साझा चूल्हा के माध्यम से संचालित हो पा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

सार –संक्षेप

अभी तक नहीं खुल सकी जादुई पत्थर की गुत्थी

मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ़ वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ही संभव है ऐसा अभी तक लोगों का मानना है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पत्थर ऐसा भी है जो मौसम का अनुमान बताता है. यह जादुई पत्थर सतना ज़िले से तक़रीबन 37 किलोमीटर दूर नागौद क्षेत्र के जसो गांव में है. यह पानी बरसने की पूर्व सूचना दे देता है. हालांकि जसों के इस जादुई पत्थर की विलक्षण शांति का रहस्योदघाटन नही किया है. खंडहर हो चुकी गढ़ी के मुख्यद्वार पर गढ़ा यह पत्थर देखने में तो दरवाज़े की शोभा के लिए लगाया गया है पर असली उद्देश्य कुछ और ही है. दो–दो के जोड़े में दरवाज़े के दोनो ओर लगे ये पत्थर बारिश के दिनों में बादलों के आकाश में छाए रहने की पूर्व सूचना देते हैं. यह सूचना एक से दो घंटे पूर्व हो जाती है. बरसात की तीव्रता के आधार पर पत्थरों से पानी टपकने का क्रम भी तीव्र होता जाता है. जानकारों के अनुसार पत्थर उन्हें पानी बरसने के पहले ही सतर्क कर देता है जिससे वे बारिश से बचने के उपाय पहले ही कर लेते है, हालांकि जो लोग इसके नजदीक रहते हैं वे ही यह जानकारी प्राप्त कर पाते हैं. गढ़ी के पास दुकान लगाने वाले व्यापारी के अनुसार इन पत्थरों को शायद नमक के घोल में वर्षों तक रखा गया होगा. जैसे नमक पानी के आस–पास होने से पसीजने लगता है, वैसे ही यह नमकयुक्त पत्थर भी अपना असर दिखाता होगा. उसने अपना अनुभव बताया कि वह दुकान के जिस हिस्से में नमक की बोरियां रखता था, दुकान बंद करने के बाद बारिश के दिनों में फर्श में अपने–आप ही बूंदे आ जाती है. बारिश में बादलों के छांए रहने पर लोग बारिश होने का अनुमान लगाते है, पर पानी गिरेगा ही, इसका पता चल जाना अपने आप में अनूठी बात है. इस अनूठे स्थान का जीर्णोद्धार आज तक नही हो पाया और न ही इस स्थान को संरक्षित करने के सफल प्रयास किए गए. जबकि इस स्थान में पुरातत्व विभाग के साथ मौसम विज्ञानियों का होना भी अपरिहार्य है. जसों के कुछ स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह हमारे गांव की अनुपम विरासत है पर इसके आस पास उजाड़ के कारण जाने में भय लगता है, जबकि इस स्थान का संरक्षण करने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है. सैलानियों के आने से जसो क्षेत्र की आय में भी इजाफ़ा हो सकता है.

बारात की मस्ती पर क़ानूनी लगाम

मध्य प्रदेश पुलिस ने शहरों और राजमार्गो पर बाजे–गाजे से बरात का जुलूस निकालने पर क़ानूनी लगाम लगाई है. इसके अनुसार बारात का जुलूस अब सड़क के एक चौथाई हिस्से को घेर कर ही निकाला जा सकेगा, वरना बाराती हवालात की मेहमानी करेंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने शहरों और राजमार्गो पर निकलने वाले बाराती जुलूसों द्वारा सड़क घेरने और यातायात अवरूद्ध करने के मामलों को गंभीरता से लिया है. राज्य के कई नगरों में राजकीय राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों के बीच से होकर गुजरते हैं, लेकिन विवाह के मौसम में इन व्यस्त मार्गो पर कई बार बारात के जुलूस मस्ती से निकाले जाते हैं. इस कारण घंटों राजकीय और अंतर्राज्यीय यातायात अवरुद्ध हो जाता है. अब पुलिस ने बारात की मस्ती पर धारा 144 का डंडा चलाया है. भोपाल जिला प्रशासन के अनुसार अब बारात सड़क के केवल एक चौथाई हिस्से पर ही निकल सकेगी और किसी भी प्रकार से यातायात अवरुद्ध नहीं किया जाएगा. जो भी इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी. इसके साथ ही भोपाल जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन संचालकों के लिए पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था करने के अनिवार्य नियम बनाए हैं तथा सभी मैरिज गार्डन संचालकों को 30 जून तक नगर निगम में पंजीयन कराने के निर्देश दे दिए हैं. यदि मैरिज गार्डन में पार्किंग या सुरक्षा को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो मैरिज गार्डन संचालक इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराये जाएंगे.

रिलायंस के नखरे, कलेक्टर भड़के

प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए पूंजीपतियों को राज्य में पूंजी निवेश के लिए हर तरह से आकर्षित कर रही हैं, लेकिन कई नकचढ़े पूंजी निवेशक सरकार से भूमि सुविधाएं और रियायतें लेने के बाद भी अपने वायदे के अनुसार काम शुरू नहीं करते हैं. साथ ही भोपाल आकर सरकार से छोटे अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिकायत करके धमकी देते हैं कि वे राज्य में पूंजी निवेश नहीं करेंगे. ऐसा ही कुछ सिंगरौली में रिलायंस ग्रुप द्वारा स्थापित किए जाने वाले पॉवर प्रोजेक्ट के मामले में हुआ. रिलायंस के अफसरों ने राज्य के मुख्य सचिव को शिकायतें करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर सिंगरौली उन्हें भूमि आवंटन में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इसलिए पॉवर प्रोजेक्ट लगाने में विलंब हो रहा है और यदि जिला प्रशासन ने आगे भी असहयोग किया तो वे अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे. रिलायंस की धमकी से घबराकर मुख्य सचिव अवनि वैश्य ने जिला कलेक्टर सिंगरौली और प्रशासन के उच्चाधिकारियों के साथ रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई. इस बैठक में रिलायंस कंपनी के प्रतिनिधियों ने शिकायतों का अंबार लगाकर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहा. मुख्य सचिव भी जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, तब उन्होंने सिंगरौली के ज़िला कलेक्टर पी नरहरी से जवाब–तलब किया. मुख्य सचिव ने रिलायंस कंपनी से भी पूछा था कि प्रोजेक्ट लगाने के काम में देरी क्यों हो रही है, तब कंपनी के अफसरों ने भूमि अधिग्रहण नहीं होने की बात कहकर ज़िला प्रशासन को प्रोजेक्ट में देरी होने के लिए ज़िम्मेदार बताया, लेकिन बैठक में मौजूद ज़िला कलेक्टर सिंगरौली पी नरहरी इस जवाब से भड़क उठे और उन्होंने रिलायंस कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोल दिया. कलेक्टर पूरी तैयारी से बैठक में आए थे. उन्होंने मुख्य सचिव के प्रोजेक्ट के लिए अब तक विभिन्न सेक्टरों में दी गई ज़मीन के बारे में बताया कि अब तक प्रोजेक्ट के लिए 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है और इसमें से 40 प्रतिशत से अधिक भूमि कंपनी को दी जा चुकी है. इसके बाद भी कंपनी ने कोई काम शुरू नहीं किया है. कलेक्टर ने कंपनी के अधिकारियों को उनकी ख़ामियां गिनाते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया. कलेक्टर ने बताया कि सिंगरौली में दूसरी कंपनियां पॉवर प्रोजेक्ट के लिए दो से तीन हज़ार मज़दूर लगाकर तेज़ी से काम कर रही हैं, लेकिन शासन में रिलायंस के प्रोजेक्ट में केवल 500 से 800 मज़दूर ही काम कर रहे हैं. इसी कारण प्रोजेक्ट का काम पिछड़ रहा है. कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन सरकारी नियमों के अनुसार कंपनी को पूरा सहयोग दे रहा है, लेकिन कंपनी ही काम धीमी गति से कर रही है. कलेक्टर के तीखे तेवर देखकर रिलायंस कंपनी के अफसर सकपका गए और उन्होंने अपनी शिकायतों और आपत्तयों को भूलकर मुख्य सचिव के सामने वायदा किया कि प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य हेतु अब ज़्यादा संख्या में मज़दूर काम पर लगाए जाएंगे और निर्माण कार्य में तेज़ी लाई जाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेस और भाजपा का दलित प्रेम

वोट बैंक की राजनीति के कारण आज दलित वर्ग का महत्व इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने हिंदी भाषी राज्यों के दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता पाई है. कई क्षेत्र में बसपा के झंडे तले दलितों के गोलबंद होने से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलितों से नाराज हैं, लेकिन मजबूरी में दलित प्रेम का दिखावा कर रही हैं.

शिवराज सिंह चौहान

सरदार बूटा सिंह

सुरेश पचौरी

हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह ग्राम जैत में एक दलित महिला को पिछड़ी जाति के कुछ दबंगों ने मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया. इस घटना को लेकर गांव के दलित समाज में तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन किसी कांग्रेस कार्यकर्ता ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश पचौरी को फोन पर इस घटना के बारे में बताया और सलाह दी कि शिवराज सिंह को अपने ही गांव में नीचा दिखाने का अच्छा मौका है. जल्दी जैत आ जाओ. फिर क्या था, फुरसत में बैठे सुरेश पचौरी को काम मिल गया और वह दल–बल सहित भोपाल से जैत पहुंच गए. उनके साथ पुलिस के सुरक्षा जवान हमेशा तैनात रहते हैं. जैत पहुंच कर सुरेश पचौरी ने वैजयंती बाई नामक उस महिला के घर धावा बोल दिया और उसे मंदिर ले गए. पचौरी ने अपने दल–बल सहित वैजयंती बाई को मंदिर में प्रवेश दिलाया और भगवान की पूजा की. इसके बाद भोपाल लौटकर पचौरी ने अपनी दलित क्रांति का जमकर शोर मचाया, जो भी हो, लेकिन जैत के दलितों में पचौरी और कांग्रेस की साख जम गई. इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष सरदार बूटासिंह भी जैत गए और उन्होंने वहां दलितों के साथ मंदिर में भगवान का पूजन किया. इसके साथ ही बूटासिंह ने दलित महिला वैजयंती बाई से भी भेंट की और उसे भरोसा दिलाया कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है और दलितों को मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं सकता है. बाद में आयोग के अध्यक्ष के रूप में बूटासिंह ने सीहोर जिला कलेक्टर को नोटिस भेजकर मामले में जवाब–तलब भी कर लिया. जैत में दलितों के बीच साख बना रही कांग्रेस की कलाबाजी के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कुछ दिन बाद अपने गांव पहुंच गए. उन्होंने पवित्र नर्मदा नदी में स्नान किया और फिर मंदिर में दलितों के साथ भजन–पूजन किया. मंदिर परिसर में शिवराज ने रामचरित मानस के सुंदरकांड का सामूहिक पाठ भी किया. इस अवसर पर उनके साथ गांव के कुछ दलित भी विशेष रूप से मौजूद रहे. बाद में प्रसाद वितरण हुआ और मुख्यमंत्री ने दलित भाईयों के साथ प्रसाद का भोग लगाया. फिर बतौर मुख्यमंत्री भाषण देते हुए शिवराज सिंह ने भरोसा दिलाया कि दलितों के साथ किसी प्रकार से अन्याय या भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा.

यह तो एक गांव का किस्सा है, जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों ने दलित प्रेम की नौटंकी की, लेकिन राज्य के बुन्देलखंड और चंबल क्षेत्र में अभी भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं, जहां जनता द्वारा चुने गए पंच–सरपंचों को उनके पदों पर गांव के दबंग केवल इसलिए काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि वे दलित जाति के हैं. छतरपुर जिले में तो दलितों को सार्वजनिक कुओं और नलकूपों से पानी भी नहीं भरने दिया जाता है. हाल ही जिले के पाए गांव में कुछ सवर्ण दबंगों ने गांव के तीन सार्वजनिक कुओं में मिट्टी का तेल डाल दिया, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पहाड़ी कोरबाः जन सुविधाओं से बेदख़ल

शिवा कुमार

हज़ारों पहाड़ी कोरबा आदिवासी इन दिनों अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं. करोड़ो रुपये की विकास योजना के बावजूद राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाली इस जनजाति के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. सरकारी स्तर पर इनके संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास ईमानदारी से नहीं किया जा रहा. बलरामपुर सरगुजा इलाक़े में एक पहाड़ी कोरबा दंपत्ति की झोपड़ी में जलकर मृत्यु हो गई थी. रात्रि ठण्ड से बचने के लिए यह दंपत्ति अलाव जलाकर सो रहा था. घासफूस की झोपड़ी में पहाड़ी कोरबा द्वारा रात में ठंड से बचने का यह आदिम तरीक़ा है. सरकारी योजनाओं की उपस्थिति के बावजूद और करोड़ो रुपये ख़र्च करने के बाद भी इस जनजाति के लोगों को अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है. पिछले साल इनके लिए सरकारी ने खाद्य, बीज, मछली पालन के लिए करोड़ों की स्वीकृति दी थी, परंतु स्थानीय व्यापारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से राहत की कोई खेप इन तक नहीं पहुंची.

> देश के प्रथम राष्ट्रपति जब पहली बार सरगुजा भ्रमण के लिए आए थे तो उन्होंनें पहाड़ी कोरबा से पूछा था तुमने रोटी खाली तो उसने रोटी के नाम से अनभिज्ञता ज़ाहिर की थी. राष्ट्रपति ने इस आदिवासी की दयनीय हालत देखकर इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में गोद पुत्र घोषित किया था.

इस जनजाति को विकास के लिए साइकिल बांटी गई, परंतु पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति साइकिल का क्या करेगा, यह तय नहीं हो पाया. इस जनजाति को दी जाने वाली प्रत्येक मदद सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है. सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर और कोरबा में पाई जाने वाली पहाड़ी कोरबाओं की बड़ी तादाद ने अब उत्तर के गांव की ओर रुख़ किया है. सरगुजा के नानदमाली क्षेत्र के पहाड़ी में दर्जनों पहाड़ी कोरबा रहते हैं. यहां बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ पीने के पानी का भी अभाव है. बढ़ते हुए परिवार से परेशान यदि कोई कोरबा नसबंदी शिविर की ओर रुख़ करता है, तो उसे वहां से वापस लौटा दिया जाता है पर परिवार को पालने के लिए संसाधनों की कमी का कोई इलाज नहीं किया जाता.

देश के प्रथम राष्ट्रपति जब पहली बार सरगुजा भ्रमण के लिए आए थे तो उन्होंनें पहाड़ी कोरबा से पूछा था तुमने रोटी खाली उसने रोटी के नाम से अनभिज्ञता जाहिर की थी. राष्ट्रपति ने इस आदिवासी की दयनीय हालत देखकर इन्हें दत्तक पुत्र के रूप में गोद पुत्र घोषित किया था. पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि जनजातियों का विकास उनकी स्वयं की परिधि में किया जाना चाहिए और उन पर कुछ भी अध्यारोपित नहीं किया जाना चाहिए. पहाड़ी कोरबाओं के विकास के लिए ईमानदारी से अभी तक कोई प्रयास नहीं किए गए. संभवतः यही कारण है कि अपने अस्तित्व के लिए आज भी ये संघर्ष जारी है.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 7 जून –13 जून 2010

सतना और आसपास खनन उद्योग में बारूद की ज़रूरत होती हैं और इसके लिए विस्फोटकों का वैध और अवैध कारोबार किया जाता है.

टाइगर स्टेट का सच

वनमंत्री सरताज सिंह

"पन्ना टाइगर रिजर्व से पिछले तीन वर्षों में लगातार बाघों की संख्या घटने के कारण एक समय स्थिति यहां तक आ गई कि इस राष्ट्रीय संरक्षित वन्यप्राणी उद्यान में एक भी बाघ नहीं बचा था."

मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है. यहां बाघों के संरक्षण के लिए विश्व वन्यप्राणी कोष तथा भारत सरकार से हर साल करोड़ों रुपये राज्य के वन विभाग को मिलता है. लेकिन राज्य के आर्थिक विकास की परियोजनाओं के नाम पर राज्य सरकार जिस प्रकार से वन्यप्राणियों की उपस्थिति वाले वनक्षेत्रों में औद्योगिक और खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे रही है, उससे बाघों के निवास का प्राकृतिक माहौल नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है.

पन्ना टाईगर रिजर्व से पिछले तीन वर्षों में लगातार बाघों की संख्या घटने के कारण इस राष्ट्रीय संरक्षित वन्यप्राणी उद्यान में एक भी बाघ नहीं बचा था. इस पर पर्यावरण प्रेमियों और वन्यप्राणी विशेषज्ञों ने हल्ला मचाया, तब कहीं सरकार होश में आई और उसने विशेषज्ञों की एक समिति बनाकर मामले की जांच कराई. लेकिन जांच रिपोर्ट आने के बाद आम जनता को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बाघों की मौत और उनके संरक्षित वन उद्यान से गायब हो जाने की घटना के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. इस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने खारिज कर दिया और वनमंत्री सरताज सिंह ने सार्वजनिक तौर पर एलान किया कि बाघों की गायबी की घटना की सीबीआई से जांच कराई जाएगी. इस जांच के लिए वन विभाग ने सीबीआई को विधिवत एक पत्र भी भेज दिया है. लेकिन हाल ही में राज्य के दूसरे टाईगर रिजर्व क्षेत्र में कोयला उत्खनन, सीमेंट प्लांट की स्थापना और लाइम स्टोन उत्खनन के लिए बड़े उद्योगों के पक्ष में वन विभाग ने जिस उदारता से अपनी रजामंदी दी है, उससे बचे-खुचे बाघों के लिए खतरा पैदा हो गया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य वन्यप्राणी संरक्षण मंडल ने सतपुड़ा और पेंच टाईगर रिजर्व जोड़ने वाले कॉरीडोर में कोयला खदान में उत्खनन की अनुमति देने की सिफारिश की है.

इस रिपोर्ट में मुख्य वन संरक्षक, छिंदवाड़ा ने खदान आवंटन और कोयला उत्खनन से वनक्षेत्र या वन्यप्राणियों को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न होने का भरोसा दिलाया है. इसी प्रकार की सिफारिश सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के पास सीमेंट कारखाना लगाने और उसके लिए लाइमस्टोन उत्खनन के लिए भी वन विभाग ने अपनी सहमति दे दी है.

जानकारों का मानना है कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेशकों को उनकी शर्तों के अनुसार भूमि और सुविधा देने के मामले में राज्य सरकार उदार बनी हुई है. इसीलिए जयप्रकाश एसोसिएट्स जेपी सीमेंट को छिंदवाड़ा जिले में भूमिगत कोयला खदानों में उत्खनन की मंजूरी वन्यप्राणी संरक्षण मंडल से मिल गई है. लेकिन जिस स्थान पर उत्खनन कार्य होना है और भारी मात्रा में कोयले का भंडार तथा उसका परिवहन किया जाना है, वह स्थान पचमढ़ी बॉयोस्फीयर रिजर्व से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके लिए सतपुड़ा और पेंच टाइगर रिजर्व के बीच 2006 की वन्यप्राणी गणना में बताया गया था कि इस क्षेत्र में केवल दो तेंदुए ही पाए जाते हैं. इस संख्या को लेकर भी जानकारों को संदेह है, क्योंकि इस क्षेत्र में कहीं ज्यादा संख्या में तेंदुओं की मौजूदगी पाई गई है और इसकी पुष्टि वन विभाग के छोटे जमीनी कर्मचारी भी कर चुके हैं. उत्खनन कार्य और कोयला खदानों के संचालन के लिए वन विभाग ने जेपी एसोसिएट्स से यह शर्त जरूर लगाई है कि इस जमीन पर मौजूद लगभग तीन लाख 30 हजार पेड़ों में से एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा. लेकिन वन पर्यावरण के जानकारों के गले यह बात नहीं उतर सकी है, क्योंकि कोयला भंडार और कोयले के परिवहन के लिए भारी वाहनों के आवागमन, हजारों की संख्या में मजदूरों की अस्थाई आवासीय बस्तियां बनाने से वनक्षेत्र और वन्यप्राणी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं.

जेपी एसोसिएट्स से जुड़ा एक और मामला सीधी जिले के मझगवां-बुदगोना और हिनोता लाईम स्टोन खदान का है. यहां स्थापित होने वाले सीमेंट कारखाने का प्रदूषित जल मड़वाल नाले के जरिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में छोड़ा जाना है. इससे पानी प्रदूषित होगा और अभ्यारण्य क्षेत्र में कचरे, मिट्टी और कीचड़ का जमाव भी बढ़ेगा. इससे नदी का जल भी प्रदूषित होगा और नदी में भी दूषित ठोस पदार्थों का जमाव बढ़ेगा. कहने को तो वन विभाग ने नदी के इस क्षेत्र का अध्ययन राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना के अनुसंधान अधिकारियों से कराया है, लेकिन उनकी हैसियत वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी अस्थाई कर्मचारी से ज्यादा कभी नहीं रही. इसलिए इन अनुसंधान अधिकारियों की विशेषज्ञता पर भी संदेह होता है. राज्य के सेवानिवृत्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एपी द्विवेदी अब खुलकर कहते हैं कि वन क्षेत्र में स्थित इस कॉरीडोर में खदानों के संचालन और भूमिगत कोयला उत्खनन की अनुमति देना समझ से परे है. अच्छे, कीमती और घने वनों तथा दुर्लभ वन्यप्राणियों के प्राकृतिक निवास स्थल के आसपास ऐसी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. राज्य सरकार को ऐसे गंभीर मामलों में समग्रता से विचार करना चाहिए तभी वन्यप्राणियों की सुरक्षा हो सकेगी.

feedback@chauthiduniya.com

बारूद के ढेर पर सतना शहर

पुष्पेन्द्र मौर्या

विंध्य अंचल का सतना शहर बारूद के ढेर पर बसा है. शहर में वैध-अवैध विस्फोटकों के ज़खीरे जहां-तहां जमा हैं. सतना और आसपास के खनन उद्योग में बारूद की ज़रूरत होती है और इसके लिए विस्फोटकों का वैध रूप से कारोबार किया जाता है. इसके अलावा इस क्षेत्र में कुओं की खुदाई, सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों में भी चट्टानों को काटने के लिए विस्फोटकों की ज़रूरत होती है. विस्फोटकों के वैध कारोबार के साथ-साथ अवैध कारोबार भी जमकर हो रहा है. हाल ही में सतना पुलिस ने शहर में लगभग 80 किलो अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया है. इसके अलावा ग्रेनेड बनाने के सामान सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है. यह विस्फोटक इतनी ज्यादा मात्रा में है कि शहर का एक बड़ा हिस्सा नष्ट किया जा सकता है.

सतना में कुछ दिन पहले बस स्टैंड में बम विस्फोट की एक घटना हुई थी. तब से पुलिस शहर में विस्फोटकों का कारोबार करने वालों का पता लगाने में सक्रिय हुई थी. पुलिस ने अपनी सहायता के लिए कई मुखबिर भी जगह-जगह तैनात किए थे. सिटी पुलिस थाने के कोतवाल बीएस जग्गी को एक मुखबीर से सूचना मिली कि शहर के पुराना पावर हाउस क्षेत्र में एक व्यक्ति भारी मात्रा में विस्फोटक सामान रखे हुए है. इस सूचना के बाद पुलिस ने सुनियोजित तरीके से छापामार कार्यवाही की और मुखबीर द्वारा बताए गए स्थान से पूरण उर्फ अब्दुल्ला पिता शिवचरण उम्र 52 वर्ष को ग्रेनेड बम बनाने के सामान सहित पकड़ने में सफलता पाई. उसके पास से कुल 80 किलो विस्फोटक जब्त हुआ है.

बाद में पुलिस ने पूरण उर्फ अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया और उससे गहन पूछताछ की. पूछताछ करने पर पूरण ने बताया कि उसने यह विस्फोटक सामान रीवा से प्राप्त किया है. पुलिस ने उससे उसके रीवा के संपर्क सूत्रों के बारे में पूरी जानकारी ली और रीवा पुलिस के सहयोग से रीवा में गुड़हाई बाजार निवासी राजबली गुप्ता पिता जगदीश गुप्ता को पकड़ा, उसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामान मिला है. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा बरामद किए गए सामान में 80 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. इसमें बारूद, पोटाश, अमोनियम नाइट्रेट, मैंसील पावडर, छर्रे, सुतली और ग्रेनेड कवर जैसी सामग्री शामिल है. विस्फोटक सामग्री मिलने की सतना में यह कोई पहली घटना नहीं है. शहर में भरहुत मोड़ के पास कुछ माह पूर्व बारूद से भरी एक जीप धमाके में ध्वस्त हुई थी. उसके अलावा कोठी क्षेत्र के पास खेत में भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट भी बरामद हुआ था. सतना में विस्फोटक पदार्थों की बरामदगी के बाद पुलिस और भी अधिक सक्रिय हो गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुई नक्सली हमलों की घटनाओं के बाद अब नक्सली भागकर विंध्य प्रदेश के उमरिया, अनूपपुर, शहडोल तथा सिंगरौली इलाकों में प्रवेश कर रहे हैं और राज्य पुलिस भी मानती है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली इन क्षेत्रों को अपने लिए शेल्टरलैंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके लिए वे आसपास के क्षेत्रों से अपने लिए विस्फोटक भी प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं. इसके अलावा पन्ना और बांधवगढ़ राष्ट्रीय वन्यप्राणी अभ्यारण्यों में भी अवैध शिकार के लिए शिकारी विस्फोटकों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com